Website : www.mantrabharat.com

जुनून है सच लिखने का

E-Mail : mantrabharatmumbai@gmail.com, Mo. 7007837917

संस्करण : मुंबई
वर्ष : 11
अंक : 28
पृष्ठ : 8
मूल्य : 2.00
बुधवार, 04 फरवरी, 2026

मंत्र भारत

हिन्दी दैनिक

मुंबई, लखनऊ, प्रयागराज एवं ग्वालियर से एक साथ प्रकाशित एवं ठाणे, नवी मुम्बई, पालघर, नासिक एवं पुणे से प्रसारित

3 महाराष्ट्र में बड़ा हादसा टला, उड़ान से ठीक...

4 ममता के बंगाल में कितने लोग जिंदा जलकर ...

7 भारतीय मूल के क्रिकेटरों का दबदबा, टी20 ...

संक्षिप्त न्यूज

युमनाम खेमचंद बनेंगे मणिपुर के नए सीएम, भाजपा विधायक दल की बैठक में फैसला

नई दिल्ली। मणिपुर में आगामी 12 फरवरी को राष्ट्रपति शासन खत्म होना वाला था। इससे पहले ही एनडीए में सरकार बनाने को लेकर कवायद तेज हो गई थी। इस बीच भाजपा विधायक दल की बैठक में मंगलवार को युमनाम खेमचंद को विधायक दल का नेता चुना गया। इसी के साथ युमनाम खेमचंद के मणिपुर के नए मुख्यमंत्री बनने का रास्ता साफ हो गया है।

मणिपुर में फिर से सरकार बनाने के लिए भाजपा के विधायक सोमवार को ही दिल्ली पहुंच गए थे। वहीं, राष्ट्रपति शासन की अवधि खत्म होने से ठीक पहले भाजपा ने पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री तरुण चुघ को राज्य का केंद्रीय पर्यवेक्षक नियुक्त किया था। मणिपुर में हिंसा भड़कने के बाद पूर्व मुख्यमंत्री एन. बीरेन सिंह ने इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद से ही करीब एक साल तक मुख्यमंत्री पद खाली रहा।

कौन हैं युमनाम खेमचंद सिंह?

युमनाम खेमचंद सिंह मणिपुर की सिंगजामेई विधानसभा सीट से दो बार के विधायक हैं। वह मणिपुर विधानसभा के स्पीकर भी रहे हैं। 2022 में युमनाम खेमचंद को बीरेन सिंह सरकार में कैबिनेट मंत्री का पद दिया गया था। युमनाम सिंह मैतेई समुदाय से संबंध रखते हैं।

मणिपुर में 13 फरवरी 2025 को पहली बार छह महीने के लिए राष्ट्रपति शासन लगाया गया था, जिसे अगस्त 2025 में बढ़ाया गया।

मणिपुर के भाजपा विधायक थोकचोम राधेश्याम सिंह ने कहा, 'यह अच्छी बात है कि हमें एक निर्वाचित सरकार और एक लोकप्रिय सरकार मिलने जा रही है। इसमें बहुत देरी हो गई। इसलिए हम इस कदम के लिए केंद्र सरकार का आभार व्यक्त करते हैं। हर समस्या का समाधान होता है।

लोकसभा में भारी हंगामा

कागज उछालने पर कांग्रेस के 7 समेत 8 सांसद पूरे बजट सत्र से निलंबित

नई दिल्ली। सदन की कुर्सी पर कागज़ फेंकने के आरोप में आठ लोकसभा सांसदों को पूरे बजट सत्र के लिए निलंबित कर दिया गया है। निलंबित सांसदों में मणिकम टैगोर, गुरजीत सिंह औजला, अमरिंदर सिंह राजा वारिंग, किरण कुमार रेड्डी, एस वेंकटेशन, हिबी ईडन, डीन कुरियाकोस और प्रशांत पाडोले शामिल हैं। इनमें से सात सांसद कांग्रेस पार्टी से हैं, जबकि वेंकटेशन सीपीएम से हैं। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू द्वारा इस संबंध में एक प्रस्ताव पेश किए जाने के बाद सांसदों के खिलाफ कार्रवाई की गई।

सदन में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव को लेकर जारी चर्चा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी द्वारा पूर्व सेना प्रमुख एम एम नरवणे के एक अप्रकाशित संस्मरण का उल्लेख करने का प्रयास करने के मुद्दे पर बैठक तीन बार स्थगित होने के बाद अपराह्न तीन बजे शुरू हुई तो पीठासीन सभापति दिलीप सैकिया ने आसन की अवज्ञा

करने के लिए कांग्रेस सदस्यों अमरिंदर सिंह राजा वडिंग, गुरदीप सिंह औजला,हिबी ईडन, डीन कुरियाकोस, प्रशांत पडोले, किरण कुमार रेड्डी और मणिकम टैगोर तथा माकपा सांसद एस वेंकटेशन के नाम लिए।

संसदीय कार्य मंत्री किरेन रीजीजू ने आठों सदस्यों का नाम लेते हुए सदन में प्रस्ताव रखा कि सदन की अवमानना करने और महासचिव तथा लोकसभा अधिकारियों की मेजों के पास आकर कागज उछालकर आसन की गरिमा को ठेस पहुंचाने के लिए उक्त सभी सदस्यों को नियम 374 (2) के तहत संसद के वर्तमान सत्र की शेष अवधि के लिए निलंबित किया जाए। सदन ने ध्वनिमत से इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी जिसके बाद बैठक दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई।

विपक्षी सदस्यों ने सदन में राहुल गांधी को बोलने की अनुमति नहीं मिलने के मुद्दे पर नारेबाजी करते हुए आसन के समीप कागज उछालकर फेंके थे। राहुल गांधी ने मंगलवार को सदन में नरवणे की पुस्तक पर आधारित लेख को सत्यापित करते हुए सदन के पटल पर रखा। उन्होंने फिर से नरवणे के संस्मरण और चीन के साथ टकराव का मुद्दा उठाते हुए कहा कि यह राष्ट्रीय सुरक्षा का महत्वपूर्ण मुद्दा है जिसका चीन तथा पाकिस्तान के साथ संबंध है और यह राष्ट्रपति के अभिभाषण का प्रमुख हिस्सा है। आसन से उन्हें आगे बोलने की अनुमति नहीं दी गई।

भारत-अमेरिका व्यापार समझौते से देश के विनिर्माण क्षेत्र को मिलेगा बढ़ावा : सीतारमण

नई दिल्ली **(एजेंसी)**। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को भारतीय सामानों पर अमेरिकी शुल्क में कटौती का स्वागत किया और इस घटनाक्रम को 'मेड इन इंडिया' पहल के लिए एक बड़ा प्रोत्साहन बताया। उन्होंने सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर पोस्ट किया कि भारतीय उत्पादों को अब 18 प्रतिशत के कम जवाबी शुल्क का सामना करना पड़ेगा।

उन्होंने कहा, ''मेड इन इंडिया उत्पादों के लिए अच्छी खबर। उन्हें अब 18 प्रतिशत का कम शुल्क देना होगा। इस विकास के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति के नेतृत्व को धन्यवाद। हमारे दो बड़े लोकतंत्रों के लोगों को इससे लाभ होगा।'' यह सफलता प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच टेलीफोन पर हुई उच्च स्तरीय बातचीत के बाद मिली है। इसके बदले भारत ने अमेरिकी वस्तुओं के लिए व्यापार बाधाओं को कम करने और ऊर्जा, प्रौद्योगिकी तथा कृषि सहित विभिन्न क्षेत्रों में आयात में उल्लेखनीय वृद्धि करने की प्रतिबद्धता जताई है।

भारत-अमेरिका व्यापार समझौते में छिपा क्या है? शशि थरूर ने उठाए सवाल, सरकार से मांगी पूरी पारदर्शिता

नई दिल्ली **(एजेंसी)**। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने मंगलवार को भारत-अमेरिका व्यापार समझौते पर स्पष्टता की मांग करते हुए कहा कि भारतीय वस्तुओं पर टैरिफ घटाकर 18 प्रतिशत करना सकारात्मक कदम हो सकता है, लेकिन सरकार को इसके विवरण स्पष्ट करने चाहिए। भारत-अमेरिका व्यापार समझौते के तहत अमेरिका में भारतीय वस्तुओं पर टैरिफ घटाकर 18 प्रतिशत कर दिया गया है, जबकि वाशिंगटन का दावा है कि इस समझौते से उसे नई दिल्ली को अधिक कृषि उत्पाद निर्यात करने में मदद मिलेगी।

एएनआई से बात करते हुए थरूर ने कहा कि मैं जानना चाहता हूं कि इसमें क्या शामिल है। विपक्ष केवल स्पष्टता मांग रहा है। हमें नहीं पता कि समझौते में क्या है। हमारे पास श्री ट्रंप और श्री मोदी के ट्वीट हैं; क्या संसदीय लोकतंत्र में इतना काफी है? क्या भारत सरकार को आकर देश की जनता को यह नहीं बताना चाहिए कि समझौते में क्या है? थरूर ने भारतीय किसानों और व्यापार पर समझौते के प्रभाव पर सवाल उठाते हुए पूछा कि कृषि के लिए क्या सुरक्षा उपाय किए गए हैं और क्या भारत को अन्य देशों से अपने आयात में बदलाव करना होगा। उन्होंने आगे कहा कि अच्छी खबर का स्वागत है, लेकिन सरकार को पूरी पारदर्शिता बरतनी चाहिए।

बिहार का मेगा बजट : वित्त मंत्री ने पेश किया 34 लाख करोड़ का लेखा-जोखा

पटना **(एजेंसी)**। बिहार के वित्त मंत्री बिजेंद्र यादव ने राज्य विधानसभा में 2026-27 का बजट पेश किया। बजट प्रस्तुत करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि इस वर्ष का 34 लाख करोड़ रुपये का बजट पिछले वर्ष के 31 लाख करोड़ रुपये के बजट से काफी अधिक है। इसमें से 7724 करोड़ रुपये सामाजिक कल्याण योजनाओं के लिए आवंटित किए गए हैं। यादव ने यह भी कहा कि 2026-27 वित्तीय वर्ष के लिए कर राजस्व लगभग 65, 800 करोड़ रुपये रहने का अनुमान है।

बिजेंद्र यादव ने कहा कि राज्य सरकार के न्याय के साथ विकास के आदर्श वाक्य के अनुरूप, सामाजिक कल्याण योजनाओं के लिए 7724 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। उन्होंने आगे कहा कि बजट ईमान, ज्ञान, विज्ञान, अरमान और सम्मान पर केंद्रित होकर तैयार किया गया है। यादव ने पिछले साल नवंबर में हुए विधानसभा चुनावों से पहले शुरू की गई बहुचर्चित मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना का भी जिक्र किया, जिसके बारे में कहा जाता है कि इसने सत्ताधारी एनडीए को निर्णायक जीत दिलाई।

मंत्री ने कहा कि 1.56 करोड़ महिलाओं के खातों में 10, 000 रुपये की राशि हस्तांतरित की गई। जल्द ही, उन महिलाओं को 2 लाख रुपये अतिरिक्त दिए जाएंगे जिन्होंने इस राशि का उपयोग व्यवसाय स्थापित करने के लिए किया होगा। बिहार भाजपा अध्यक्ष संजय सरावगी ने मंगलवार को इस बात पर प्रकाश डाला कि राज्य का बजट पिछले कुछ वर्षों में लगातार बढ़ा है और कहा कि इस वर्ष का बजट राज्य को और आगे ले जाएगा।

बिहार की प्रगति का उल्लेख करते हुए संजय सरावगी ने कहा कि राज्य देश में सबसे तीव्र आर्थिक विकास का अनुभव कर रहा है। उन्होंने कहा कि बिहार में पेश किए गए बजटों में लगातार बजटीय प्रावधानों में वृद्धि देखी गई है। 2005 में यह 23, 000 करोड़ रुपये था; पिछले बजट में यह बढ़कर 3, 17, 000 करोड़ रुपये हो गया और आज वित्त मंत्री बिहार का बजट पेश करेंगे। निसंदेह, यह बजट बिहार को और भी आगे ले जाएगा। उन्होंने आगे कहा कि कल प्रस्तुत आर्थिक सर्वेक्षण से पता चलता है कि बिहार देश के अग्रणी राज्यों में से एक है, जो सबसे तीव्र आर्थिक विकास का अनुभव कर रहा है। किसी राज्य के तीव्र विकास के लिए विचार किए गए सभी मापदंडों पर बिहार आर्थिक सर्वेक्षण में सबसे आगे है।

राहुल गांधी का पीएम मोदी पर बड़ा हमला

कहा- डर और दबाव में अमेरिका से की ट्रेड डील

नई दिल्ली। विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी, जिन्हें लोकसभा में बोलने की अनुमति नहीं दी गई थी, ने संसद के बाहर कहा कि चार महीने से अटका भारत-अमेरिका व्यापार समझौता अचानक कैसे संपन्न हो गया। उन्होंने केंद्र से व्यापार समझौते का विस्तृत विवरण भी मांगा। प्रधानमंत्री मोदी पर देश को बेचने का आरोप लगाते हुए राहुल ने कहा कि प्रधानमंत्री डरे हुए हैं क्योंकि जिन लोगों ने उनकी छवि गढ़ी, वही अब उसे बिगाड़ रहे हैं।

राहुल गांधी ने कहा कि मोदी जी घबराए हुए हैं। पिछले कुछ महीनों से रुका हुआ (अमेरिका-भारत) व्यापार समझौता कल रात नरेंद्र मोदी ने कर दिया। उन पर बहुत दबाव है। नरेंद्र मोदी जी की छवि खराब हो सकती है। मुख्य बात यह है कि हमारे प्रधानमंत्री की छवि खराब हो गई है। जनता को इस बारे में सोचना चाहिए। पहली बार राष्ट्रपति के भाषण में विपक्ष के नेता को बोलने की अनुमति नहीं दी गई। नरेंद्र मोदी

जी ने इस व्यापार समझौते में आपकी मेहनत बेच दी है क्योंकि उनकी छवि खराब हो गई है। उन्होंने देश को बेच दिया है।

उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी जी डरे हुए हैं क्योंकि जिन्होंने उनकी छवि बनाई, वही अब उसे बिगाड़ रहे हैं... अमेरिका में अडानी जी पर एक मामला चल रहा है, असल में यह मामला मोदी जी पर ही है... एपस्टीन फाइल्स में और भी बहुत कुछ है जो अमेरिका ने अभी तक जारी नहीं किया है। इसकी वजह से भी दबाव है। ये दो मुख्य कारण हैं। देश को यह समझना चाहिए। लोकसभा में हंगामे के बीच भाषण देते हुए राहुल गांधी ने पूर्व सेना प्रमुख के अप्रकाशित 'संस्मरण' का हवाला देने वाले लेख की 'प्रमाणित' प्रति प्रस्तुत की। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि जब फैसला पहले ही सुनाया जा चुका है तो वे अप्रत्यक्ष संदर्भ देने के बहाने उसी विषय का उल्लेख नहीं कर सकते।

राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि उन्हें बोलने नहीं दिया गया क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी डरे हुए हैं। उन्होंने कहा कि पिछले चार महीनों से अटका व्यापार समझौता कल शाम अचानक प्रधानमंत्री मोदी ने हस्ताक्षरित कर दिया। प्रधानमंत्री पर भारी दबाव है और 1000 करोड़ रुपये की लागत से बनाया गया छवि का गुब्बारा फूट सकता है। महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रधानमंत्री मोदी को दबाव में लाया गया है। किसने उन्हें दबाव में लाया और यह कैसे किया गया, इस बारे में भारत की जनता को सोचना चाहिए।

कोलकाता समेत पूर्वी भारत में भूकंप के झटके, म्यांमार रहा केंद्र; तीव्रता 6.0 दर्ज

कोलकाता। कोलकाता समेत दक्षिण बंगाल के कई जिलों में मंगलवार शाम को भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए, जिससे आम लोगों में अफरा-तफरी मच गई। भूकंप के झटके इतने स्पष्ट थे कि कई इलाकों में लोग डर के मारे अपने घरों से बाहर निकलकर सड़कों पर आ गए। फिलहाल किसी बड़े जान-माल के नुकसान की सूचना नहीं है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, भूकंप के झटके रात करीब 9:05 बजे महसूस किए गए। कोलकाता के अलावा हावड़ा और हुगली जिलों में भी धरती कांपती हुई महसूस की गई। इतना ही नहीं, उत्तरी बंगाल के कई हिस्सों में भी भूकंप का असर देखा गया।

म्यांमार में था भूकंप का केंद्र

शुरुआती आंकड़ों के मुताबिक, इस भूकंप का केंद्र म्यांमार में स्थित था। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 6.0 मापी गई है। बताया जा रहा है कि भूकंप का केंद्र म्यांमार के अक्याब से करीब 70

मील पूर्व में था और इसकी गहराई लगभग 10 किलोमीटर थी।

बांग्लादेश और उत्तर-पूर्व भारत में भी असर

इस भूकंप के झटके केवल भारत तक सीमित नहीं रहे। बांग्लादेश और उत्तर-पूर्वी भारत के कई इलाकों में भी तेज कंपन महसूस किया गया, जिससे लोग सतर्क हो गए। पिछले 71 घंटों में म्यांमार में इस तीव्रता का यह तीसरा भूकंप है। म्यांमार भूकंपीय रूप से संवेदनशील क्षेत्र में आता है, जिसका असर आसपास के देशों तक महसूस किया जाना असामान्य नहीं है।

क्यों आता है भूकंप?

पृथ्वी के अंदर 7 प्लेट्स हैं, जो लगातार घूमती रहती हैं। जहां ये प्लेट्स ज्यादा टकराती हैं, वह जोन फॉल्ट लाइन कहलाता है। बार-बार टकराने से प्लेट्स के कोने मुड़ते हैं। जब ज्यादा दबाव बनता है तो प्लेट्स टूटने लगती हैं। नीचे की ऊर्जा बाहर आने का रास्ता खोजती हैं और डिस्टर्बेंस के बाद भूकंप आता है।

कांग्रेस को बंगाल में झटका, तमिलनाडु में राहत; सीट बंटवारे पर स्टालिन बोले- जल्द बनाएंगे समिति

चेन्नई। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (द्रमुक) के अध्यक्ष एम के स्टालिन ने मंगलवार को कहा कि पार्टी आगामी विधानसभा चुनावों के मद्देनजर अपने सहयोगी दलों के साथ जल्द ही सीट बंटवारे को लेकर बातचीत शुरू करेगी। इसके लिए द्रमुक की ओर से एक समिति का गठन किया जाएगा।

मुख्यमंत्री स्टालिन ने यह बात चेन्नई के कोलाथुर विधानसभा क्षेत्र में एक सरकारी कार्यक्रम के दौरान मीडिया से संक्षिप्त बातचीत में कही। सीट बंटवारे की प्रक्रिया को लेकर पूछे गए सवाल पर उन्होंने कहा, 'हम जल्द ही बातचीत के लिए समिति का गठन करेंगे।' गौरतलब है कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मंगलवार को एलान किया कि चुनावी राज्य बंगाल में टीएमसी अकेले ही चुनाव लड़ेगी।

राजनीतिक विरोधियों से लेकर केंद्रीय बजट पर क्या बोले स्टालिन?

राजनीतिक विरोधियों को लेकर पूछे गए एक सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री स्टालिन ने कहा कि वह किसी को भी राजनीतिक दुश्मन नहीं मानते। उन्होंने कहा, 'मैं किसी को शत्रु नहीं मानता, मैं सभी को दोस्त के तौर पर देखता हूं।'

केंद्र सरकार के 2026-27 के केंद्रीय बजट

पर प्रतिक्रिया देते हुए स्टालिन ने इसे निराशाजनक बताया। उन्होंने कहा कि पहले भी इस बारे में अपनी बात रख चुके हैं और इस बजट से किसी बदलाव की उम्मीद थी, लेकिन निराशा ही हाथ लगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस बजट से लोगों को कोई राहत नहीं मिली।

भाजपा को सबक सिखाएगी जनता :सीएम स्टालिन

चुनावी वर्ष में अपने मुख्य संदेश को लेकर पूछे गए सवाल पर मुख्यमंत्री ने कहा कि जनता इसका जवाब देगी और भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाएगी। इससे पहले मुख्यमंत्री स्टालिन ने अपने कोलाथुर निर्वाचन क्षेत्र में चेन्नई महानगर विकास प्राधिकरण द्वारा 11.74 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित बहुमंजिला भवन का उद्घाटन किया। इस भवन में रक्त शुद्धिकरण इकाई के साथ फिजियोथेरेपी केंद्र, कृत्रिम अंग केंद्र, डायलिसिस केंद्र और मरीजों के लिए अन्य सुविधाएं उपलब्ध हैं।

मुख्यमंत्री ने इसी परिसर में छह राशन दुकानों का उद्घाटन भी किया। इसके अलावा कोलाथुर झील के पास विकसित एक पार्क का उद्घाटन किया गया, जिसमें स्थानीय निवासियों के लिए मनोरंजन की सुविधाएं हैं। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने छात्रों को लैपटॉप और पुस्तकें भी वितरित कीं।

'चिकन नेक' में अंडरग्राउंड रेल लाइन से पूर्वोत्तर को मिलेगा सुरक्षित गलियारा; सीएम हिमंता सरमा का दावा

गुवाहाटी। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने कहा है कि पश्चिम बंगाल के रणनीतिक रूप से बेहद अहम 'चिकन नेक' कॉरिडोर में प्रस्तावित अंडरग्राउंड रेल लिंक से पूर्वोत्तर भारत को देश के बाकी हिस्सों से जोड़ने का एक सुरक्षित और मजबूत मार्ग सुनिश्चित होगा। उन्होंने इसे भारत की सुरक्षा और रणनीतिक मजबूती की दिशा में एक बड़ा कदम बताया।

मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि दशकों से 'चिकन नेक' कॉरिडोर का इस्तेमाल देश विरोधी ताकतों द्वारा डराने और दबाव बनाने के लिए किया जाता रहा है। उन्होंने कहा कि यह संकरी भूमि पट्टी भारत की एक रणनीतिक कमजोरी रही है, जिसे बहुत पहले ही दूर कर लिया जाना चाहिए था।

'यह एक बड़ा रणनीतिक बदलाव है'

हिमंत बिस्वा सरमा ने कहा प्रस्तावित

अंडरग्राउंड रेल लिंक एक ऐतिहासिक रणनीतिक उपलब्धि है। इससे नॉर्थ ईस्ट और देश के बाकी हिस्सों के बीच एक सुरक्षित और भरोसेमंद परिवहन गलियारा बनेगा। उन्होंने यह भी कहा कि यह कमजोरी 1971 के बाद ही खत्म की जानी चाहिए थी, लेकिन अब केंद्र सरकार इस दिशा में निर्णायक कदम उठा रही है।

प्रधानमंत्री और रेल मंत्री का आभार

मुख्यमंत्री सरमा ने इस फैसले के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का धन्यवाद करते हुए कहा कि यह कदम लंबे समय से चली आ रही रणनीतिक चुनौती को काफी हद तक खत्म कर देगा। उन्होंने पहले दिए गए अपने बयानों का जिक्र करते हुए कहा था कि 1971 के युद्ध के बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी चाहतीं तो इस कॉरिडोर का विस्तार कराया जा सकता था, जिससे नॉर्थ ईस्ट की निर्भरता खत्म हो जाती।

रेल मंत्री ने दी परियोजना की जानकारी

रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सोमवार को बताया था कि सरकार करीब 40 किलोमीटर लंबे 'चिकन नेक' कॉरिडोर में अंडरग्राउंड रेलवे ट्रैक बिछाने की योजना पर काम कर रही है। इसके साथ ही मौजूदा रेल लाइनों को चार लाइन में बदले जाने का भी प्रस्ताव है।

यूएस ट्रेड डील पर संजय राउत का बड़ा आरोप, बोले- ये गौतम अडानी को बचाने के लिए हुई

दिव्यांश

शिवसेना के यूबीटी सांसद संजय राउत ने मंगलवार को दावा किया कि भारत-अमेरिका व्यापार समझौता अडानी समूह के अध्यक्ष गौतम अडानी को लाभ पहुंचाने के लिए किया गया है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि यह समझौता राष्ट्रीय हित और किसानों के कल्याण से समझौता करता है। इस समझौते से भारतीय वस्तुओं पर अमेरिकी टैरिफ में 18इ की कमी आई है, जिससे कपड़ा, दवा और इंजीनियरिंग जैसे क्षेत्रों को लाभ होगा।

संसद के बाहर पत्रकारों से बात करते हुए संजय राउत ने कहा कि पूरा विपक्ष राज्यसभा से वॉकआउट कर गया। राष्ट्रीय हित और किसानों के हित से समझौता किया गया है। मुझे लगता है कि यह व्यापार समझौता गौतम अडानी को बचाने के लिए किया गया है, और हम इसके खिलाफ सड़कों से लेकर संसद तक विरोध प्रदर्शन करेंगे। अरविंद सावंत ने भी इसी तरह की चिंता व्यक्त करते हुए केंद्रीय बजट का हवाला देते हुए सरकार की आर्थिक प्राथमिकताओं पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि क्या आपने अपना बजट देखा है? उस बजट

में आपने शून्य प्रतिशत शुल्क लगाया है। सभी वस्तुएं अमेरिका से आ रही हैं। अमेरिका पाकिस्तान पर 10इ कर लगाता है, जबकि पहले वह हम पर 3इ कर लगाता था।

आज सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि दोनों देशों ने एक व्यापार समझौते पर सहमति जताई है जिसके तहत अमेरिका पारस्परिक शुल्क को घटाकर 25इ से 18इ कर देगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में घोषणा की कि अब 'मेड इन इंडिया' उत्पादों पर अमेरिका का शुल्क घटकर 18इ हो जाएगा और उन्होंने इस शानदार घोषणा के लिए भारत की 14 लाख जनता की ओर से राष्ट्रपति ट्रंप को हार्दिक धन्यवाद दिया।

इससे पहले, मंगलवार को लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर अमेरिकी दबाव में भारतीय किसानों को बेचने का आरोप लगाया था। संसद के बाहर पत्रकारों से बात करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि मोदी जी घबराए हुए हैं। पिछले कुछ महीनों से रुका हुआ (अमेरिका-भारत) व्यापार समझौता कल रात नरेंद्र मोदी ने हस्ताक्षरित कर दिया। उन पर अत्यधिक दबाव है। नरेंद्र मोदी जी की छवि खराब हो सकती है। मुख्य बात यह है कि हमारे प्रधानमंत्री की छवि खराब हो रही है। जनता को इस बारे में सोचना चाहिए। पहली बार विपक्ष के नेता को राष्ट्रपति के भाषण पर बोलने की अनुमति नहीं दी गई।

आदित्य ठाकरे का मोदी सरकार पर तीखा हमला, बोले- लोकतंत्र में मजबूत, राष्ट्रहित में कमजोर

मुंबई(संवाददाता)

मंत्र न्यूज

शिवसेना (यूबीटी) नेता आदित्य ठाकरे ने मंगलवार को भारत-अमेरिका व्यापार समझौते को लेकर केंद्र सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि सरकार लोकतंत्र के मामले में मजबूत होने का दावा करती है, लेकिन भारत की संप्रभुता और राष्ट्रीय हितों की रक्षा करने में कमजोर है। उन्होंने केंद्र सरकार से व्यापार समझौते की स्पष्ट व्याख्या करने और एक खुली प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया के सवालों के जवाब देने की मांग की। भारत-अमेरिका व्यापार समझौते के तहत अमेरिका में भारतीय वस्तुओं पर टैरिफ घटकर 18 प्रतिशत हो गया है, जबकि वाशिंगटन का दावा है कि इस समझौते से उसे नई दिल्ली को अधिक कृषि उत्पाद निर्यात करने में मदद मिलेगी।

एक पोस्ट में उन्होंने लिखा कि भाजपा की भारत सरकारः लोकतंत्र, लोकतांत्रिक विपक्ष, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता, पर्यावरण सक्रियता और सामान्य ज्ञान के पक्ष और विपक्ष में मजबूत। भारत की संप्रभुता की रक्षा करने, व्यापार समझौतों पर बातचीत करने, भू-

राजनीति और राष्ट्रीय हितों को कूटनीतिक रूप से संभालने में कमजोर। केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल भारत-अमेरिका व्यापार समझौते पर संसद को संबोधित करेंगे, जिसके तहत भारत से निर्यात होने वाले सामानों पर टैरिफ घटाकर 18 प्रतिशत कर दिया गया है। यह विपक्षी सांसदों द्वारा कृषि क्षेत्र और रूस से तेल खरीद को लेकर चिंता जताते हुए समझौते का विवरण मांगने के बाद हो रहा है। इससे पहले, राज्यसभा में विपक्ष के नारेबाजी के बीच, केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने आश्वासन दिया कि केंद्र सरकार स्वतः संज्ञान लेते हुए एक बयान जारी करेगी, जिसमें समझौते का विवरण साझा किया जाएगा और सदन में इस पर चर्चा करने के लिए भी तैयार है। नड्डा ने राज्यसभा में कहा कि कल देर रात अमेरिकी राष्ट्रपति ने टैरिफ पर ट्वीट किया और प्रधानमंत्री मोदी को सच्चा मित्र बताया। इसके बाद प्रधानमंत्री ने अमेरिकी राष्ट्रपति को धन्यवाद देते हुए और व्यापार पर ट्वीट किया। सरकार इस व्यापार समझौते पर स्वतः संज्ञान लेते हुए बयान जारी करेगी और इस पर चर्चा भी करेगी।

ऐरोली विभाग में अवैध निर्माणों पर कड़ी कार्रवाई

मुंबई(संवाददाता)

मंत्र न्यूज

आयुक्त डॉ. कैलास शिंदे के निर्देशानुसार, नवी मुंबई महानगरपालिका के माध्यम से तथा अतिरिक्त आयुक्त (2) डॉ. राहुल घेते और उपायुक्त (अतिक्रमण) डॉ. कैलास गायकवाड़ के मार्गदर्शन में अतिक्रमण विभाग द्वारा ऐरोली विभाग में निष्कासन (बेदखली) की कार्रवाई की गई।

नवी मुंबई महानगरपालिका के अधिकार क्षेत्र में, जी-डिवीजन ऐरोली कार्यालय के अंतर्गत, श्री बाबन बाबू पवार, गुफरान खान (ठेकेदार), ओंकार निर्गुडे (वास्तुकार) द्वारा एसएस-II/बी-229, सेक्टर-02, ऐरोली, नवी मुंबई तथा श्री प्रेमानंद प्रजापति, गुफरान खान (ठेकेदार), ओंकार निर्गुडे (वास्तुकार) द्वारा एसएस-II/बी-230, सेक्टर-02, ऐरोली, नवी मुंबई में महानगरपालिका की अनुमति के बिना निर्माण कार्य प्रारंभ किया गया था।

उक्त अवैध निर्माणों के संबंध में महाराष्ट्र क्षेत्रीय नगर नियोजन एवं नगर विकास अधिनियम, 1966 की धारा 54 के अंतर्गत विभागीय कार्यालय के माध्यम से संबंधित व्यक्तियों– बाबन बाबू पवार, गुफरान खान (ठेकेदार), ओंकार निर्गुडे (वास्तुकार), एसएस-II/बी-229 तथा प्रेमानंद प्रजापति, गुफरान खान (ठेकेदार), ओंकार निर्गुडे (वास्तुकार), एसएस-II/बी-230, सेक्टर-02, ऐरोली, नवी मुंबई–को नोटिस जारी किए गए थे। नोटिस में संबंधितों को स्वयं अवैध निर्माण हटाने के निर्देश दिए गए थे, किंतु इसके बावजूद अवैध निर्माण जारी रखा गया।

इसके पश्चात, छठे आयुक्त एवं ऐरोली विभागीय अधिकारी नैनिश एस. बडले के नियंत्रण में ध्वस्तीकरण अभियान चलाकर उक्त अवैध निर्माण को आंशिक रूप से ध्वस्त किया गया। साथ ही, अवैध निर्माण हटाने की कार्रवाई के लिए 5,000 रुपये प्रति प्रकरण के अनुसार कुल 10,000 रुपये का दंड शुल्क वसूल किया गया।

इस ध्वस्तीकरण अभियान के लिए जी-डिवीजन कार्यालय के अतिक्रमण विभाग के अधिकारी एवं कर्मचारी, 10 मजदूर, 2 ब्रेकर, 1 गैस कटर, 2 कंक्रीट कटर तथा पुलिस बल तैनात किया गया था।

भविष्य में भी इसी प्रकार अवैध निर्माणों के विरुद्ध कार्रवाई को और अधिक सख्ती से जारी रखा जाएगा।

जनगणना 2027 को लेकर पहला प्रशिक्षण सत्र नवी मुंबई में उत्साहपूर्वक संपन्न

मुंबई(संवाददाता)

मंत्र न्यूज

जनगणना कार्य निदेशालय, महाराष्ट्र की ओर से जनगणना 2027 से संबंधित कार्यवाही प्रारंभ की जा रही है। इसी क्रम में नवी मुंबई महानगरपालिका के चार्ज अधिकारी एवं जनगणना से संबंधित अधिकारियों के लिए प्रथम चरण का प्रशिक्षण कार्यक्रम, महानगरपालिका आयुक्त डॉ. कैलास शिंदे के मार्गदर्शन में मुख्यालय स्थित ज्ञानकेंद्र में संपन्न हुआ। इस अवसर पर सहायक निदेशक (जनगणना) श्रीमती अनुमोल एम. तथा सांख्यिकी अधिकारी श्रीमती रुचिता तेलंग ने जनगणना कार्य से संबंधित विस्तृत जानकारी दी।

नवी मुंबई महानगरपालिका परिमंडल-2 के उप आयुक्त एवं शहर जनगणना अधिकारी श्री संजय शिंदे तथा परिमंडल-1 के उप आयुक्त श्री सोमनाथ पोटरे ने महानगरपालिका की ओर से उपस्थित प्रशिक्षकों का स्वागत किया।

जनगणना एक राष्ट्रीय कार्य है, जिसकी पहली गणना वर्ष 1872 में हुई थी। इससे पूर्व वर्ष 2011 में जनगणना संपन्न हुई थी तथा वर्ष 2021 में अगली जनगणना अपेक्षित थी, किंतु कोविड काल के कारण वह संभव नहीं हो सकी। अब यह प्रक्रिया पुनः प्रारंभ हो रही है, जो देश की 16वीं तथा स्वतंत्रता के बाद की

8वीं जनगणना होगी।

वर्ष 2027 की इस जनगणना की विशेषता यह है कि यह पहली डिजिटल जनगणना होगी। इसमें मोबाइल ऐप के माध्यम से जानकारी दर्ज की जाएगी तथा पते का जियो-टैगिंग भी किया जाएगा। इसके लिए एचएलओ नामक विशेष ऐप का उपयोग किया जाएगा। जनगणना के प्रथम चरण में घर सूचीकरण (हाउस लिस्टिंग) के अंतर्गत समूहवार जानकारी संकलित की जाएगी तथा दूसरे चरण में नागरिकों की अन्य जानकारी एकत्र की जाएगी। विशेष रूप से नागरिक स्वयं भी ऐप के माध्यम से अपनी जानकारी दर्ज कर सकेंगे, जिसे स्व-गणना कहा जाएगा। इस प्रशिक्षण सत्र में प्रथम चरण में किए जाने वाले कार्यों की विस्तृत जानकारी सहायक निदेशक (जनगणना) श्रीमती अनुमोल एम. एवं सांख्यिकी अधिकारी श्रीमती रुचिता तेलंग द्वारा प्रस्तुतीकरण के माध्यम से दी गई।

इस अवसर पर शहर जनगणना अधिकारी एवं उप आयुक्त श्री संजय शिंदे ने कहा कि जनगणना एक राष्ट्रीय महत्व का कार्य है, जो केवल जनसंख्या की संख्या जानने तक सीमित नहीं है, बल्कि देश के आर्थिक, सामाजिक विकास एवं अन्य अनेक क्षेत्रों में जनगणना से प्राप्त आंकड़ों का उपयोग किया जाता है। यह कार्य राष्ट्रीय स्तर पर निश्चित समय-सीमा में पूरा किया जाना होता है, इसलिए समयबद्ध योजना बनाना आवश्यक है। उन्होंने बताया कि नवी मुंबई महानगरपालिका से अपेक्षा की जा रही है कि वह इस कार्य में भी एक रोल मॉडल के रूप में उदाहरण प्रस्तुत करे, जिससे अन्य संस्थाएं प्रेरणा लें। इस दृष्टि से हम सभी की बड़ी जिम्मेदारी है।

जनगणना का कार्य लगभग 2500 से अधिक प्रगणकों द्वारा किया जाएगा, जिन पर 400 से अधिक पर्यवेक्षकों की निगरानी रहेगी। महानगरपालिका आयुक्त डॉ. कैलास शिंदे प्रमुख जनगणना अधिकारी होंगे तथा उप आयुक्त श्री संजय शिंदे शहर जनगणना अधिकारी के रूप में अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे। प्रत्येक विभाग के सहायक आयुक्त एवं विभाग अधिकारी अपने-अपने विभाग के चार्ज ऑफिसर के रूप में कार्य करेंगे। जनगणना 2027 के अंतर्गत हाउस लिस्टिंग कार्य से प्रथम चरण की शुरुआत होगी, जिसके लिए संबंधित अधिकारियों एवं कर्मचारियों को पहला प्रशिक्षण दिया गया।

जनगणना अधिनियम 1948 के अनुसार नागरिकों द्वारा प्रगणकों को दी गई जानकारी पूर्णतः गोपनीय रखी जाती है और यह दस्तावेज केवल केंद्रीय जनगणना विभाग के अधिकार क्षेत्र में रहता है। इसलिए नवी मुंबई के नागरिकों से महानगरपालिका आयुक्त डॉ. कैलास शिंदे की ओर से यह अपील की गई है कि वे जनगणना कार्य के लिए घर-घर आने वाले प्रगणकों को सही एवं सत्य जानकारी देकर इस राष्ट्रीय कार्य में पूर्ण सहयोग करें।

राऊत राजनीति छोड़कर मनोरंजक वेबसीरीज़ की पटकथा लिखें

भाजपा मीडिया विभाग प्रमुख नवनाथ बन की तीखी टिप्पणी

मुंबई(संवाददाता)

मंत्र न्यूज

अजित पवार स्वगृही लौटने के लिए इच्छुक थे, ऐसा बिनबुनियाद और मनगढ़ंत बयान देने वाले संजय राऊत जानबूझकर किसी रहस्यमय और मनोरंजक वेबसीरीज़ की तरह चटपटी पटकथा लिखकर झूठी जानकारी फैला रहे हैं। अजित पवार के बारे में निराधार बयानबाज़ी करने वाले राऊत इस संबंध में ठोस सबूत पेश करें–यह खुली चुनौती भारतीय जनता पार्टी के मीडिया विभाग प्रमुख नवनाथ बन ने मंगलवार को दी।

सांसद पद पर रहते हुए झूठे आरोप लगाने की आदत डाल चुके संजय राऊत को राजनीति छोड़कर ओटीटी प्लेटफॉर्म के लिए निर्देशन और पटकथा लेखन करना चाहिए, तभी उनका 'दुकान' चलेगा–ऐसी तीखी टिप्पणी भी श्री. बन ने की। उन्होंने स्पष्ट किया कि अजित पवार कभी भी स्वगृही लौटने के इच्छुक नहीं थे। हां, वे अन्य घटकों को एनडीए में शामिल करने के प्रयासरत थे या नहीं, इस पर विचार किया जा सकता है–ऐसी पुस्ती भी श्री. बन ने जोड़ी।

राऊतों को जल-स्थल-काष्ठ-पाषाण हर जगह 'ऑपरेशन लोटस' ही दिखता है अजित पवार के विमान हादसे को 'ऑपरेशन लोटस' का हिस्सा बताकर भाजपा पर ओछे आरोप लगाने से पहले संजय राऊत ठोस सबूत पेश करें। हवा

में तीर चलाने का काम न करें–ऐसा कहते हुए श्री. बन ने राऊतों की कड़ी आलोचना की। उन्होंने कहा कि भूकंप, सुनामी या बाढ़ आ जाए, तब भी राऊतों को हर घटना में 'ऑपरेशन लोटस' ही नजर आता है, जो हास्यास्पद है।

अजित पवार का विमान हादसा एक दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना अजित पवार का विमान हादसा अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण था। केंद्र और राज्य सरकार इस हादसे की जांच कर रही हैं और जांच से सच्चाई सामने आएगी–ऐसा श्री. बन ने कहा। उन्होंने यह भी याद दिलाया कि शरद पवार ने स्वयं स्पष्ट किया है कि यह एक दुर्घटना थी, इसके पीछे कोई साजिश नहीं थी।

श्री. बन ने सवाल उठाया कि क्या संजय राऊत शरद पवार से भी अधिक बुद्धिमान हैं? उन्होंने कहा कि कल यदि अदालत का फैसला आ भी जाए, तब भी राऊत कहेंगे कि अदालत बिक गई है। राऊतों को भारतीय न्याय व्यवस्था पर विश्वास नहीं है, इसलिए उन्हें पाकिस्तान की अदालत में जाना चाहिए–ऐसा खोचक सल्ला भी उन्होंने दिया।

इस पूरे प्रकरण में संजय राऊत जानबूझकर झूठा नैरेटिव फैला रहे हैं। जो राऊत लगातार अजित पवार का अपमान करते रहे, उन्हें अचानक अजित पवार के प्रति प्रेम उमड़ आया है। यह मृतक के सिर पर घी खाने जैसा नीच कृत्य है–ऐसी प्रखर टीका भी श्री. बन ने की।

रोज़ाना पत्रकार परिषद कर झूठ बोलना संजय राऊत का व्यवसाय बन गया है। कभी वे कहते हैं कि भाजपा के भ्रष्टाचार की फाइल अजित पवार के पास थी, इसलिए यह सब हुआ; और उसी पत्रकार परिषद के अंत में कहते हैं कि भाजपा पार्थ पवार को बचा रही है। कम से कम एक पत्रकार परिषद में तो राऊत एक ही रुख रखें। परस्पर विरोधी बयान देकर राऊत स्वयं अपने ही वक्तव्यों का खंडन कर रहे हैं और होश खोकर असंबद्ध प्रलाप कर रहे हैं–ऐसी घनघोर आलोचना भी श्री. बन ने की।

मीरा भायंदर में भाजपा का शक्ति प्रदर्शन, दिंपल मेहता बनीं मेयर, कांग्रेस-शिवसेना का दांव फेल

मुम्बई **(एजेंसी)**। महाराष्ट्र के मीरा भायंदर नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी की पार्षद दिंपल मेहता नई महापौर चुनी गई हैं। उनके चुनाव का महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (एमएनएस) और महाराष्ट्र एकीकरण समिति (एमईएस) ने कड़ा विरोध जताया है। ये पार्टियां मांग कर रही हैं कि महापौर के पद पर केवल मराठी भाषी नेता को ही नियुक्त किया जाना चाहिए। मीरा भायंदर नगर निगम में 95 पार्षद हैं। इनमें भाजपा की 78 निर्वाचित सीटों के साथ मजबूत स्थिति है। कांग्रेस के 13 पार्षद हैं, शिवसेना (शिंदे गुट) के 3 पार्षद हैं और भाजपा के एक बागी उम्मीदवार ने भी जीत हासिल की है। गौरतलब है कि बागी पार्षद अनिल पाटिल ने भी भाजपा को अपना समर्थन दिया है। कांग्रेस और शिवसेना (शिंदे गुट) ने महापौर चुनाव में भाजपा की ताकत को चुनौती देने के लिए एक संयुक्त मोर्चा बनाया था। भाजपा ने वरिष्ठ नेता नरेंद्र मेहता की भाभी दिंपल मेहता को अपना उम्मीदवार बनाया था। वहीं, कांग्रेस-शिवसेना गठबंधन ने रुबीना खातून को इस पद के लिए अपना उम्मीदवार नामित किया। गैर-मराठी महापौर के चयन को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। महाराष्ट्र एकीकरण समिति ने दिंपल मेहता की नियुक्ति के विरोध में आज विरोध प्रदर्शन और तीन किलोमीटर लंबी सड़क पदयात्रा निकालने की घोषणा की है।

मध्य रेल

सोलापुर मण्डल

विद्युत कार्य

भारत के राष्ट्रपति के लिए और उनकी ओर से वरिष्ठ मंडल विद्युत इंजीनियर (क.वि.), मध्य रेल, सोलापुर, निम्नलिखित कार्य के लिए ख्याति प्राप्त और अनुभवी विद्युत ठेकेदारों से रेलवे की ई प्रोक्यूरमेंट वेबसाइट **www.ireps.gov.in** पर ऑनलाइन ई निविदा आमंत्रित करते हैं। [दो बोली प्रणाली] **ई-निविदा सूचना क्र. SUR/TD/T/2026/02S.** कार्य का नाम : दो वर्षों की अवधि के लिए सोलापुर डिवीजन के पारेवाडी, कुर्दुवाडी, सोलापुर, दुधनी और कलबुर्गी डिपो के ट्रैक्शन सबस्टेशन (टीएसएस) का संचालन का कार्य। कार्य की अनुमानित लागत : ₹ 1,19,41,949.99। बयाना राशि : ₹ 2,09,700/-। कार्य पुरा करने की अवधि : 24 माह। निविदा प्रस्ताव की वैधता : 90 दिन। वेबसाइट पर निविदा बंद होने की तिथि और समय : दि. 25.02.2026 को 15.00 बजे। EXP-03

टिकट के लिए UTS App डाउनलोड करे

मध्य रेल

भुसावल मंडल

ई-नीलामी सूचना

भुसावल मण्डल, मध्य रेल ने ई-नीलामी पट्टा प्रारूप के जरिए **www.ireps.gov.in** पर नीचे उल्लेखित सम्पत्तियों को पट्टे पर प्रदान करने हेतु ई-नीलामी आमंत्रित की है। इच्छुक बोलीदाताओं से ई-नीलामी से पहले पंजीकरण कराने तथा साइट पर सभी आवश्यक दस्तावेज अपलोड करने का अनुरोध किया जाता है। अधिक विवरण के लिए बोलीदाताओं से नीचे उल्लेखित ई-नीलामी के संबंध में सभी विवरण की जानकारी हासिल करने के लिए वेबसाइट **www.ireps.gov.in** देखने का अनुरोध किया जाता है।

श्रेणी	सूचीपत्र सं.	सम्पत्ति का विवरण	नीलामी की तिथि एवं समय
मिस्ले-स्टेटिक सर्विसेस	बीएसएल-एमएसआरजेड एमएफसी26-2	1) अकोला स्टेशन में रिलेक्शन जोन के लिए 3 वर्षों की अवधि हेतु अनुबंध के लिए ई-नीलामी। 2) मनमाड स्टेशन में मल्टी फंक्शनल कॉमप्लेक्स के लिए 5 वर्षों हेतु अनुबंध।	18.02.2026 11:00:00 बजे
विज्ञापन	बीएसएल-आरडीजी-सीएसएन-26	चालीसगाँव स्टेशन में सार्वजनिक उद्घोषणा प्रणाली के माध्यम से 3 वर्षों की अवधि के लिए ऑडियो विज्ञापन के अनुबंध हेतु ई-नीलामी।	18.02.2026 11:00:00 बजे

इस निविदा के संबंध में आगे के संयोजन/शुद्धिपत्र, समय का विस्तार, स्पष्टीकरण इत्यादि, यदि कोई हो, वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाएगा। बोलीदाता को नवीनतम जानकारी हासिल करने के लिए नियमित रूप से वेबसाइट देखते रहना होगा। EXP

रेलमदद हेल्पलाईन 139

पश्चिम रेलवे – रतलाम मंडल

विविध कार्य

डब्ल्यू/623/एनआईटी/1, दिनांक : 29/01/2026, मंडल रेल प्रबंधक /मंडल कार्यालय (कार्यलेखा शाखा) पश्चिम रेलवे, के लिये "खुली निविदा" ई–निविदा के माध्यम से वेबसाइट **www.ireps.gov.in** पर आमंत्रित करते हैं। विवरण इस प्रकार है।

ई–निविदा सं. एवं कार्य का नाम	अनुमानित लागत (₹)	बयाना राशि (₹)
1. आरटीएम–2025–26–139. चंदेरिया–धोसवास सेक्शन – स्टाफ क्वार्टर (सीओआर, एसएमपी, जीआरएफ एवं एनबीएच रेलवे कॉलोनी) में पानी की आपूर्ति और ड्रेनेज सुविधा का सुधार।	2,34,09,347.19	2,67,100
2. आरटीएम–2025–26–140. नीमच–मंदसौर सेक्शन – एसएसई/पी.वे/नीमच ऑफिस, डिपो और स्टोर में बिजली के काम सहित सुधार।	1,30,49,858.15	2,15,300
3. आरटीएम–2025–26–172. डॉ. अंबेडकर नगर (डीएडीएन) – खराब क्वार्टरों (टी/190ए से एन=14 नग, टी/193ए से एफ–06 नग) के स्थान पर 20 यूनिट टाइप 2 क्वार्टर उपलब्ध कराना जिसमें बिजली का काम भी शामिल है।	4,47,69,420.29	3,73,900
4. आरटीएम–2025–26–173. रतलाम डिवीजन– अजनोद–12 नग और पालिया–08 नग (कुल 20 नग) टाइप 2 क्वार्टर उपलब्ध कराना जिसमें बिजली का काम भी शामिल है।	4,51,08,038.26	3,75,600
5. आरटीएम–2025–26–174. निम्बाहेड़ा– खराब क्वार्टर नं. जी–33ए से एच–8 नग और टी/16ए से बी–2 नग (कुल 10 नग) के स्थान पर टाइप 2 स्टाफ क्वार्टर (10 नग) का निर्माण जिसमें बिजली का काम भी शामिल है।	2,28,76,170.64	2,64,400
6. आरटीएम–2025–26–175. सीएनए–आरटीएम सेक्शन– विभिन्न स्टेशनों, एलसी गेट् और गैंग चौल पर 2 वर्ष के लिए टैंकर से पीने के पानी की आपूर्ति।	54,55,440.64	1,09,100
7. आरटीएम–2025–26–176. बेराच–बेराच केबिन पर एक साथ रिसेप्शन सुविधा के साथ पूरी लंबाई की दूसरी लूप लाइन का प्रावधान।	1,26,11,336.07	2,13,100
8. आरटीएम–2025–26–177. 1. चित्तौड़गढ़– पीएफ लाइन नं 2 (डीएन एमएल), पीएफ लाइन नं. 4 (कॉमन लूप लाइन) और पीएफ नं. 5 (अप लूप लाइन) पर ब्लास्ट लैस ट्रैक का प्रावधान और 2. उज्जैन स्टेशन– पीएफ नं. 1 (डाउन मेन), पीएफ नं. 3/4 (लूप), पीएफ नं. 5 (लूप) और पीएफ नं. 6 (लूप) लाइन पर ब्लास्टलैस ट्रैक का प्रावधान।	33,37,98,534.58	18,19,000
9. आरटीएम–2025–26–179. 1. राजेंद्र नगर–सिंहस्थ 2028 के संबंध में स्टेबलिंग लाइन का प्रावधान और 2. लेकोडा में सिंहस्थ 2028 के संबंध में मौजूदा "डी" क्लास को "बी" क्लास में अपग्रेड करना जिसमें बिजली का काम भी शामिल है।	17,46,63,526.01	10,23,300
10. आरटीएम–2025–26–180. डीईएन नॉर्थ आरटीएम क्षेत्राधिकार के तहत हुक बोल्ट के लिए साइज़ एम–27 लॉक नट एम 027 के लिए सिंगल पीस स्प्रिंग इंसर्टेड रियूजेबल सीज़ नट प्रदान करना और लगाना।	55,71,467.20	1,11,400
11. आरटीएम–2025–26–181. चंदेरिया–रतलाम फतेहाबाद सेक्शन–डिवीजन इंजीनियर (नॉर्थ) रतलाम के क्षेत्राधिकार में टिम्बल गेदो वोर्सिस ट्रॉली सिस्टम का उपयोग करके प्री और पोस्ट टैम्पिंग ट्रैक माप सर्वेक्षण।	62,07,081.57	1,24,200
12. आरटीएम 2025–26–182. रतलाम डिवीजन–जीआरपी थाना/बैरक में सुधार/मरम्मत (7 स्टेशन – दाहोद एस, एमजीएन, सीओआर, यूजेएन, एसईएच, आईएनडी और डीएडीएन) का सुधार/मरम्मत।	52,45,620.57	1,04,900

अनुमानित मात्रा : क्र.सं.–1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12 के लिए – निविदा अनुसूची के अनुसार। **निविदा प्रपत्र का मूल्य :** क्र.सं.– 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12 के लिए – शून्य। **कार्य समापन अवधि :** क्र.सं.–1, 2, 5, 7, 10, 11 और 12 के लिए – 12 महीने। क्र.सं.– 3, 4 और 9 के लिए– 18 महीने। क्र.सं.– 6 और 8 के लिए – 24 महीने। **वेबसाइट पर अपलोड करने की तिथि :** क्र.सं. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12 के लिए – 29.01.2026. **निविदा खुलने की तिथि :** क्र.सं. 1 और 6 के लिए – 20.02.2026. क्र.सं. 2, 9 और 12 के लिए – 24.02.2026. क्र.सं. 3, 4 और 5 के लिए– 02.03.2026. क्र.सं. 7 के लिए – 06.03.2026. क्र.सं. 8, 10 और 11 के लिए – 27.02.2026. • विस्तृत निविदा सूचना, अर्हता शर्तें एवं अन्य शर्तें वेबसाइटः **www.ireps.gov.in** पर उपलब्ध हैं।

SNP-440

हमें लाइक करें : facebook.com/WesternRly | हमें फॉलो करें : x.com/WesternRly

बृहन्मुंबई महानगरपालिका के पुल विभाग के अधिकारी एवं अभियंता सम्मानित

मुंबई। बृहन्मुंबई महानगरपालिका के पुल विभाग के अधिकारियों एवं अभियंताओं ने मुंबई में महत्वपूर्ण पुलों के निर्माण कार्य को निर्धारित समय-सीमा में पूर्ण करने में उल्लेखनीय भूमिका निभाई है। इस महत्वपूर्ण योगदान के लिए बृहन्मुंबई महानगरपालिका के आयुक्त एवं प्रशासक श्री भूषण गगराणी ने संबंधित अधिकारियों एवं अभियंताओं को प्रमाण-पत्र प्रदान कर सम्मानित किया।

यह सम्मान समारोह बृहन्मुंबई महानगरपालिका मुख्यालय में आयोजित किया गया। इस अवसर पर अपर नगर आयुक्त (परियोजना) श्री अभिजीत बांगर, मुख्य अभियंता (पुल) श्री उत्तम श्रोते तथा पुल विभाग के अधिकारी एवं अभियंता उपस्थित थे। इसी अवसर पर सेवानिवृत्ति के उपलक्ष्य में मुख्य अभियंता (पुल) श्री उत्तम श्रोते को भी आयुक्त एवं प्रशासक श्री भूषण गगराणी द्वारा पुष्पगुच्छ देकर सम्मानित किया गया।

महानगरपालिका के पुल विभाग द्वारा बांद्रा पूर्व स्कायवॉक, बेलासिस ब्रिज तथा सफेद पुल का निर्माण अत्यंत कुशलता से किया गया। इन परियोजनाओं का कार्य प्रशासनिक दृष्टि से चुनौतीपूर्ण था। संबंधित परियोजनाओं में योगदान देने वाले अधिकारियों एवं अभियंताओं को उनके उत्कृष्ट कार्य के लिए प्रमाण-पत्र देकर सम्मानित किया गया।

'पुलिस एस्कॉर्ट शुल्क पर सौदेबाजी नहीं चलेगी'; अबू सलेम की पैरोल याचिका पर हाईकोर्ट सख्त

मुंबई(संवाददाता)

मंत्र न्यूज

मुंबई। बॉम्बे हाईकोर्ट ने 1993 मुंबई सिलसिलेवार धमाकों के मामले में सजा काट रहे अंडरवर्ल्ड डॉन अबू सलेम को स्पष्ट शब्दों में कहा है कि पैरोल पर जाने के लिए पुलिस एस्कॉर्ट शुल्क को लेकर कोई सौदेबाजी नहीं की जा सकती। अदालत ने संकेत दिए कि यदि निर्धारित राशि जमा नहीं की गई तो उसकी पैरोल याचिका खारिज की जा सकती है।

न्यायमूर्ति अजय गडकरी और न्यायमूर्ति श्याम चंदक की खंडपीठ अबू सलेम की उस याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें उसने अपने बड़े भाई अबू हकीम अंसारी के निधन पर उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ स्थित पैतृक गांव जाने के लिए पैरोल मांगी थी।

17 लाख से ज्यादा का एस्कॉर्ट खर्च

सलेम इस समय नासिक रोड सेंट्रल जेल में बंद है। जेल प्रशासन ने अदालत को बताया कि अगर सलेम को पुलिस एस्कॉर्ट के साथ पैरोल दी जाती है, तो उसे 17 लाख रुपये से अधिक की राशि एस्कॉर्ट टीम के खर्च के तौर पर जमा करनी होगी। मंगलवार को सुनवाई के दौरान सलेम की वकील फरहाना शाह ने अदालत को बताया कि यह राशि

बेहद ज्यादा है और उनका मुवक्किल वर्षों से जेल में बंद होने के कारण आर्थिक रूप से बेहद कमजोर हालत में है। उन्होंने कहा कि सलेम एक लाख रुपये से अधिक भुगतान करने की स्थिति में नहीं है।

कोर्ट की दो टूक

इस पर हाईकोर्ट ने साफ कहा आप एस्कॉर्ट शुल्क पर मोलभाव नहीं कर सकते। अगर पैरोल चाहिए, तो तय शुल्क देना होगा। अदालत ने वकील से कहा कि या तो याचिका वापस ले ली जाए या फिर अदालत इसे खारिज कर देगी। इसके बाद सलेम की ओर से समय मांगे जाने पर मामले की सुनवाई गुरुवार तक के लिए टाल दी गई।

पहले भी खारिज हो चुकी है मांग

अबू सलेम ने दिसंबर 2025 में हाईकोर्ट का रुख किया था। उसने बताया था कि भाई की मौत नवंबर में हुई थी, लेकिन क्रिसमस अवकाश के कारण याचिका दाखिल करने में देरी हुई। सलेम के अनुसार, उसने 15 नवंबर को 14 दिन की आपात पैरोल के लिए जेल प्रशासन को आवेदन दिया था, ताकि अंतिम संस्कार और अन्य रस्मों में शामिल हो सके। हालांकि, जेल अधिकारियों ने 20 नवंबर 2025 को उसका आवेदन खारिज कर दिया था।

अब तक सीमित पैरोल

अपनी याचिका में सलेम ने यह भी कहा कि नवंबर 2005 में गिरफ्तारी के बाद से उसे केवल कुछ ही बार, वह भी मां और सौतेली मां के निधन पर, सीमित अवधि की पैरोल दी गई है। गौरतलब है कि अबू सलेम को पुर्तगाल से प्रत्यर्पित कर 11 नवंबर 2005 को भारत लाया गया था। वह 1993 मुंबई धमाकों के मामले में 25 साल की सजा काट रहा है। इसके अलावा, 1995 में मुंबई के बिल्डर प्रदीप जैन की हत्या के मामले में एक विशेष TADA अदालत ने उसे आजीवन कारावास की सजा भी सुनाई है।

महाराष्ट्र में बड़ा हादसा टला, उड़ान से ठीक पहले पंकजा मुंडे के हेलीकॉप्टर में आई खराबी

मुंबई(संवाददाता)

मंत्र न्यूज

अजित पवार की विमान दुर्घटना में मृत्यु के कुछ दिनों बाद, महाराष्ट्र के अन्य राजनेता भी हवाई यात्रा करते समय सावधानी बरत रहे हैं। ताजा घटना भाजपा नेता और कैबिनेट मंत्री पंकजा मुंडे से जुड़ी है, जिनके हेलीकॉप्टर में तकनीकी खराबी आ गई, जिसके कारण उन्हें अपनी हेलीकॉप्टर यात्रा स्थगित करनी पड़ी।

पंकजा कहाँ जाने की योजना बना रही थीं?

पंकजा मुंडे जिला परिषद चुनाव प्रचार के लिए संभाजीनगर से लातूर के लिए हेलीकॉप्टर से उड़ान भरने वाली थीं। हालांकि, पायलट ने तकनीकी खराबी की सूचना दी, जिसके कारण उन्हें अपनी यात्रा स्थगित करनी पड़ी। गौरतलब है कि अजित पवार की विमान दुर्घटना में मृत्यु के बाद, सभी राजनेता हवाई यात्रा करते समय सावधानी बरत रहे हैं। छत्रपति संभाजीनगर से उड़ान भरने से ठीक पहले खराबी का पता चला। पंकजा मुंडे को जिला परिषद चुनाव प्रचार के लिए लातूर जाना था। पंकजा मुंडे दूसरे हेलीकॉप्टर से सभा में शामिल होंगी। अजित पवार का हाल ही में बारामती में विमान दुर्घटना में निधन हो गया। यह ध्यान देने योग्य है कि एनसीपी नेता अजित पवार का बारामती में विमान दुर्घटना में निधन हो गया। तब से, सभी राजनेता हवाई यात्रा करने से पहले सावधानी बरत रहे हैं।

अजित पवार महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री थे और बारामती में एक रैली को संबोधित करने के लिए सुबह मुंबई से रवाना हुए थे। अजित पवार के निधन के बाद, उनकी पत्नी सुनेत्रा पवार को महाराष्ट्र का उपमुख्यमंत्री नियुक्त किया गया है। अजीत पवार से पहले, गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी की भी 2025 में अहमदाबाद में एयर इंडिया के विमान दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। यह दुर्घटना 12 जून, 2025 को अहमदाबाद से उड़ान भरने के कुछ ही समय बाद हुई थी। इस दुर्घटना में एयर इंडिया की फ्लाइट 171 पूरी तरह से नष्ट हो गई थी। इससे पहले, भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, जनरल बिपिन रावत की 2021 में तमिलनाडु के कुन्नूर में एक Mi-17V5 हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। यह ध्यान देने योग्य है कि विमान दुर्घटना में सवार लोगों के बचने की संभावना बहुत कम होती है।

शिवसेना की शर्मिला पिंपलोलकर बनीं ठाणे की नई मेयर, भाजपा के कृष्णा पाटिल चुने गए डिप्टी मेयर

ठाणे। एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना की शर्मिला पिंपलोलकर मंगलवार को नगर निकाय की एक विशेष आम सभा की बैठक में ठाणे की 23वीं मेयर निर्विरोध चुनी गईं। उन्होंने चार साल बाद राज्य सरकार द्वारा नियुक्त

प्रशासक की जगह ली। भाजपा के कृष्णा पाटिल को डिप्टी मेयर चुना गया। इन पदों के लिए कोई और नामांकन दाखिल नहीं किया गया था, जिससे उनका निर्विरोध चुनाव हुआ।

एक शिवसेना नेता ने कहा, महायुति गठबंधन के भीतर आंतरिक महत्वाकांक्षाओं को संभालने के लिए, शिवसेना और भाजपा ने एक रोटेशन फॉर्मूला पेश किया है, जिसके अनुसार मेयर और डिप्टी मेयर का कार्यकाल 15 महीने तय किया गया है। उन्होंने कहा कि यह व्यवस्था चुने हुए सदस्यों को संतुष्ट करने के लिए की गई है, जिससे पूरे कार्यकाल में चार अलग-अलग पार्षदों को हर भूमिका में काम करने का मौका मिलेगा।

नगर निगम मुख्यालय जश्न के माहौल में बदल गया, जहां पारंपरिक महाराष्ट्रीयन पोशाक पहने महिलाओं ने लेजिम नृत्य किया। ठाणे नगर निगम के प्रवेश गलियारे के ऊपर छत्रपति शिवाजी महाराज की एक विशाल प्रतिमा स्थापित की गई, जिसने देखने वालों और अधिकारियों दोनों का ध्यान खींचा।

131 सदस्यीय टीएमसी में शिवसेना 75 पार्षदों के साथ सबसे बड़ी पार्टी है। उसकी सहयोगी भाजपा के पास 28 सीटें हैं। बाकी सीटें एनसीपी (शरद पवार), एनसीपी, एआईएमआईएम, शिवसेना (यूबीटी) और एक निर्दलीय के बीच बंटी हुई हैं।

मध्य रेलवे के सोलापुर मंडल ने पहले ही वर्ष में इंडियन ऑयल निगम लिमिटेड की पाकणी साइडिंग से रेक लोडिंग का त्रिशतक पूरा किया

मुंबई(संवाददाता)

मंत्र न्यूज

मध्य रेलवे के सोलापुर मंडल ने सोलापुर जिले में स्थित इंडियन ऑयल निगम लिमिटेड की पाकणी साइडिंग पर पेट्रोलियम उत्पादों की लोडिंग में जनवरी 2026 तक निरंतर और प्रभावशाली वृद्धि दर्ज करते हुए माल परिवहन के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। पाकणी साइडिंग पर पेट्रोलियम उत्पादों के कुल 301 रेक लोड किए गए, जिससे 44 करोड़ 20 लाख रुपये का सशक्त मालभाड़ा राजस्व प्राप्त हुआ है।

माल परिवहन लोडिंग की उपलब्धि

पाकणी साइडिंग से पेट्रोलियम उत्पादों की पहली रेक लोडिंग 28 जनवरी 2025 को की गई थी। यह उपलब्धि भारतीय रेल और इंडियन ऑयल निगम लिमिटेड–दोनों के लिए ऐतिहासिक रही। संचालन प्रारंभ होने के बाद से ही इस साइडिंग का प्रदर्शन अत्यंत उत्साहजनक रहा है।

जनवरी 2026 तक कुल 301 रेक का सफलतापूर्वक लोडिंग

सोलापुर मंडल को 44 करोड़ 20 लाख रुपये का मालभाड़ा राजस्व प्राप्त

प्रमुख गंतव्य स्थल

पाकणी साइडिंग से निम्नलिखित प्रमुख स्थानों तक पेट्रोलियम उत्पादों की आपूर्ति की जा रही है–

हिरियानदुरु, कर्नाटक
मिरज, महाराष्ट्र

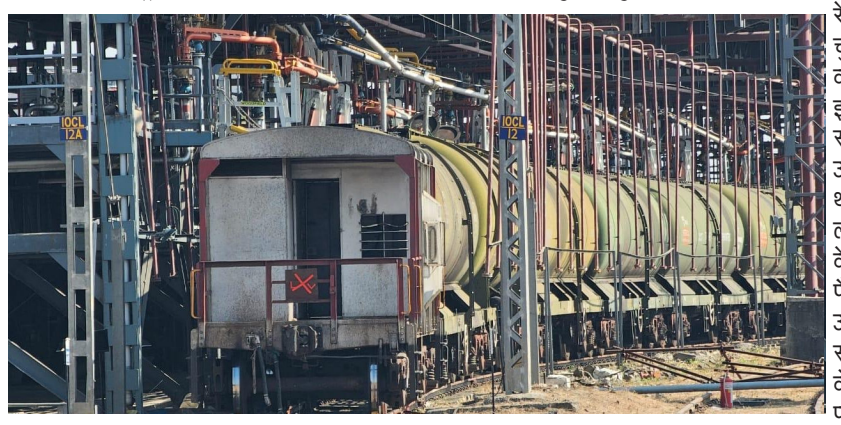

विजयपुरा, कर्नाटक
देसूर, कर्नाटक
नवलूर, कर्नाटक
रामगुंडम, तेलंगाना

यह व्यवस्था बहु-राज्यीय क्षेत्रीय संपर्क को सुदृढ़ रूप से दर्शाती है।

लोड किए जाने वाले उत्पाद

पाकणी साइडिंग पर निम्नलिखित पेट्रोलियम उत्पादों का लोडिंग किया जाता है–

उच्च गति डीज़ल
मोटर स्पिरिट (पेट्रोल)

रेल मार्ग से ईंधन की ढुलाई सुरक्षित, कुशल एवं पर्यावरण के अनुकूल परिवहन सुनिश्चित करती है।

पाकणी साइडिंग का रणनीतिक महत्व

पाकणी साइडिंग आज एक रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण माल परिवहन केंद्र के रूप में उभर चुकी है। यह–

महाराष्ट्र की पहली इंडियन ऑयल निगम लिमिटेड रेक-लोडिंग सुविधा,

भारत में इंडियन ऑयल निगम लिमिटेड की नौवीं विशेष विपणन रेक-लोडिंग साइट, तथा

देशभर में रिफाइनरियों सहित कुल अठारहवीं इंडियन ऑयल निगम लिमिटेड रेक-लोडिंग सुविधा बन चुकी है।

वर्ष 1996 में अधिसूचित इस साइडिंग में पहले सीमित मात्रा में पेट्रोलियम उत्पादों की आवक होती थी। वर्ष 2025 में बाह्य लोडिंग संचालन शुरू होने के बाद यह साइडिंग बड़े पैमाने पर पेट्रोलियम उत्पादों की आवाजाही संभाल रही है और क्षेत्र के एक प्रमुख माल परिवहन केंद्र के रूप में विकसित हो चुकी है।

यह महत्वपूर्ण माल परिवहन व्यवस्था कोयाली (वडोदरा) से पाकणी (सोलापुर) तक फैली 752 किलोमीटर लंबी समर्पित पाइपलाइन द्वारा समर्थित है, जिसे कोयाली-अहमदनगर-सोलापुर पाइपलाइन के नाम से जाना जाता है। वर्ष 2023 में प्रारंभ की गई इस पाइपलाइन की स्थापित क्षमता प्रति वर्ष 50 लाख मीट्रिक टन है। इसका मुख्य पंपिंग केंद्र कोयाली रिफाइनरी के समीप डुमाड में स्थित है तथा महाराष्ट्र के मनमाड, अहमदनगर और सोलापुर में इसके टर्मिनल केंद्र हैं।

कोयाली रिफाइनरी से पाइपलाइन के माध्यम से पेट्रोलियम उत्पादों को पाकणी डिपो तक निर्बाध रूप से पहुंचाया जाता है। इसके बाद रेल रेकों के माध्यम से निकटवर्ती डिपो और उपभोग केंद्रों तक वितरण किया जाता है, जिससे सुरक्षा, दक्षता और विश्वसनीयता सुनिश्चित होती है।

पाकणी साइडिंग पर पेट्रोलियम उत्पादों की लोडिंग में प्राप्त यह उल्लेखनीय उपलब्धि भारतीय रेल और इंडियन ऑयल निगम लिमिटेड के बीच उत्कृष्ट समन्वय का सशक्त उदाहरण है। मध्य रेलवे का सोलापुर मंडल माल परिवहन क्षमता में वृद्धि, राजस्व सृजन तथा महाराष्ट्र, पड़ोसी राज्यों और संपूर्ण देश के आर्थिक विकास में निरंतर योगदान देने के लिए प्रतिबद्ध है।

उप महापौर बने भाजपा के अमर गोविंद राम लुंड

उल्हासनगर मनपा की महापौर बनी शिवसेना पार्टी की अश्विनी कमलेश निकम

महापौर कार्यालय में सांसद डॉक्टर श्रीकांत शिंदे ने मनाया शिवसेना नेता महेश सुखरामानी का जन्मदिन

उल्हासनगर। उल्हासनगर महानगरपालिका की सभागृह में महापौर पद पर निर्विरोध शिवसेना पार्टी की अश्वनी कमलेश निकम चुनी गई। वही भाजपा पार्टी से उपमहापौर के उम्मीदवार अमर गोविंद राम लुंड कोउप महापौर पद के लिए निर्विरोध चुने गए।

खास बात यह रही की महापौर अश्वनी कमलेश निकम और उपमहापौर अमर गोविंद राम लुंड को बधाई देने के लिए कल्याण लोक सभा के सांसद डॉक्टर श्रीकांत शिंदे स्वयं पहुंचे। डॉक्टर श्रीकांत शिंदे ने महापौर अश्वनी कमलेश निकम और उपमहापौर अमर गोविंद लुंड को उनके कार्यालय में कुर्सी पर विराजमान करवाया। मुख्य बात यह रही कि इस मौके पर शिवसेना के वरिष्ठ नगरसेवक महेश सुखरामानी का जन्मदिन महापौर कार्यालय में केक काटकर सबके बीच डॉक्टर श्रीकांत शिंदे द्वारा मनाया गया। इस मौके पर शिवसेना के वरिष्ठ नेता गोपाल लांडगे, जमुनादास पुरस्वानी, प्रकाश माखिजा, शिवसेना शहर प्रमुख राजेंद्र सिंह भुल्लर (महाराज), अभिजीत दरेकर सहित सैकड़ो लोग उपस्थित थे।

बता दे की उल्हासनगर मनपा चुनाव में शिवसेना और भाजपा पार्टी ने अलग-अलग चुनाव लड़ा था जिसमें भाजपा पार्टी को 37 सीट मिली और शिवसेना पार्टी को 36 सीट मिली और बहुजन समाज पार्टी को दो सीट मिली ।कांग्रेस पार्टी को एक सीट मिली और दो अपक्ष चुनकर आए। उल्हासनगर महानगरपालिका में कुल 78 नगर सेवक है शिवसेना और भाजपा के पास दोनों के पास बहुमत नहीं था अंत में वरिष्ठों के हस्तक्षेप करने के बाद दोनों पार्टी की युति हो गई जिसमें शिवसेना पार्टी से अश्विनी कमलेश निकम महापौर और उपमहापुर पद के लिए भाजपा से अमर गोविंद राम लुंड को निर्विरोध चुना गया। जबकि इस मनपा चुनाव में टीओके प्रमुख ओमी कालानी का जलवा बरकरार रहा और उनके गट से शिवसेना पार्टी से अश्वनी कमलेश निकम को महापौर बनाया गया।

लाड़की बहिन योजना का नाम अजित पवार के नाम पर रखे सरकार, एनसीपी विधायक ने की मांग

मुंबई। महाराष्ट्र के एनसीपी विधायक अमोल मिटकरी ने मंगलवार को एक बड़ी मांग रखी। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र सरकार की मुख्यमंत्री लाड़की बहिन योजना का नाम बदलकर दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजित पवार के नाम पर रखा जाना चाहिए। मिटकरी ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि अजितदादा राज्य की महिलाओं के सबसे पसंदीदा भाई थे।

क्या बोले विधायक?

विधायक ने बताया, जब अजित पवार राज्य के दौरों पर निकलते थे, तो उनकी कलाई राखियों से भरी रहती थी। उन्होंने सुझाव दिया कि अगर सरकार इस योजना का नाम 'अजितदादाची

लाड़की बहिन योजना' रखती है, तो यह उनके लिए एक सच्ची श्रद्धांजलि होगी। बता दें कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) के नेता अजित पवार और चार अन्य लोगों की 28 जनवरी को पुणे के बारामती में एक विमान हादसे में मौत हो गई थी।

अजित पवार ने शुरू की थी योजना

अजित पवार ने वित्त मंत्री रहते हुए इस योजना की घोषणा की थी। जुलाई 2024 में शुरू हुई यह योजना 21 से 65 साल की महिलाओं को हर महीने 1,500 रुपये की आर्थिक मदद देती है। यह पैसा सीधे उनके बैंक खातों में भेजा जाता है। माना जाता है कि 2024 के विधानसभा चुनावों में महायुति गठबंधन की जीत में इस योजना ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी।

क्या बोले उप मुख्यमंत्री?

उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने सोमवार को साफ किया कि सरकार इस योजना को बंद नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि यह योजना महिलाओं की बहुत मदद कर रही है। शिंदे ने यह भी भरोसा दिलाया कि सही समय आने पर इस सहायता राशि को 1,500 रुपये से बढ़ाकर 2,100 रुपये कर दिया जाएगा।

स्वच्छ सर्वेक्षण में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए

बृहन्मुंबई को 'स्वच्छ और सुंदर' बनाए रखने हेतु नागरिकों से सहयोग की अपील

मुंबई। केंद्र सरकार ने स्वच्छ सर्वेक्षण 2025-26 के कार्यक्रम की घोषणा की है। इस वर्ष के स्वच्छ सर्वेक्षण में बृहन्मुंबई के उत्कृष्ट प्रदर्शन हेतु, नगर प्रशासन की ओर से अपर नगर आयुक्त (शहर) डॉ. (श्रीमती) अश्विनी जोशी ने समस्त मुंबई महानगर में स्वच्छता बनाए रखने के लिए नागरिकों से सहयोग की अपील की है। साथ ही, बृहन्मुंबई महानगरपालिका के ठोस कचरा प्रबंधन, वर्षा जल निकासी, मलजल संचालन, मुंबई सीवेज डिस्पोज़ल परियोजना, शिक्षा आदि विभागों को बृहन्मुंबई क्षेत्र में स्वच्छ सर्वेक्षण के लिए आपसी समन्वय के साथ प्रभावी उपाय करने के निर्देश दिए गए हैं। डॉ. जोशी ने यह भी निर्देश दिया है कि मूल्यांकन एवं रिपोर्टिंग हेतु आवश्यक समग्र, सटीक और अद्यतन जानकारी संकलित की जाए।

स्वच्छ सर्वेक्षण के संदर्भ में, कल (2 फरवरी 2026) बृहन्मुंबई महानगरपालिका मुख्यालय में एक बैठक आयोजित की गई। इस अवसर पर वे बोल रही थीं। बैठक में उपायुक्त (ठोस कचरा प्रबंधन) श्री किरण दिघावकर सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।

स्वच्छ सर्वेक्षण का आयोजन प्रतिवर्ष केंद्रीय आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा किया जाता है, जिसमें शहरों की स्वच्छता, कचरा प्रबंधन तथा नागरिक सहभागिता का आकलन कर रैंकिंग की जाती है। इस वर्ष स्वच्छ सर्वेक्षण का दसवां वर्ष है। इसमें स्वच्छता, कचरे का पृथक्करण, संग्रहण एवं परिवहन, प्रसंस्करण आदि पहलुओं का मूल्यांकन किया जाता है।

स्वच्छ सर्वेक्षण 2025-26 के लिए केंद्र सरकार ने 'स्वच्छता के लिए नई पहल– हाथ उठाइए, सफाई में सहयोग कीजिए' नामक केंद्रीय अवधारणा प्रस्तुत की है। इसके अंतर्गत स्वच्छता से संबंधित नागरिक प्रतिक्रिया और सत्यापन को अधिक महत्व दिया गया है। तदनुसार, वेबसाइटों और मोबाइल ऐप्स के माध्यम से पूरे वर्ष डिजिटल फीडबैक एकत्र किया जाएगा। खुले में शौच और मूत्र त्याग पर प्रतिबंध के अनुरूप नए मानक निर्धारित किए गए हैं। साथ ही, विद्यालयों में व्यवहार परिवर्तन कार्यक्रमों पर विशेष जोर दिया गया है। इस वर्ष के सर्वेक्षण में तटीय शहरों के लिए अलग मूल्यांकन मानदंड भी लागू किए गए हैं। पर्यटन, विरासत, धार्मिक स्थलों तथा अधिक भीड़-भाड़ वाले सार्वजनिक स्थानों से जुड़ी स्वच्छता कसौटियों पर भी विशेष ध्यान दिया गया है।

इस संदर्भ में बैठक में डॉ. अश्विनी जोशी ने कहा कि ठोस कचरा प्रबंधन विभाग ग्रेटर मुंबई (शहर एवं उपनगर) क्षेत्र में ठोस कचरे के प्रभावी एवं वैज्ञानिक प्रबंधन हेतु निरंतर प्रयास कर रहा है। इन प्रयासों का स्वच्छ सर्वेक्षण में उचित मूल्यांकन सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी कदम आवश्यक हैं। इसके लिए ठोस कचरा प्रबंधन, मलजल संचालन एवं परियोजनाएं, मुंबई सीवेज डिस्पोज़ल परियोजना, वर्षा जल निकासी तथा शिक्षा विभागों को समन्वय के साथ ठोस उपाय करने होंगे। मूल्यांकन एवं रिपोर्टिंग के लिए आवश्यक समग्र, सटीक और अद्यतन जानकारी एकत्र की जानी चाहिए। साथ ही, इस वर्ष नागरिक सहभागिता और विद्यालय-आधारित गतिविधियों पर विशेष जोर देकर नागरिकों एवं विद्यार्थियों की भागीदारी सुनिश्चित की जानी चाहिए। विद्यार्थियों में कम उम्र से स्वच्छता की आदतें विकसित होने पर समाज स्तर पर दीर्घकालिक और टिकाऊ व्यवहार परिवर्तन होता है, जो शहरी स्वच्छता में सहायक सिद्ध होता है। नागरिकों से भी स्वच्छता को प्राथमिकता देने और महानगरपालिका के साथ सहयोग करने की अपील की गई।

सम्पादकीय

बजट में दिख रहा विकसित भारत का रोडमैप और आर्थिक संतुलन का समायोजन

अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर जिस तरह की वैश्विक चुनौतियां खड़ी हो रही हैं, नए समीकरण तैयार हो रहे हैं, उसमें सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए ऐसा बजट पेश करना एक चुनौती भरा काम है, जो संतुलित हो और जिसमें लोकलुभावन प्रस्तावों से बचने की कोशिश की जाए। सरकार का मानना है कि देश अब तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के लिए दृढ़ संकल्पित है और 2026-27 का आम बजट भविष्य को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया।

किसी भी बजट की उपादेयता इससे साबित होती है कि वह देश की आर्थिक मजबूती में कितना सहायक साबित हुआ और उसका आम जनता के जीवन पर क्या असर पड़ा। इस लिहाज से देखें तो रविवार को पेश बजट को व्यापार और पूंजी के क्षेत्र में बढ़ती जरूरतों के साथ-साथ भारत को अंतरराष्ट्रीय बाजारों के साथ तालमेल बिठाते हुए अधिक निर्यात और स्थिर दीर्घकालिक निवेश को आकर्षित करने वाला कहा जा सकता है।

यों इस बजट को गरीबों, किसानों, युवाओं और महिलाओं के हितों के संदर्भ में उम्मीद जगाने वाले प्रयास के तौर पर देखा जा सकता है, मगर कोई लोकलुभावन घोषणाओं से बचते हुए यथार्थवादी दृष्टिकोण पर जोर दिया गया। युवा वर्ग के सशक्तीकरण के मकसद से शिक्षा क्षेत्र में लगभग 1.35 लाख करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान किया गया है। इसके तहत पचास नए आइआइटी और मेडिकल कालेज खोले जाने की बात कही गई है।

साथ ही कौशल के विकास के उद्देश्य से 'स्किल इंडिया' कार्यक्रम को जमीन पर उतारने के लिए दो लाख करोड़ रुपए और प्रशिक्षु योजना से पांच करोड़ युवाओं को छात्रवृत्ति की व्यवस्था की जाएगी। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों यानी एमएसएमई के क्षेत्र में मदद के साथ ही रोजगार केंद्रित विकास को प्रमुखता दी जाएगी। दरअसल, देश में आज भी विकास के सारे सवाल बढ़ती बेरोजगारी के सामने चुनौती की तरह लगने लगते हैं।

इसके मद्देनजर बजट में बेरोजगारी दर को आठ फीसद से नीचे लाने का संकल्प जाहिर किया गया है। मगर सारे निवेश और कार्यक्रम की कामयाबी इस बात पर निर्भर करेगी कि शहरों-महानगरों के साथ-साथ ग्रामीण इलाकों में भी रोजगार के कितने अवसर सृजित हुए और उसमें हिस्सेदारी करने के लिए कौशल की कसौटी पर कितनी प्रशिक्षित युवा आबादी तैयार हुई।

इसी तरह, लक्ष्मी वंदना योजना को विस्तार दिया गया है और स्वरोजगार ऋण के नियम शिथिल किए गए, ताकि महिला सशक्तीकरण की दिशा में ठोस नतीजे हासिल किए जा सकें। मगर यह देखने की बात होगी कि इससे जमीनी स्तर पर लैंगिक समानता की स्थितियों को सशक्त बनाने में कितनी मदद मिलेगी। पांच 'विश्वविद्यालय शहर' के निर्माण, डिजिटल नालेज ग्रिड की स्थापना और देश के प्रत्येक जिले में महिला छात्रावास खोलना युवा सशक्तीकरण की राह को मजबूती दे सकती है।

अर्थव्यवस्था को मजबूती देने के मकसद से विनिर्माण, पर्यटन, दुर्लभ खनिजों के खनन और नई बुनियादी ढांचा परियोजना को बढ़ावा देने का प्रस्ताव किया गया है। बदलते दौर में तकनीक और नवाचार के क्षेत्र में मजबूती के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता केंद्र की स्थापना डिजिटल इंडिया के सपने को पूरा करने में मददगार होगी, लेकिन यह ध्यान रखने की जरूरत होगी कि गरीब और अमीर आबादी के बीच डिजिटल विभाजन को पाटा जा सके, क्योंकि आने वाले वर्षों में अगर देश को दुनिया में एक अग्रणी अर्थव्यवस्था बनना है, तो उसमें समावेशी विकास के सिद्धांत को वास्तव में जमीन पर उतारना होगा।

ममता के बंगाल में कितने लोग जिंदा जलकर मर गए? आनंदपुर के अग्नि कांड की कहानी पर मीडिया में इतना सन्नाटा क्यों

चमकदार होर्डिंग्स, ललचाते हुए एड्स और सोशल मीडिया ट्रेंड से ब्रांड चमकाने वाली कंपनियों की हकीकत अक्सर तभी बाहर आती है जब कोई हादसा होता है। दो रोज पहले की बात है यानी कि 28 जनवरी की सुबह करीब 3:00 बजे कोलकाता के आनंदपुर इलाके में रूबी क्रॉसिंग के पास अचानक एक गोदाम में आग लग गई। कुछ ही मिनटों में यह आग दो बड़े गोदामों तक फैल गई। एक पुष्पांजल डेकोरेटर्स का गोडाउन और दूसरा वाओ मोमो कंपनी का लीज़ पर लिया हुआ वेयर हाउस। वाओ मोमो एक फास्ट फूड चेन है जिसके आउटलेट आप फूड डिलीवरी एप्स में देख सकते हैं। बंगाल का अग्निकांड इतना भयानक था कि अभी भी शवों की पहचान संभव नहीं हो सकी है। अधिकारियों के अनुसार, शव बहुत ही बुरी तरह जल चुके हैं। सिर्फ बड़ी हड्डियां और खोपड़ियां ही बची है। टीओआई की रिपोर्ट के मुताबिक, पुलिस और राहत टीमें अब इन खोपड़ियों और हड्डियों को गिनकर मृतकों की संख्या का पता लगाने की कोशिश कर रही हैं। यह आग 26 जनवरी को पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले में दै! मोमो के गोदाम में लगी। आग लगने की वजहें अभी साफ नहीं हो सकी हैं। राहत दल मलबे और खंडहर में खोज कर रहे हैं ताकि और शव मिल सकें। आग में मृतकों की संख्या बढ़कर 21 पहुंच गई है। क्षतिग्रस्त इमारतों से 13 और शव बरामद किए गए। पुलिस के मुताबिक, 28 लोग अब भी लापता हैं। आशंका है कि मृतकों की संख्या और बढ़ सकती हैं। यह हादसा सिर्फ एक आग की घटना नहीं है बल्कि इसे कोलकाता के इतिहास की तीसरी सबसे बड़ी फायर ट्रेजडी माना जा रहा है। इससे पहले 2011 में

एएमआरआई हॉस्पिटल में आग लग गई थी जिसमें 89 लोगों की मौत हो गई थी और 2010 में स्टीफन कोर्ट में भी आग लग गई थी जिसमें 43 लोगों की जान गई थी। उन दोनों घटनाओं की तरह आनंदपुर की यह घटना भी कई गंभीर सवाल खड़े करती है। खासकर सुरक्षा, लापरवाही और सिस्टम की नाकामी को लेकर।

आनंदापुर के नजीराबाद इलाके में स्थित यह दोनों गोदाम एक दूसरे से बेहद सटे हुए हैं। उस वक्त दोनों गोदामों में मिलाकर करीब 37 लोग मौजूद थे। कुछ लोग काम कर रहे थे तो कुछ सो रहे थे। शुरुआती जांच में सामने आया कि सबसे पहले आग पुष्पांजलि डेकोरेटर्स के गोडाउन में लगी। हालांकि आग लगने की वजह नहीं पता चल पाई है। लेकिन जिस तरह का सामान वहां पर रखा था उसने आग को और भी ज्यादा भयानक बना दिया। पुष्पांजलि डेकोरेटर्स के गोदाम में प्लास्टिक के फूल थे। लकड़ी, कपड़े, पेंट, फर्नीचर और कई तरह के केमिकल्स भी थे। यानी कि बेहद ज्वलनशील सामग्री। आग लगते ही इन चीजों ने चिंगारी को कुछ ही पलों में भीषण आग में बदल दिया। तेज गर्मी और धुएं के कारण लोगों को बाहर निकलने का मौका तक नहीं मिला। कुछ ही देर में यह आग बगल के वाओ मोमो के वेयर हाउस तक पहुंच गई। वहां भी पैकेजिंग मटेरियल, प्लास्टिक, कोल्ड ड्रिंक्स की बोतलें और स्टोरेज का सामान था। दोनों गोदामों में मौजूद ज्वलनशील चीजों के कारण लगभग 30 से 35, 000 स्क्वायर फीट का पूरा परिसर टिंडर बॉक्स में बदल गया।

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार इस भीषण आग में सिर्फ तीन लोग जिंदा बच पाए और ये तीनों वाओ मोमो के वेयर हाउस में काम करने वाले कर्मचारी बताए जा रहे हैं। बाकी लोग जो पुष्पांजलि डेकोरेटर्स के गोदाउन में थे आग और धुएं के बीच फंस गए। कई लोग बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उसी दौरान वह बेहोश हो गए तो कईयों को रास्ता ही नहीं मिला। फरेंसिक विशेषज्ञों ने बताया कि जले हुए शवों से डीएनए सैंपल लेना मुश्किल हो सकता है। वजह यह है कि शव इतनी बुरी तरह जले हैं कि शरीर के अंदर मौजूद जेनेटिक मटीरियल खराब या नष्ट हो सकता है। हालांकि विशेषज्ञों का कहना है कि शरीर की कुछ लंबी हड्डियां और गर्मी को ज्यादा सहन कर लेते है। इसलिए सावधानी और मेहनत से डीएनए सैंपल जुटाना संभव हो सकता है। उन्होंने बताया कि बहुत ज्यादा जले हुए शवों से डीएनए लेना चुनौतीपूर्ण जरूर है, लंबी हड्डियां और दांत अक्सर मिल जाते हैं, क्योंकि ये गर्मी से कम प्रभावित होते हैं। मेडिकल कॉलेज के फरेंसिक विभाग के प्रमुख का कहना है कि जले हुए शवों से मिली हड्डियां और दांत डीएनए जांच के लिए भरोसेमंद होते हैं। दांतों की ऊपरी परत (इनेमल) अंदर के गूदे को सुरक्षित रखती है, जिससे डीएनए बचा रहता है। वहीं, लंबी हड्डियां अपनी मजबूत बनावट के कारण तेज और लंबे समय तक की गर्मी को सहन कर लेती हैं।

पुलिस ने ने बताया कि मृतकों की पहचान के लिए डीएनए टेस्ट जरूरी है। अधिकारी ने कहा कि अलग-अलग बॉडी के हिस्सों के डीएनए खोपड़ियों से मिलाए जाएंगे। इससे पता लग सकेगा कि वे हिस्से किसी एक ही शख्स के हैं या अलग-अलग व्यक्ति के हैं। घटना स्थल पर मौजूद पुलिस ने बताया कि आग के समय कुछ कर्मचारी सामने की ओर भागने की कोशिश कर रहे थे, जबकि कुछ पीछे की ओर भागे, लेकिन कोई नहीं बच सका। फरेंसिक एक्सपर्ट खोपड़ियों और हड्डियों से डीएनए के सैंपल इकट्ठा कर रहे हैं ताकि मृतकों की पहचान हो सके और उनके परिवार को जानकारी दी जा सके।

फॉरेंसिक और पुलिस जांच में भी यह साफ हो गया कि आग बगल के गोदाम से आई थी। हमारा वेयर हाउस किराए पर था और मकान मालिक का ही वो डेकोरेटर गोदाम था जहां से आग शुरू हुई। हालांकि कंपनी अपनी सफाई दे रही है लेकिन सवाल वही है कि क्या इतने बड़े ब्रांड को ऐसे असुरक्षित परिसर में अपना सामान स्टोर करना चाहिए था जहां फायर सेफ्टी का कोई ऑडिट नहीं हुआ था। लाइसेंस और एनओसी सिर्फ कागजों पर लेकर काम चलाया जा रहा था। अभी 13 लोगों की जान चली गई है। अगर अभी इंडस्ट्रियल इलाकों में फायर सेफ्टी को गंभीरता से नहीं लिया गया तो अगली बार फिर किसी ब्रांड के पीछे इंसानी जान की बलि चढ़ सकती है। वहीं विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी और बीजेपी के अन्य नेताओ के प्रस्तावित दौरे से पहले अधिकारियों ने इलाके में कर्फ्यू लागू कर आम लोगो की आवाजाही बैन कर दी है। शुभेंदु अधिकारी ने घटनास्थल पर जाने और पास के एक मंदिर से वहा तक मार्च निकालने की अनुमति के लिए कलकत्ता हाई कोर्ट कोर्ट का रुख किया है। सूत्र के मुताबिक मामले की सुनवाई जस्टिस शुभ्रा घोष कर सकती है।

पश्चिम बंगाल के यूट्यूबर पाथ चटर्जी का दावा है कि 50 लोग से ज्यादा मरे हैं। सोचिए अगर यही हाल देश के किसी दूसरे राज्य में इस तरह की घटना होती तो क्या रिएक्शन होता? अब तक हंगामा हो चुका होता। मान लीजिए कि आपके उत्तर प्रदेश में 50 लोग जिंदा जलकर मर गए। क्या हाल होता। हालांकि पश्चिम बंगाल सरकार के आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार 23 लाशें बरामद की जा चुकी है। बाकी 22 या 23 का कोई पता नहीं। अभी उनकी उनको ढूंढने की कोशिश जारी है।

वाओ मोमो ने एक ऑफिशियल प्रेस स्टेटमेंट जारी किया है। उस स्टेटमेंट में वाओ मोमो नाम की कंपनी द्वारा यह कहा गया है कि हमारे तीन वैलुएबल एंप्लई की डेथ हो गई है। हम उन तीनों को 10 ?1 लाख मुआवजा देंगे और लाइफ टाइम सैलरी देंगे और उनके जो बच्चे हैं उनके पढ़ने का इंतजाम करेंगे। हम सुनते थे बहुत पहले दिल्ली में उपहार सिनेमा हॉल में आग लगी थी और वह पूरा प्रकरण बहुत उस कई काफी दिनों तक मीडिया में छाया रहा था।

विदेशों में बस गए थे, फिर 100 साल पुराने घर ने लौटा दीं जड़ें, कराईकुडी से परिवार और परंपरा की वापसी

देश भर में लोगों का गांव से शहरों और शहरों से विदेश पलायन करने की प्रवृत्ति बढ़ रही है। मुख्य रूप से रोजगार और शिक्षा जैसे कारणों से एक बार गांव-घर छूटता है, फिर लौटना ही नहीं हो पाता। कामकाजी आपाधापी एवं बदलती जीवनशैली पर्व-त्योहारों और सामाजिक-पारिवारिक आयोजनों में भी नियमित मेलजोल का अवसर नहीं देती। हाल ही में तमिलनाडु के शिवगंगा जिले के कराईकुडी में अपनी जड़ों से जुड़े रहने की एक घटना चर्चा में आई। यहां एक ही परिवार की पीढ़ियों ने गांव-घर लौटने का मन बनाया। दुनिया के अलग-अलग हिस्से में जा बसे इन लोगों ने व्यस्तता और जीवन की आपाधापी को भूल कर एक-दूजे से मिलने का मार्ग निकाला और अपने पैतृक आवास पर पहुंच गए। बिखरते रिश्तों के इस दौर में यह प्रयास पीढ़ियों को जोड़ने की एक प्रेरणादायी घटना है।

दरअसल, शिवगंगा जिले के कराईकुडी में एक एकड़ में फैले तीस कमरों वाले पैतृक घर की सौवीं वर्षगांठ के अवसर पर देश-विदेश में बसे परिवार के तीन सौ से अधिक सदस्य इकट्ठा हुए। इस आयोजन में दुबई, मलेशिया और कनाडा में बसे सगे-सबंधियों के कुल पैंसठ परिवारों ने भाग लिया। इससे पहले वर्ष 2016 में परिवार के कुछ सदस्य एक कार्यक्रम के लिए इस घर में आए थे।

इस परिवार के सदस्यों के लिए यह सुखद एहसास है कि उनका पैतृक घर एक बार फिर संबंधों को मजबूती देने का माध्यम बना। यह पैतृक घर केवल ईंट-पत्थर की संरचना नहीं, बल्कि परंपरा, संस्कृति और पारिवारिक एकता का प्रतीक बन गया। इसमें दोराय नहीं कि देश-विदेश में जा बसी एक परिवार की पीढ़ियों के बीच भौगोलिक दूरी ही मन के फासले का कारण भी बन जाती है।

परिवार के सदस्यों का अलग-अलग देशों या शहरों में रहना कभी समय क्षेत्र का अंतर तो कभी बदलती सोच और सरोकारी भाव-बर्ताव के कारण नियमित रूप से संवाद करने में बाधा बन जाते हैं। एक साथ कोई आयोजन करना तो बिल्कुल असंभव-सा ही लगता है। समय के साथ प्राथमिकताएं भी बदलती हैं और कभी बहुत मान से बनाए गए घर पारिवारिक सदस्यों की बाट जोहते रह जाते हैं।

वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो भारतीय प्रवासी दुनिया का सबसे बड़ा प्रवासी समुदाय है। मई 2024 के आंकड़ों के अनुसार, देश के लगभग 3.54 करोड़ लोग प्रवासी समुदाय में शामिल हैं। कमोबेश हर प्रांत के गांव-कस्बे से लेकर शहरों तक के बाशिंदे दूसरे देशों में अपना ठिकाना बना चुके हैं। एक समय बाद पैतृक घरों को देखने-संभालने भी कोई नहीं आता। ऐसे में कराईकुडी का यह वाकया अपनों से जुड़े रहने के सार्थक प्रयास का उदाहरण है। विशेषकर बदलती पारिवारिक परिस्थितियों में यह कोई साधारण प्रसंग भर नहीं।

देखने में आ रहा है कि हम संयुक्त परिवार से एकल परिवार तक आ पहुंचे हैं। घर-परिवार के इस नए परिवेश में अब एकल परिजनों के बीच अलगाव ही नहीं, बल्कि आपराधिक आंकड़े बढ़ रहे हैं। सहिष्णु व्यवहार करीबी संबंधों से भी नदारद है। विरासत को सहेजने वाली भावी पीढ़ियों में विरासत को लेकर ही टकराव की स्थितियां बन रही हैं। पारिवारिक मुकदमों की संख्या लगातार बढ़ रही है। कभी साथ बैठकर समस्याएं सुलझाने वाले पारिवारिक ढांचे में अब आपसी विवादों के लाखों मामले अदालतों में लंबित हैं।

इनमें अधिकतर मुकदमे तलाक, भरण-पोषण, संपत्ति और संतान की अभिरक्षा से संबंधित होते हैं। यानी 'वसुधैव कुटुम्बकम' की बात करने वाले देश में भी लोग अपने ही परिवार के सदस्यों के साथ नहीं रह पा रहे हैं। वैश्विक स्तर पर सार्वभौमिक भाईचारे का संदेश देने वाला भारतीय समाज अब अपने घरों में पारिवारिक कलह और संपत्ति के मुकदमों में उलझा हुआ है, जो पुरानी मान्यताओं और आधुनिक वास्तविकताओं के बीच अंतर को दिखाता है।

देश में लोग विश्व को एक परिवार मानने वाले सिद्धांत का उल्लेख तो करते हैं, लेकिन अपने करीबी रिश्तेदारों के साथ भी एकजुट नहीं रह पा रहे हैं। 'परिवार' की मूल अवधारणा ही समाप्त होती जा रही है और एक व्यक्ति-एक परिवार की प्रवृत्ति बढ़ रही है। यह स्थिति बढ़ती पारिवारिक टूटन से अकेले छूटते बच्चों से लेकर प्रताड़ित होते बुजुर्गों और युवा जोड़ों के संबंधों में दरार के दुखद पहलुओं को सामने रखती है। ऐसे में यह कहना गलत नहीं होगा कि विदेश में जा बसे लोगों का यों पारिवारिक मेलजोल का मार्ग निकालना हमारी वास्तविक मान्यताओं की ओर लौटने के समान है।

समाज में पारिवारिक व्यवस्था का छिन्न-भिन्न होना पीड़ादायक तो है ही, एक-दूसरे से पूरी तरह कट जाना और भी दुखद है। बीते कुछ वर्षों में पश्चिमी देशों जैसी पारिवारिक व्यवस्था ने भारतीय समाज में भी जड़ें जमा ली हैं। समझना आवश्यक है कि पश्चिमी देशों के परिवारों में भावनात्मक जुड़ाव और आत्मीयता के बजाय व्यक्तिगत स्वतंत्रता और आत्मनिर्भरता के भाव को अधिक महत्त्व दिया जाता है। संबंधों के निर्वहन को लेकर वहां बहुत सीमित, स्पष्ट और व्यावहारिक सोच रही है।

वहीं, भारतीय समाज में परिवार की पीढ़ियों से गहरा लगाव हुआ करता था। शहरीकरण, पलायन और व्यक्तिगत सोच के कारण अब यह हाव-भाव बदला है। घरेलू संबंधों से जुड़ी संवेदनाओं का स्थान व्यक्तिगत सरोकारों ने ले लिया है। यह तथ्य विचारणीय है कि परिवार को वैश्विक समुदाय का लघु रूप कहा जाता है। एक ऐसी इकाई, जो स्नेह और सहभागिता की मानवीय समझ को आधार देती है और संवेदनाओं को पोषित करने वाला परिवेश बनाती है।

भारतीय संस्कृति में तो परिवार को आर्थिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक परेशानियों के दौर में संबल के तौर पर देखा जाता है। घर-परिवार से मिलने वाला सुख-समर्पण का भाव ही हमें समाज और देश से जोड़ता है। यही राष्ट्र के प्रति दायित्वबोध का भाव भी जगाता है। पारिवारिक खुशहाली राष्ट्र निर्माण में भी महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसलिए बदलती परिस्थितियों में भी तयशुदा प्रयासों के साथ लोगों को परिवार से जुड़ाव रखने के मार्ग तलाशने होंगे। जब जुड़ाव का मन बना लिया जाए, तो जुड़े रहना कठिन नहीं है।

नारी देह, नारी अधिकार : माहवारी पर सुप्रीम कोर्ट की दृष्टि

भारत के सामाजिक विकास की यात्रा में महिलाओं की स्थिति हमेशा एक निर्णायक कसौटी रही है। किसी भी राष्ट्र की प्रगति केवल आर्थिक आँकड़ों या बुनियादी ढाँचे से नहीं मापी जाती, बल्कि इस बात से आँकी जाती है कि वह अपने समाज के आधे हिस्से-महिलाओं को कितना सम्मान, सुरक्षा और समान अवसर देता है। इसी सन्दर्भ में सुप्रीम कोर्ट ने 30 जनवरी 2026 को एक ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए मासिक धर्म स्वास्थ्य को संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत मौलिक अधिकार घोषित किया है। कोर्ट ने देश के सभी सरकारी और निजी स्कूलों में छात्राओं को मुफ्त और सुरक्षित बायोडिग्रेडेबल सैनिटरी पैड उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। मासिक धर्म स्वच्छता को गरिमा और स्वास्थ्य के साथ जीने के मौलिक अधिकार का हिस्सा माना गया है। स्कूलों में साफ-सुथरे शौचालय और पानी की उचित व्यवस्था अनिवार्य है। इस निर्णय का उद्देश्य पीरियड्स के कारण लड़कियों की पढ़ाई में होने वाली बाधा को रोकना और उन्हें शर्मिंदगी से बचाना है। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला महिलाओं और विशेषकर स्कूली लड़कियों की माहवारी से जुड़ी समस्या पर दिया गया ऐतिहासिक निर्णय, एक सशक्त और दूरदर्शी कदम है। कर्नाटक सरकार ने सरकारी और प्राइवेट क्षेत्र की महिला कर्मचारियों के लिए 12 दिन का सवेतन पीरियड लीव नीति को भी मंजूरी दी है। यह फैसला स्कूलों में मासिक धर्म प्रबंधन की कमी को दूर करने और छात्राओं के सम्मानजनक शिक्षा के अधिकार की सुरक्षा के लिए एक बड़ा कदम है। स्कूलों में अनिवार्य रूप से सेनेटरी पैड उपलब्ध कराने का निर्देश केवल एक प्रशासनिक आदेश नहीं, बल्कि सामाजिक चेतना को झकझोरने वाला संदेश है कि अब माहवारी जैसे विषय को चुप्पी, लज्जा और अज्ञान के अंधेरे में नहीं छोड़ा जा सकता।

विडंबना यह है कि जिस माहवारी को प्रकृति ने जीवन-चक्र का अनिवार्य और स्वस्थ हिस्सा बनाया है, उसे हमारे समाज ने सदियों से अपवित्रता, अशुद्धता और वर्जना से जोड़ दिया। परिणामस्वरूप, करोड़ों महिलाएँ और किशोरियाँ न केवल शारीरिक कष्ट झेलती हैं, बल्कि मानसिक पीड़ा, हीनभावना और सामाजिक बहिष्कार का भी सामना करती हैं। आज भी भारत के अनेक हिस्सों में माहवारी के दौरान लड़कियों को रसोई, पूजा, स्कूल और सामाजिक गतिविधियों से दूर रखा जाता है। यह व्यवहार केवल परंपरा नहीं, बल्कि स्त्री की गरिमा और अधिकारों का प्रत्यक्ष हनन है। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी कि 'माहवारी स्वच्छता की कमी महिलाओं की गरिमा को ठेस पहुँचाती है' इस पूरे विमर्श को एक नई संवैधानिक दृष्टि देती है। संविधान द्वारा प्रदत्त जीवन और गरिमा के अधिकार को यदि वास्तविक अर्थों में लागू करना है, तो महिलाओं के स्वास्थ्य से जुड़े मुद्दों को प्राथमिकता देनी ही होगी। स्कूलों में सेनेटरी पैड की अनिवार्य व्यवस्था इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि कई अध्ययन बताते हैं कि स्वच्छता सुविधाओं के अभाव में बड़ी संख्या में लड़कियाँ किशोरावस्था में ही पढ़ाई छोड़ने को मजबूर हो जाती हैं। यह केवल शिक्षा का नुकसान नहीं, बल्कि पूरे समाज की बौद्धिक और नैतिक पूंजी की क्षति है।

न्यायालय ने शिक्षा को एक 'मल्टीप्लायर राइट' बताया जो अन्य मानवाधिकारों के उपयोग की कुंजी है। न्यायालय ने इस निर्णय को केवल आदर्शों की घोषणा तक सीमित नहीं रखा, बल्कि उसे जमीन पर उतारने के लिए स्पष्ट और व्यावहारिक निर्देश दिए। कक्षा 6 से 12 तक की सभी छात्राओं को मुफ्त, उच्च गुणवत्ता वाले ऑक्सो-बायोडिग्रेडेबल सैनिटरी पैड उपलब्ध कराने का आदेश दिया गया। इन पैड्स का एएसटीएम डी-6954 जैसे अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप होना अनिवार्य किया गया, ताकि स्वास्थ्य सुरक्षा के साथ पर्यावरण संरक्षण भी सुनिश्चित हो सके। साथ ही, पैड्स की सहज, सुरक्षित और गोपनीय उपलब्धता के लिए स्कूलों में वेंडिंग मशीन या नामित अधिकारी की व्यवस्था तय की गई, जिससे छात्राओं की झिझक और असहजता पूरी तरह दूर की जा सके। इसके साथ ही स्कूलों में 'मासिक धर्म स्वास्थ्य प्रबंधन कॉर्नर' स्थापित करने का आदेश दिया गया, जहाँ अतिरिक्त यूनिफॉर्म, स्पेयर इनरवियर, डिस्पोजेबल बैग और आवश्यक स्वच्छता सामग्री उपलब्ध होगी। दिव्यांग छात्राओं के लिए व्हीलचेयर-अनुकूल शौचालय और सहायक उपकरण जैसी विशेष सुविधाएँ अनिवार्य की गईं। निजी स्कूलों द्वारा निर्देशों की अवहेलना पर मान्यता रद्द करने का प्रावधान रखकर जवाबदेही को मजबूत किया गया, ताकि यह फैसला केवल कागजों तक सीमित न रहे, बल्कि हर छात्रा के जीवन में वास्तविक बदलाव ला सके।

माहवारी स्वच्छता केवल पैड उपलब्ध कराने तक सीमित विषय नहीं है। इसके साथ जुड़ा है स्वच्छ शौचालय, साफ पानी, कचरा निस्तारण की व्यवस्था और सबसे महत्वपूर्णकृसही जानकारी। आज भी अनेक लड़कियाँ पहली माहवारी के समय भय, भ्रम और अपराधबोध से घिर जाती हैं क्योंकि उन्हें पहले से कोई वैज्ञानिक और संवेदनशील जानकारी नहीं दी जाती। स्कूलों में यदि स्वास्थ्य शिक्षा को गंभीरता से लागू किया जाए और माहवारी को एक सामान्य जैविक प्रक्रिया के रूप में समझाया जाए, तो यह डर और संकोच स्वतः समाप्त हो सकता है। यह भी सच है कि माहवारी को लेकर समाज में फैली चुप्पी पुरुषों की भूमिका को भी प्रश्नों के घेरे में लाती है। जब तक पुरुष-चाहे वे पिता हों, शिक्षक हों, प्रशासक हों या नीति-निर्माता, इस विषय को केवल 'महिलाओं का मामला' मानकर किनारे करते रहेंगे, तब तक वास्तविक बदलाव संभव नहीं। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश इस दृष्टि से भी महत्वपूर्ण हैं कि उन्होंने समाज और खासकर पुरुषों को संवेदनशील बनने का अवसर दिया है। जागरूकता का अर्थ केवल महिलाओं को सशक्त बनाना नहीं, बल्कि पुरुषों को सहृदय और जिम्मेदार बनाना भी है।

ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों में माहवारी से जुड़ी चुनौतियाँ और भी गंभीर हैं। वहाँ आज भी कपड़े, राख या अस्वच्छ साधनों का उपयोग आम है, जिससे संक्रमण और दीर्घकालिक स्वास्थ्य समस्याएँ उत्पन्न होती हैं। सरकारी योजनाएँ और गैर-सरकारी प्रयास मौजूद हैं, परंतु उनकी पहुँच और प्रभावशीलता अभी भी सीमित है। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय यदि ईमानदारी से लागू होता है, तो यह नीति और जमीन के बीच की खाई को पाटने में सहायक हो सकता है। यह भी विचारणीय है कि माहवारी स्वच्छता को केवल कल्याणकारी योजना न मानकर महिला अधिकारों के व्यापक ढाँचे में देखा जाए। स्वास्थ्य का अधिकार, शिक्षा का अधिकार और समानता का अधिकार-तीनों इस विषय से सीधे जुड़े हैं। एक ऐसी व्यवस्था जहाँ लड़की केवल इसलिए स्कूल न जा सके क्योंकि उसके पास सेनेटरी पैड नहीं हैं, वह व्यवस्था संविधान की आत्मा के विपरीत है। इसलिए यह फैसला सामाजिक न्याय की अवधारणा को भी मजबूती देता है।

आज भारत 'नए प्रवेश' के साथ आगे बढ़ने की बात करता है-डिजिटल इंडिया, आत्मनिर्भर भारत और विश्वगुरु बनने की आकांक्षा रखता है। किंतु यदि इस विकास की गाथा में महिलाओं की बुनियादी आवश्यकताएँ और सम्मान शामिल नहीं हैं, तो यह प्रगति खोखली सिद्ध होगी। वास्तविक विकास वही है जो सबसे कमजोर वर्ग की पीड़ा को समझे और उसे दूर करने का साहस रखे। माहवारी जैसे विषय पर खुली चर्चा उसी साहस का प्रतीक है। समाज में जन-जागृति लाना इस पूरी प्रक्रिया का सबसे महत्वपूर्ण चरण है। कानून और आदेश दिशा दिखा सकते हैं, परंतु मानसिकता बदलना समाज की सामूहिक जिम्मेदारी है। मीडिया, शिक्षा संस्थान, धार्मिक और सामाजिक संगठन सभी को मिलकर माहवारी को लेकर फैली भ्रांतियों को तोड़ना होगा। इसे शर्म का नहीं, स्वास्थ्य और स्वाभिमान का विषय बनाना होगा। अंततः, सुप्रीम कोर्ट का यह निर्णय एक शुरुआत है, मंज़िल नहीं। इसकी सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि हम इसे कितनी ईमानदारी से लागू करते हैं और कितनी संवेदनशीलता से अपनाते हैं। यदि हम सचमुच एक समावेशी, न्यायपूर्ण और मानवीय भारत का निर्माण चाहते हैं, सबका साथ, सबका विकास एवं सबका विश्वास के साथ नया भारत बनाना चाहते हैं तो महिलाओं के स्वास्थ्य और अधिकारों को विकास के केंद्र में रखना ही होगा। माहवारी से मुक्ति का अर्थ केवल शारीरिक सुविधा नहीं, बल्कि मानसिक, सामाजिक और संवैधानिक स्वतंत्रता है। यही स्वतंत्रता किसी भी सभ्य और प्रगतिशील समाज की पहचान होती है।

तहसील में नियमों की खुलेआम उड़ रही धज्जियां प्राइवेट कर्मचारियों की मनमानी से किसान परेशान

मंत्र भारत संवाददाता

कौशाम्बी। जनपद की सिराथू तहसील में नियम-कानूनों की खुलेआम धज्जियां उड़ाए जाने का मामला सामने आ रहा है। सूत्रों के अनुसार तहसील परिसर में तैनात प्राइवेट कर्मचारियों द्वारा काश्तकारों से जमकर अवैध वसूली की जा रही है, जिससे आम जनता में भारी नाराजगी है। सूत्र बताते हैं कि तहसील के भीतर कई अधिकारियों के कक्षों में प्राइवेट कर्मचारियों की तैनाती कराई गई है, जो सरकारी कार्यों के नाम पर किसानों और फरियादियों से पैसे वसूल रहे हैं। बिना रकम दिए काम न होने की शिकायतें लगातार सामने आ रही हैं।

ज्ञात हो कि सूत्रों की मानें तो यह अवैध वसूली केवल निचले स्तर तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें कुछ अधिकारियों की संलिप्तता की भी आशंका जताई जा रही है। काश्तकारों का आरोप है कि खतौनी, पैमाइश, नामांतरण और अन्य राजस्व संबंधी कार्यों के लिए उनसे तय रकम से अधिक धन की मांग की जाती है।स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि तहसील प्रशासन द्वारा समय रहते इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच नहीं कराई गई तो किसानों का प्रशासन से भरोसा पूरी तरह उठ जाएगा। अब सवाल यह है कि जिला प्रशासन इस गंभीर आरोप पर क्या संज्ञान लेता है और दोषियों पर कब कार्रवाई होती है।

जिलाधिकारी ने की जल निगम, सिंचाई एवं नलकूप विभाग के कार्यों की विस्तृत समीक्षा

मंत्र भारत संवाददाता

कौशाम्बी। जिलाधिकारी डॉ. अमित पाल ने आज एन.आई.सी. सभागार में जल निगम, सिंचाई एवं नलकूप विभाग के कार्यों की विस्तृत समीक्षा की।

ज्ञात हो कि बैठक में अधिशासी अभियंता जल निगम ने बताया कि जल-जीवन मिशन के अन्तर्गत लक्ष्य 353 ट्यूबवेल के सापेक्ष 348 की प्रगति हुई है, लक्ष्य 309 ओवरहेड टैंक के सापेक्ष 223 ओवरहेड टैंक का निर्माण कार्य पूर्ण, 218263 गृह संयोजन लक्ष्य के सापेक्ष 203576 गृह संयोजन एवं 4042 किमी0 पाइपलाइन लक्ष्य के सापेक्ष 3507 किमी0 पाइप लाइन बिछाने का कार्य पूर्ण हो चुका है।

जिलाधिकारी ने ओवरहेड टैंक का निर्माण कार्य, पाइपलाइन बिछाने का कार्य, गृह संयोजन एवं पाइपलाइन बिछाने के दौरान तोड़ी गई सड़क के मरम्मत कार्य में अपेक्षित प्रगति न पाए जाने पर नाराजगी प्रकट करते हुए फर्म जे.एम.सी. एवं बाबा जी.ए. इन्फ्रा. को कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने फर्म बाबा जी.ए. इन्फ्रा. के विरूद्ध कड़ी कार्यवाही करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि पाइपलाइन बिछाने के दौरान तोड़ी गई सड़क के मरम्मत का कार्य प्राथमिकता पर कराते हुए शीघ्र पूर्ण कराई जाय।

जिलाधिकारी ने नलकूप विभाग की समीक्षा के दौरान सहायक अभियंता नलकूप से कहा कि यान्त्रिक दोष एवं विद्युत दोष आदि के कारण बंद नलकूपों को शीघ्र क्रियाशील किया जाय। उन्होंने सिंचाई विभाग की समीक्षा के दौरान अधिशासी अभियंता से कहा कि यह सुनिश्चित किया जाय कि नहरों में टेल तक पानी पहुँचें, ताकि किसानों को सिंचाई के लिए परेशान न होना पड़े। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी विनोद राम त्रिपाठी सहित अन्य सम्बन्धित अधिकारीगण उपस्थित रहें।

यूजीसी विनियम 2026 को लागू करने के लिए भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी का शक्ति प्रदर्शन

मंत्र भारत संवाददाता

कौशाम्बी। जिला मुख्यालय मंझनपुर में भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी (कांशीराम) के कार्यकर्ताओं ने उच्च शिक्षण संस्थानों में समानता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से लाए गए यूजीसी विनियम 2026 के समर्थन में कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। संगठन ने जिलाधिकारी के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति और सर्वोच्च न्यायालय को ज्ञापन भेजकर इस विनियम पर लगी रोक हटाने और इसे देशभर में सख्ती से लागू करने की मांग की है। भीम आर्मी के जिला पदाधिकारियों ने बताया कि 15 जनवरी 2026 को जारी यूजीसी विनियम का मूल उद्देश्य उच्च शिक्षण संस्थानों में जाति, धर्म, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर होने वाले भेदभाव को खत्म करना है। ज्ञापन में रोहित वेमुला और डॉक्टर पायल तडवी जैसी हृदयविदारक घटनाओं का जिक्र करते हुए कहा गया कि मौजूदा व्यवस्था में अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्र मानसिक उत्पीड़न का शिकार हो रहे हैं।

वांछित अभियुक्त को पुलिस ने गिरफ्तार कर भेजा न्यायालय

मंत्र भारत संवाददाता

सिद्धार्थनगर। जिले के थाना खेसरहा पुलिस ने अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत एक वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार कर न्यायालय भेज दिया है। यह कार्रवाई वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉ. अभिषेक महाजन के आदेश, अपर पुलिस अधीक्षक प्रशांत कुमार प्रसाद के निर्देशन तथा क्षेत्राधिकारी बांसी रोहिणी यादव के पर्यवेक्षण में, थानाध्यक्ष अनूप कुमार मिश्र के नेतृत्व में की गई।थाना खेसरहा पर पंजीकृत मु0अ0सं0 10/2026, धारा 109(1), 115(2) बीएनएस से संबंधित वांछित की गिरफ्तारी के लिए उपनिरीक्षक जगत नारायण यादव (चौकी प्रभारी कुर्थिया), हेड कांस्टेबल उमेश चंद, कांस्टेबल आदित्य यादव की टीम ने अभियुक्त कन्हैया तिवारी पुत्र राम उजागिर तिवारी, निवासी अवँरी थाना खेसरहा को दिनांक 03 फरवरी 2026 को समय करीब 12:05 बजे लक्ष्मीगंज तिराहा से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त की निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त लोहे का पाइप भी बरामद किया गया। घटना के क्रम दिनांक 02 फरवरी 2026 को शाम लगभग 5:30 बजे कस्बा घोसियारी में बाजार करने आए जगदीश उर्फ टक्कल पर अभियुक्त कन्हैया तिवारी ने लोहे के पाइप से जान से मारने की नीयत से हमला कर दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए। घायल का इलाज गोरखपुर में चल रहा है। पीड़ित के भाई की तहरीर पर थाना खेसरहा में मुकदमा दर्ज किया गया था।अभियुक्त कन्हैया तिवारी के विरुद्ध थाना खेसरहा में पूर्व से कई आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं, जिनमें छेड़छाड़, मारपीट, गुंडा एक्ट तथा गंभीर धाराओं में अभियोग शामिल हैं।पुलिस ने अभियुक्त को आवश्यक विधिक कार्यवाही के उपरांत माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर दिया है।

पुलिस ने दो नफर वारंटी को गिरफ्तार कर न्यायालय भेजा

मंत्र भारत संवाददाता

सिद्धार्थनगर। जिले के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉ0 अभिषेक महाजन के आदेश के क्रम में अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत प्रशान्त कुमार प्रसाद अपर पुलिस अधीक्षक के कुशल निर्देशन में व रोहिनी यादव क्षेत्राधिकारी बांसी के कुशल पर्यवेक्षण व थानाध्यक्ष जोगिया उदयपुर मीरा चौहान द्वारा अपराध एंव अपराधियो व वारंटी व वाछिंत व पु0घो0 के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट जनपद सिद्धार्थनगर फौजदारी वाद संख्या 1911/19 धारा 379/411 भा0द0वि0 सम्बन्धित वारंटीगण राजेश पुत्र दशरथ दूसरा कृष्णा पुत्र दशरथ साकिनान पकरडीहा थाना जोगिया उदयपुर को वहद ग्राम पकरडीहा से उप निरीक्षक देवव्रत पांडे, कांस्टेबल विजय प्रजापति ने गिरफ्तार कर न्यायालय सिद्धार्थनगर पेशी हेतु रवाना किया।

मूरतगंज ब्लॉक में जल जीवन मिशन की टंकी शोपीस बनी

ग्रामीण पानी की समस्या से त्रस्त

मंत्र भारत संवाददाता

कौशाम्बी। मूरतगंज के आलम चंद गांव में जल जीवन मिशन के तहत नव नियमित पानी की टंकी शोपीस बनकर रह गई है। टंकी से लोगों को पर्याप्त पानी नहीं मिल पा रहा है, जिससे उन्हें परेशानी उठानी पड़ रही है। हैंडपंप पर पानी भरने के लिए दूर जाना पड़ता है, इससे समय भी बर्बाद होता है। इससे ग्रामीणों में काफी रोष व्याप्त है। आलम चांद में कई दशक पहले पानी की टंकी बनवाई गई थी जिससे लोगों को पानी की आपूर्ति की जाती थी।

ज्ञात हो कि इस टंकी के बगल में जल जीवन मिशन यानी हर घर जल योजना के तहत नई टंकी जल निगम द्वारा बनवा दी गई। इससे करीब 15 दिन पहले उसे पुरानी टंकी से सप्लाई रोक कर नई पानी की टंकी से आपूर्ति शुरू कर दी गई। लोग बताते हैं कि जिस दिन से नई पानी की टंकी से सप्लाई की जाने लगी उसी दिन से लोगों के घरों में पानी की समस्या होने लगी। लोगों का कहना है कि मुश्किल से 5 मिनट भी पानी नहीं आता है, जिससे मजबूरी में उन्हें हैंडपंप पर लाइन लगाना पड़ता है। शिकायत के बावजूद समस्या का निराकरण न होने से लोगों में अधिकारियों की प्रति नाराजगी है। इस संबंध में जल निगम के अधिशासी अभियंता जयपाल सिंह का कहना है कि मामला मेरे संज्ञान में नहीं है, हो सकता है कि तैनात ऑपरेटर लापरवाही कर रहा हो। इसकी फॉरेन रिपोर्ट लगाकर लोगों की समस्या से निजात दिलवाई जाएगी।

गोरखपुर ने लखनऊ को 7 विकेट से हराकर ट्रॉफी पर किया कब्जा

मंत्र भारत संवाददाता

सिद्धार्थनगर। जिले के शोहरतगढ़ स्थित छतहरी मैदान में क्रिकेट एसोसिएशन के तत्वावधान में आयोजित गौतम बुद्ध ऑल इंडिया क्रिकेट प्रतियोगिता का फाइनल मुकाबला मंगलवार को गोरखपुर और लखनऊ के बीच खेला गया। रोमांचक मुकाबले में गोरखपुर ने शानदार प्रदर्शन करते हुए लखनऊ को 7 विकेट से हराकर ट्रॉफी अपने नाम की।फाइनल मैच में गोरखपुर के कप्तान नीरज यादव ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। पहले बल्लेबाजी करते हुए लखनऊ की टीम निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट के नुकसान पर 167 रन ही बना सकी। लखनऊ की ओर से आशुतोष चौधरी ने 68 रन, अमित शर्मा ने 38 रन और राजकुमार ने 36 रनों का योगदान दिया। गेंदबाजी में गोरखपुर के राहुल सिंघवा और नीरज यादव ने दो-दो विकेट चटकाए, जबकि संदीप मित्तल और अमन पासवान को एक-एक सफलता मिली।

168 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी गोरखपुर की टीम ने सधी हुई शुरुआत की। अमन पासवान ने शानदार 60 रन, संदीप मित्तल ने 31 रन, अंकुर लखमणि ने 39 रन और आनंद दुबे ने 22 रनों की उपयोगी पारी खेलते हुए टीम को जीत दिलाई।और ट्रॉफी पर कब्जा किया।फाइनल मुकाबले में गोरखपुर के अमन पासवान को 'मैन ऑफ द मैच' घोषित किया गया। वहीं पूरे टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन के लिए संदीप मित्तल (गोरखपुर) को 'मैन ऑफ द सीरीज' और 'बेस्ट बैट्समैन' का पुरस्कार मिला। 'बेस्ट बॉलर' का खिताब गोरखपुर के अनुराग यादव को दिया गया।फाइनल मुकाबले के मुख्य अतिथि पूर्व कैबिनेट मंत्री एवं वर्तमान विधायक बांसी राजा जय प्रताप सिंह व नपं अध्यक्ष उमा अग्रवाल ने फीता काटकर व खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त किया।और मुख्य अतिथि राजा जय प्रताप सिंह ने कहा कि खेल प्रतियोगिताएं युवाओं में अनुशासन, टीम भावना और स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देती हैं। इस दौरान मुख्य अतिथि पूर्व कैबिनेट मंत्री व विधायक बांसी राजा जय प्रताप सिंह, नपं अध्यक्ष उमा अग्रवाल, भाजपा नेता श्याम जायसवाल, श्याम सुंदर चौधरी, नपं अध्यक्ष प्रतिनिधि रवि अग्रवाल, शैलू सिंह, सिद्धार्थनगर क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष उमेश प्रताप सिंह, उपाध्यक्ष विनय प्रताप सिंह, मनीष श्रीवास्तव, राजेश उपाध्याय, विवेक त्रिपाठी, विपिन त्रिपाठी, सुनील पांडे, सुनील सिंह, संदीप दुबे, मनोज सिंह, गंगेश्वर कुशवाहा, सदानंद उपाध्याय, मणिकांत उपाध्याय, धनंजय सिंह, वकील खान, बाबूजी अंसारी, गोपाल फौजी, राजकुमार मोदनवाल, केशवराम यादव सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहें।

सीईपीसी ने भारत-अमेरिका बीटीए का किया स्वागत

मंत्र भारत संवाददाता

भदोही। भारतीय हस्तनिर्मित कालीन उद्योग का प्रतिनिधित्व करने वाली कार्पेट एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल (सीईपीसी) ने भारत-अमेरिका द्विपक्षीय व्यापार समझौते (बीटीए) के संपन्न होने का स्वागत करते हुए इसे उद्योग के लिए समयोचित और निर्णायक कदम बताया है। परिषद का कहना है कि यह समझौता वैश्विक बाजारों में लंबे समय से चुनौतियों का सामना कर रहे हस्तनिर्मित कालीन क्षेत्र के लिए नई ऊर्जा और विश्वास लेकर आया है।

सीईपीसी के अनुसार, बढ़े हुए टैरिफ के कारण भारतीय हस्तनिर्मित कालीन उद्योग सबसे अधिक प्रभावित हुआ था, जबकि भारत के कुल हस्तनिर्मित कालीन निर्यात का लगभग 60 प्रतिशत हिस्सा अमेरिका को जाता है। ऐसे में भारत-अमेरिका बीटीए से इस प्रमुख बाजार में भारतीय उत्पादों की प्रतिस्पर्धात्मक स्थिति मजबूत होगी। सीईपीसी ने इस उपलब्धि के लिए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह के नेतृत्व में भारत सरकार के सतत और केंद्रित प्रयासों के प्रति आभार व्यक्त किया है। परिषद ने कहा कि सक्रिय व्यापार कूटनीति के माध्यम से भारतीय हस्तनिर्मित कालीनों के लिए वैश्विक बाजारों तक पहुंच में उल्लेखनीय सुधार हुआ है।

सीईपीसी के अध्यक्ष कैप्टन मुकेश गोंबर ने कहा कि भारत-ईयू और भारत-ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौतों से उद्योग को आंशिक राहत मिली थी, लेकिन भारत-अमेरिका बीटीए से विशेष उत्साह पैदा हुआ है। उन्होंने बताया कि टैरिफ को पहले के लगभग 50 प्रतिशत से घटाकर 18 प्रतिशत किए जाने से भारतीय हस्तनिर्मित कालीनों की अमेरिका में प्रतिस्पर्धा क्षमता बहाल हुई है और निर्यातकों व खरीदारों का विश्वास मजबूत हुआ है।सीईपीसी के उपाध्यक्ष अस्लम महबूब ने कहा कि उद्योग मौजूदा वित्तीय वर्ष को सकारात्मक रूप से समाप्त कर रहा है और आने वाले वित्तीय वर्ष में इन व्यापार समझौतों से बेहतर परिणाम मिलने की पूरी उम्मीद है।

सीईपीसी की कार्यकारी निदेशक (कार्यकारी) डॉ. स्मिता नागरकोटी ने बताया कि परिषद निर्यातकों और अन्य हितधारकों के लिए जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करेगी, ताकि वे भारत-ब्रिटेन और भारत-ईयू मुक्त व्यापार समझौतों से जुड़े अवसरों, अनुपालन आवश्यकताओं और प्रक्रियाओं को समझ सकें और इन समझौतों का लाभ जमीनी स्तर तक पहुंच सके। परिषद के अनुसार, इन व्यापार समझौतों से लगभग 2 अरब अमेरिकी डॉलर के भारतीय हस्तनिर्मित कालीन उद्योग को मजबूती मिलेगी और देशभर में इस शिल्प से जुड़े करीब 25 लाख कारीगरों की आजीविका पर इसका सीधा सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।

आयुष्मान, मोरवा नदी पुनरोद्धार सहित प्रमुख योजनाओं की डीएम ने की समीक्षा

कार्यों का समयबद्ध क्रियान्वयन न होने पर होगी सख्त कार्रवाई-जिलाधिकारी

मंत्र भारत संवाददाता

भदोही। जनपद में निर्वाचन, राजस्व एवं विकास प्राथमिकताओं वाले कार्यक्रमों को त्वरित गति एवं समयबद्ध रूप से किये जाने हेतु जिलाधिकारी शैलेष कुमार की अध्यक्षता कलेक्ट्रेट सभागार में साप्ताहिक समीक्षा बैठक आहूत की गयी।

इस अवसर पर विशेष गहन पुनरीक्षण, पंचायत निर्वाचक नामावलियों का पुनरीक्षण, गुणवत्ता पूर्ण धान खरीद, शत प्रतिशत आयुष्मान गोल्डेन कार्ड- सामान्य/वरिष्ठ नागरिक, सर्टिफिकेशन-समस्त उप स्वास्थ्य केंद्रों पर, टीबी मुक्त जनपद, जिला अस्पताल ज्ञानपुर में ई-सुश्रुत का प्रभावी क्रियान्वयन, विंग को संचालित कराया जाना, स्वयं सहायता समूहों में अधिकाधिक अच्छादन, फार्मर रजिस्ट्री, फैमिली आईडी, पीएम-सूर्य घर, जीरो प्रॉवर्टी अभियान, पुराने राजस्व वादों का अभियान चलाकर निस्तारण। मोरवा नदी का पुनरोद्धार, वीडीपी, पीएम अजय, आदर्श ग्राम घोषित करवाना, सहकारी समितियों पर उर्वरक की उपलब्धता आईजीआरएस जनशिकायत निस्तारण में गुणवत्ता व बेहतर रैंकिंग, आईजीआरएस-तहसीलों में बेहतर निस्तारण- टॉप 50 रैंक, सीएम डैश बोर्ड (राजस्व/विकास) में बेहतर रैंक प्राप्त करना जिला मुख्यालय की भूमि पर से कब्जा हटवाना, एनएच 731बी मुआवजा भुगतान, नथईपुर रोड मुआवजा भुगतान, निराश्रित गोवंश की व्यवस्था आदि की विभागवार प्रगति की समीक्षा की गयी।

जिलाधिकारी शैलेष कुमार ने धान खरीद लक्ष्य के सापेक्ष 67ज्होने पर डिप्टी आरएमओ को कड़ी हिदायद दी की लक्ष्य के सापेक्ष सत प्रतिशत समय से पूर्ण कराए जिलाधिकारी स्वास्थ्य विभाग मे आयुष्मान गोल्डन कार्ड समीक्षा के दौरान प्रगति खराब होने पर एम ओ आई सी के जिला पूर्ति अधिकारी खंड विकास अधिकारी कड़ी हिदायदि की आयुष्मान कार्ड की प्रतिदिन समीक्षा करें सबसे खराब कार्य करने वाले कार्मिक को चिन्हित कर करवाई करें साथ ही पंचायत सहायक सी एच ओ कोटेदार जिनकी आईडी बनी हुई है कार्य में प्रगति करने के साथ-साथ प्रतिदिन साय 6:00 बजे तक संबंधित अधिकारी रिपोर्ट उपलब्ध कराना सुनिश्चित कराए शहरी क्षेत्र में विशेष निगरानी करने का निर्देश जिला पूर्ति अधिकारी को दिया जिला पंचायत राज अधिकारी को निर्देश दिया कि 40 ग्राम पंचायतों में पंचायत सहायकों का नियमानुसार प्रस्ताव बनाकर चयन कराये। उन्होंने मोरवा नदी के पुनरोद्धार के सम्बन्ध में सम्बन्धित अधिकारी को निर्देश दिया कि समय से सफाई का कार्य पूर्ण कराये। ताकि बरसात के दिनों में पानी का संचय हो जाय। नदी को जीवित करने के लिए चैक डैम बनाने का निर्देश सम्बन्धित अधिकारी को दिया। साथ ही साथ अधिशासी अभियंता लोक निर्माण को नथईपुर मार्ग में एनएच 731बी मुआवजा पाने वाले कृषकों को प्रत्येक दशा में समय से मुआवजा दिलाए यदि कहीं कोई समस्या आ रही है तो तहसील से समन्वय स्थापित कर प्राथमिकता से भुगतान कराए साथ ही साथ अगली बैठक में कितना किसानों को भुगतान किया गया है पूरे डिटेल सहित उपस्थित होने का निर्देश अधिशासी अभियंता लोक निर्माण को दिया फार्मर रजिस्ट्री की समीक्षा के दौरान दौरान उप कृषि निदेशक को निर्देश दिया कि प्रतिदिन कम से कम 1400 फार्मर रजिस्ट्री कार्ड प्रतिदिन बनवाना सुनिश्चित कराए प्रतिदिन मॉनिटरिंग कर 6:30 बजे रिपोर्ट भी उपलब्ध कराना सुनिश्चित कराए साथ ही लक्ष्य को 15 मार्च तक प्रत्येक दशा सत प्रतिशत पूर्ण कराए त पीएम सूर्य घर समीक्षा के दौरान अधिशासी अभियंता विद्युत को निर्देश दिया कि समस्त एसडीओ से माह फरवरी तक निर्धारित लक्ष्य को शत प्रतिशत पूर्ण कराए अन्यथा की दशा में संबंधित की जिम्मेदारी जवाब देही तय की जाएगीत जिलाधिकारी ने फैमिली आईडी समीक्षा के दौरान नगर पालिका नगर पंचायत के अधिशासी अधिकारियों को कड़ा निर्देश दिया कि अपने अपने नगर निकायों में माह फरवरी में कम से कम 500 फैमिली आईडी बनवाना सुनिश्चित कराए त साथ ही गोल्डेन कार्ड की प्रगति बढ़ाने का निर्देश दिया अन्यथा सख्त कार्रवाई की जाएगी जिलाधिकारी ने उपस्थित सभी अधिकारियों को निर्देश दिया कि अगली साप्ताहित समीक्षा बैठक में अपने-अपने विभागों में प्रगति करते हुए रिपोर्ट प्रेषित करने का निर्देश सम्बन्धित अधिकारियों को दिया, और कहा कि जिन विभागों में प्रगति खराब होगी। उन विभागो के अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जायेगी। जिलाधिकारी ने उपस्थित अधिकारियों को यह भी निर्देश दिया कि आइ जीआर एस के प्रकरणों को समय से गुणवत्ता के अनुरूप शिकायत कर्ताओं से बातचीत कर निस्तारण कराए। इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी बाल गोबिन्द शुक्ल, अपर जिलाधिकारी कुंवर वीरेन्द्र मौर्य, अपर जिलाधिकारी न्यायिक विजय नारायण सिंह, मुख्य चिकित्सा अधिकारी एवं विभिन्न विभागों के अधिकारीगण उपस्थित रहे।

ई-बीएलओ ऐप पर उत्कृष्ट कार्य करने वाले भदोही के 08 बीएलओ को मिलेगा प्रोत्साहन

भदोही।त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन-2026 के अंतर्गत पंचायत निर्वाचक नामावली के वृहद पुनरीक्षण कार्य में ई-बीएलओ ऐप के प्रभावी उपयोग को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तर प्रदेश ने जनपद भदोही के आठ सर्वश्रेष्ठ बूथ लेवल अधिकारियों को प्रोत्साहन राशि प्रदान करने की अनुमन्यता दी है।

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत एवं नगरीय निकाय) भदोही को भेजे गए पत्र के अनुसार, ई-बीएलओ ऐप पर 50 प्रतिशत से अधिक मतदाताओं की प्रविष्टि करने वाले बीएलओ को यह प्रोत्साहन दिया जा रहा है। आयोग स्तर पर लिए गए निर्णय के क्रम में जनपद भदोही में उत्कृष्ट कार्य करने वाले बीएलओ का चयन किया गया है। प्रोत्साहन सूची में विकास खंड डीघ के ग्राम पंचायत सोनैचा के बीएलओ राजनाथ यादव को प्रथम स्थान प्राप्त करते हुए 10, 000 रुपये, विकास खंड औराई के ग्राम पंचायत उमरहा के बीएलओ सतीश कुमार चौबे को द्वितीय स्थान पर 8, 000 रुपये, जबकि विकास खंड डीघ के ग्राम पंचायत त्रिभुवनपुर के राजीव कुमार गुप्ता को तृतीय स्थान पर 6, 000 रुपये की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी।

इसके अतिरिक्त उत्कृष्ट कार्य के लिए पांच अन्य बीएलओ को 3, 000-3, 000 रुपये की सांत्वना प्रोत्साहन राशि देने की स्वीकृति दी गई है। इनमें विकास खंड औराई के डेरवा ग्राम पंचायत के आलोक कुमार मिश्र, जाठी के हृदय नारायण, डीघ विकास खंड के ग्राम पंचायत डीघ के दयाशंकर, औराई विकास खंड के दिघवट के अमरनाथ पटेल तथा डीघ विकास खंड के मवैयाथान सिंह के विनोद कुमार शामिल हैं।

इस पहल से बीएलओ के कार्यों में और अधिक पारदर्शिता, तकनीकी दक्षता एवं गति आएगी, साथ ही डिजिटल माध्यम से निर्वाचन प्रक्रिया को सशक्त बनाने में भी मदद मिलेगी।

भिवंडी में सड़क निर्माण के दौरान मुंबई मनपा की पाइपलाइन फूटी, कई इलाकों में 15 घंटे जलापूर्ति बंद

मनपा जलापूर्ति विभाग की टीम दुरुस्ती में जुटी, 12 घंटे में मरम्मत पूरी होने की संभावना

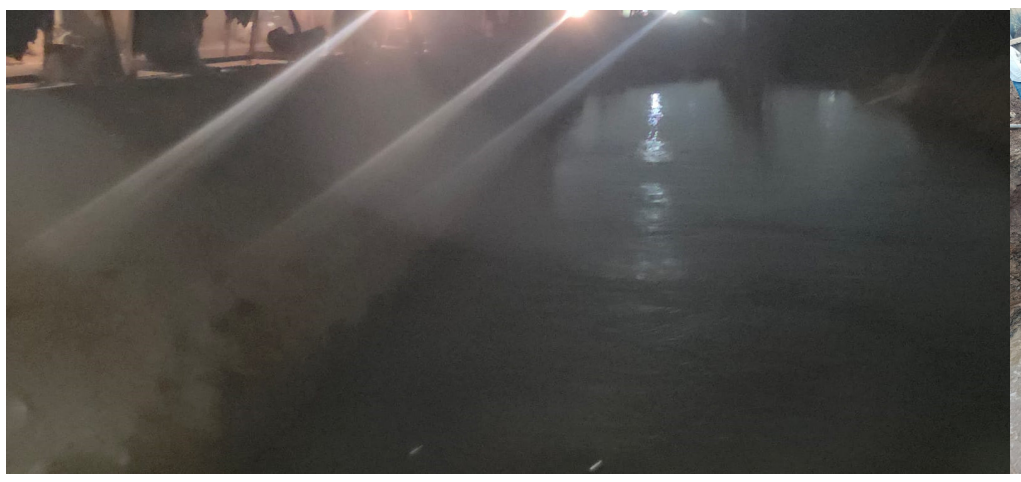

भिवंडी (संवाददाता)

मंत्र न्यूज

भिवंडी शहर में उस वक्त अफरा-तफरी मच गई, जब सड़क निर्माण कार्य के दौरान मुंबई महानगरपालिका की मुख्य जलापूर्ति पाइपलाइन अचानक फट गई। इस घटना के चलते शहर के कई इलाकों में बड़े पैमाने पर पानी बर्बाद हुआ, वहीं एहतियातन लगभग 15 घंटे तक जलापूर्ति बंद करनी पड़ी है। मनपा जलापूर्ति विभाग ने तत्काल मौके पर पहुंचकर मरम्मत कार्य युद्धस्तर पर शुरू कर दिया है।

भिवंडी मनपा जलापूर्ति विभाग के कार्यकारी अभियंता संदीप पटनावर ने जानकारी देते हुए बताया कि भिवंडी शहर को प्रतिदिन लगभग 42 एमएलडी पानी की आपूर्ति मुंबई मनपा की 600 एमएम व्यास की पाइपलाइन के जरिए की जाती है। यह पानी वडाला स्थित पानी की टंकी में लाकर शहर के विभिन्न हिस्सों में वितरित किया जाता है। शनिवार शाम करीब 6 बजे स्थानीय के.वी. ब्रीन, गौतम कंपाउंड परिसर में मुंबई मनपा द्वारा आरसीसी सड़क निर्माण का कार्य चल रहा था। इसी दौरान लापरवाही या तकनीकी कारणों से मुख्य पाइपलाइन फट गई, जिससे भारी मात्रा में पानी बहने लगा।

घटना की सूचना मिलते ही भिवंडी मनपा के जलापूर्ति विभाग की टीम कार्यकारी अभियंता संदीप पटनावर के नेतृत्व में मौके पर पहुंची और तुरंत पाइपलाइन की दुरुस्ती का काम शुरू किया गया। पटनावर ने बताया कि मरम्मत कार्य में लगभग 12 घंटे का समय लगने की संभावना है। इसी कारण सोमवार शाम 7 बजे से मंगलवार सुबह 10 बजे तक संबंधित पाइपलाइन से होने वाली जलापूर्ति पूरी तरह बंद रखी गई है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि मरम्मत कार्य पूर्ण होने के बाद अगले एक दिन तक कम दबाव में पानी की आपूर्ति की जाएगी। मनपा प्रशासन ने नागरिकों से इस अवधि में पानी का संयमित उपयोग करने और प्रशासन को सहयोग करने की अपील की है। अचानक हुई इस तकनीकी खराबी से प्रभावित क्षेत्रों के नागरिकों को असुविधा का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन प्रशासन ने जल्द से जल्द स्थिति सामान्य करने का भरोसा दिलाया है।

तीन बेटियों के जन्म पर विवाहिता को किया प्रताड़ना

दूसरी शादी की इजाज़त न देने पर बढ़ा विवाद

भिवंडी (संवाददाता)

मंत्र न्यूज

भिवंडी के शांतिनगर पुलिस स्टेशन क्षेत्र में एक विवाहिता को बेटा न होने के कारण शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित किए जाने का गंभीर मामला सामने आया है। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने पति, सास, ननद और पति की कथित प्रेमिका के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस के अनुसार, पीड़िता (35) वर्ष, गृहिणी है और भादवड गांव भिवंडी में रहती है। शिकायत में बताया गया है कि विवाह के बाद पीड़िता से तीन बेटियां हुईं, लेकिन एक भी बेटा नहीं होने के कारण ससुराल पक्ष उससे नाराज़ रहने लगा। आरोप है कि पति प्रकाश श्रीहरी कांबले, सास विजय माला श्रीहरी कांबले, ननद कल्पना दत्तात्रय वाघमारे और पति की प्रेमिका संध्या संजय जाधव ने लगातार पीड़िता पर बेटा पैदा करने का दबाव बनाते थे। शिकायत के अनुसार, पति व उसके परिजनों का कहना था कि वंश चलाने के लिए बेटे की आवश्यकता है। इसी बात को लेकर घर में आए दिन विवाद होता था। पीड़िता ने यह भी आरोप लगाया है कि जब उसने पति को दूसरी शादी करने की अनुमति देने से इनकार किया, तो प्रताड़ना और बढ़ गई। इस दौरान पति की कथित प्रेमिका संध्या संजय जाधव भी पीड़िता को मानसिक रूप से प्रताड़ित करने में शामिल रही।

शिकायत के मुताबिक, 20 अक्टूबर 2022 से 12 जनवरी 2026 के बीच अलग-अलग अवसरों पर पीड़िता के साथ गाली-गलौज, मानसिक उत्पीड़न और मारपीट की गई। अंततः 12 जनवरी 2026 को आरोपियों ने पीड़िता के साथ मारपीट कर उसे उसके बेटियाँ के साथ घर से बाहर निकाल दिया।पीड़िता की शिकायत पर शांतिनगर पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 85 और 3(5) के तहत मामला दर्ज किया है। जिसकी आगे की जांच सहायक पुलिस निरीक्षक पोटे द्वारा किया जा रहा है।

भिवंडी में महिला पर लाठी से हमला, तीन आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज

भिवंडी। भिवंडी शहर में कानून-व्यवस्था को चुनौती देती घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। मानकोली गांव में आपसी विवाद के दौरान एक महिला पर लाठी से हमला किए जाने का मामला उजागर हुआ है। इस घटना में महिला गंभीर रूप से घायल हो गई, जबकि पुलिस ने तीन आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर उनकी तलाश शुरू कर दी है।

पुलिस के अनुसार, मानकोली गांव निवासी आमीरूलनिसा राजा खान (38) 1 फरवरी 2026 की शाम करीब 7.30 बजे स्मशानभूमि के पास गणेश शेठ की चॉल इलाके में मौजूद थीं। इससे पहले गांव के एक युवक और पड़ोस में रहने वाले सलीम खान के बच्चों के बीच किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ था। उसी विवाद के संबंध में पूछताछ करने पर सलीम खान के बड़े बेटे सहीम खान, उसके रिश्तेदार मोटू और अनारू ने आमीरूलनिसा से बहस शुरू कर दी। देखते ही देखते विवाद हिंसक हो गया और आरोप है कि सहीम खान ने लकड़ी के डंडे से महिला के सिर पर जोरदार वार किया। अन्य आरोपियों ने भी उसके साथ मारपीट की। घायल महिला की शिकायत पर 2 फरवरी 2026 को नारपोली पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया है। फिलहाल तीनों आरोपी फरार हैं और पुलिस उनकी तलाश कर रही है।

अवैध हथियार के साथ युवक गिरफ्तार, चार देसी पिस्टल और जिंदा कारतूस बरामद

भिवंडी। भिवंडी में अपराध शाखा पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक युवक को अवैध हथियारों के साथ गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास से चार देसी पिस्टल और चार जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। यह कार्रवाई ठाणे पुलिस की विशेष शाखा की टीम ने की है। मामले में आरोपी के खिलाफ नारपोली पुलिस थाना में शस्त्र अधिनियम के तहत केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है।

पुलिस के अनुसार, गिरफ्तार आरोपी की पहचान सोहेल बेग शोराब बेग मिर्झा (20) के रूप में हुई है, जो मूल रूप से आलमपुर, लहारखेड़ा, जिला भिंड, मध्यप्रदेश का निवासी है। वर्तमान में वह भिवंडी क्षेत्र में रह रहा था। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि एक युवक अवैध हथियार लेकर भिवंडी इलाके में घूम रहा है। सूचना के आधार पर 2 फरवरी की दोपहर करीब 3.55 बजे जय बारकुला देव चौक, वेहले-भाटाले रोड, मानकोली नाका के पास भिवंडी में जाल बिछाकर आरोपी को रोका गया। तलाशी के दौरान उसके पास से बिना किसी वैध लाइसेंस के चार देसी पिस्टल और चार जिंदा कारतूस बरामद हुए। जब पुलिस ने हथियार रखने का कारण और दस्तावेज पूछे, तो आरोपी कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे सका।पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपी ने महाराष्ट्र पुलिस आयुक्त, ठाणे द्वारा जारी निषेधाज्ञा (मनाई आदेश) का भी उल्लंघन किया है। बरामद हथियारों की कुल कीमत करीब 4 लाख 12 हजार 940 रुपये आंकी गई है। इस मामले में नारपोली पुलिस स्टेशन में शस्त्र अधिनियम की धारा 3, 25, 27 के साथ-साथ महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम की धाराओं 37(1) और 135 के तहत केस दर्ज किया गया है। आरोपी को गिरफ्तार कर आगे की पूछताछ की जा रही है। पुलिस यह भी जांच कर रही है कि आरोपी इन हथियारों को कहां से लाया, किस उद्देश्य से भिवंडी आया था और क्या वह किसी संगठित अपराध गिरोह से जुड़ा हुआ है। इस कार्रवाई से शहर में अवैध हथियारों की तस्करी पर एक बार फिर चिंता बढ़ गई है। जिसकी आगे की जांच अमली पदार्थ विरोधी पथक, अपराध शाखा ठाणे के पुलिस उप निरीक्षक राजेन्द्र निकम कर रहे है।

भिवंडी-वाडा रोड की बदहाली से जनता त्रस्त, उड़ती धूल और गड्ढों ने बढ़ाई मुश्किलें

भिवंडी (संवाददाता)

मंत्र न्यूज

भिवंडी।भिवंडी-वाडा रोड की जर्जर हालत और सड़कों से उड़ती धूल ने आम जनता की ज़िंदगी मुहाल कर दी है। ठाणे और पालघर जिलों को जोड़ने वाला यह प्रमुख मार्ग इन दिनों भारी प्रदूषण, गड्ढों और धीमे निर्माण कार्य के कारण लोगों के लिए परेशानी का सबब बन गया है। सड़क की खराब स्थिति से छात्र, नौकरीपेशा लोग, व्यापारी और रोज़ाना यात्रा करने वाले नागरिक सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं।

स्थानीय नागरिकों का कहना है कि सड़क पर बने बड़े-बड़े गड्ढों और कच्ची सतह से लगातार उड़ती धूल वातावरण को बुरी तरह दूषित कर रही है। भारी वाहनों के गुजरते ही धूल का गुबार उठता है, जिससे सामने चल रहे वाहन तक दिखाई नहीं देते। इससे दुर्घटनाओं का खतरा लगातार बढ़ रहा है। अंबाडी से भिवंडी रोज़ सफर करने वाले अनिल वर्मा बताते हैं कि धूल के कारण आंखों में जलन, सांस लेने में तकलीफ और खांसी जैसी समस्याएं आम हो गई हैं। भिवंडी-वाडा रोड पर पिछले तीन-चार वर्षों से कंक्रीटीकरण का काम चल रहा है, लेकिन इसकी रफ्तार बेहद धीमी है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि करोड़ों रुपये खर्च होने के बावजूद काम की गुणवत्ता खराब है। सड़क को जगह-जगह खोदकर छोड़ दिया गया है, न तो डायवर्जन की उचित व्यवस्था है और न ही चेतावनी बोर्ड लगाए गए हैं। इससे ट्रैफिक जाम और हादसों की संख्या बढ़ती जा रही है।

कई सामाजिक संगठनो के सदस्य व विभिन्न गांवों के नागरिकों का आरोप है कि पिछले 12 वर्षों में इस मार्ग पर 600 से अधिक लोगों की जान जा चुकी है। उन्होंने ठेकेदारों और सरकारी तंत्र पर लापरवाही और भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए हैं। वहीं, सांसद सुरेश म्हात्रे ने कहा कि काम के लिए निधि उपलब्ध करा दी गई है और पीडब्ल्यूडी अधिकारियों से मिलकर निर्माण में तेजी लाने की मांग की जाएगी। पीडब्ल्यूडी के उप अभियंता दत्तू गीते का कहना है कि निविदा शर्तों के अनुसार काम चल रहा है और नालियों का कार्य पूरा होने के बाद सड़क निर्माण तेजी से किया जाएगा। हालांकि, जनता का सवाल साफ है–जब तक सड़क पूरी नहीं बनती, तब तक धूल और खतरे से राहत कब मिलेगी?

युवती से शादी का झांसा देकर दुष्कर्म और ब्लैकमेलिंग का आरोप, मामला दर्ज

भिवंडी (संवाददाता)

मंत्र न्यूज

भिवंडी । भिवंडी के नारपोली पुलिस स्टेशन क्षेत्र में एक युवती से शादी का झांसा देकर लंबे समय तक शारीरिक शोषण और बाद में बदनाम करने की धमकी देने का गंभीर मामला सामने आया है। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी युवक के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

पुलिस के अनुसार, पीड़िता (21) वर्ष, जो भिवंडी तालुका के एक गांव की निवासी है।आरोपी की पहचान सुरज बालाजी लहुटे (23), निवासी ताडाली, हनुमान मंदिर के पास, कामतघर, भिवंडी के रूप में हुई है। शिकायत के मुताबिक, वर्ष 2019 से अक्टूबर 2024 के बीच आरोपी ने पीड़िता को शादी का झांसा देकर उसके साथ कई बार शारीरिक संबंध बनाए। यह घटनाएं ताडाली, हनुमान मंदिर के पास स्थित आरोपी के घर पर हुईं। शिकायत में यह भी आरोप लगाया गया है कि बाद में आरोपी ने पीड़िता की निजी तस्वीरें और वीडियो दिखाकर उसे बदनाम करने की धमकी दी। इतना ही नहीं, आरोपी ने पीड़िता की सात ग्राम वजनी सोने की चेन और उसकी मां की 20 तोले वजनी सोने की गठान (गहने) को लेकर भी धमकाने का आरोप है। पीड़िता ने 2 फरवरी को नारपोली पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस ने तुरंत मामला दर्ज कर लिया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 64, 77, 351(2), 308(3), 66(ई), 67 और 67(अ) के तहत अपराध पंजीबद्ध किया है। जिसकी आगे की जांच पुलिस निरीक्षक ज्ञानेश्वर कदम कर रहे हैं।

भिवंडी में एक ही दिन दो नाबालिग बच्चे लापता, पुलिस की सक्रियता पर उठे सवाल

धामणकर नाका पर मारपीट, युवक गंभीर रूप से घायल

भिवंडी (संवाददाता)

मंत्र न्यूज

भिवंडी शहर में नाबालिग बच्चों के लापता होने की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। एक ही दिन में शहर के अलग-अलग इलाकों से दो नाबालिग बच्चों के गायब होने की घटनाओं ने अभिभावकों की चिंता बढ़ा दी है। लगातार सामने आ रही ऐसी वारदातों के चलते पुलिस की सक्रियता और कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठने लगे हैं।

पुलिस के अनुसार, नारपोली पुलिस स्टेशन अंतर्गत काल्हेर इलाके से एक 12 वर्षीय नाबालिग बच्चा अचानक लापता हो गया है। परिजनों को आशंका है कि किसी अज्ञात व्यक्ति ने बच्चे की नासमझी का फायदा उठाकर उसे बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया है। वहीं दूसरी घटना शांतिनगर पुलिस स्टेशन क्षेत्र के न्यू आजाद नगर की है, जहां 9 वर्षीय बच्चा 31 जनवरी को दोपहर करीब 12 बजे अपने घर के सामने खेल रहा था, लेकिन उसके बाद वह वापस नहीं लौटा। काफी तलाश के बावजूद बच्चे का कोई सुराग नहीं लग पाया। दोनों मामलों में पुलिस ने अपहरण का केस दर्ज कर बच्चों की तलाश शुरू कर दी है। हालांकि, बीते दिनों में नाबालिगों के गायब होने की बढ़ती घटनाओं और कई मामलों में बच्चों का अब तक पता न चल पाने से नागरिकों में भय का माहौल है। पुलिस का कहना है कि बच्चों की तलाश के लिए विशेष टीमें गठित की गई हैं और जांच तेज कर दी गई है। साथ ही नागरिकों से अपील की गई है कि वे बच्चों पर विशेष नजर रखें और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की तुरंत सूचना पुलिस को दें। इधर, भिवंडी शहर पुलिस स्टेशन क्षेत्र के धामणकर नाका चौकी के पास 1 फरवरी 2026 की सुबह करीब 11 बजे मारपीट की घटना सामने आई। पुराने विवाद को लेकर रक्षा राकेश वाघे (18) और एक नाबालिग बालक ने महेश नामक युवक के साथ गाली-गलौज और हाथापाई की। धक्का लगने से महेश चौकी के स्लैब से नीचे सड़क पर गिर पड़ा, जिससे उसके सिर में गंभीर चोट आई। इस मामले में भारतीय न्याय संहिता की संबंधित धाराओं के तहत केस दर्ज कर पुलिस आगे की जांच कर रही है।

दो दिन में बिजली चोरी के तीन मामले उजागर, 6 आरोपियों पर केस.

भिवंडी (संवाददाता)

मंत्र न्यूज

भिवंडी में बिजली चोरी की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। बीते दो दिनों के भीतर शहर के अलग-अलग इलाकों से बिजली चोरी के तीन बड़े मामले सामने आए हैं। टोरेंट पावर कंपनी को कुल 5 लाख 15 हजार 250 रुपये से अधिक का नुकसान पहुंचाने के आरोप में 6 लोगों के खिलाफ शांतिनगर पुलिस स्टेशन में मामले दर्ज किए गए हैं। इन घटनाओं से बिजली चोरी पर रोक लगाने के दावों पर एक बार फिर सवाल खड़े हो गए हैं।

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, पहला मामला दरगाह रोड स्थित आलिया बिल्डिंग (विंग-सी) का है। टोरेंट पावर कंपनी के एक्जीक्यूटिव विकास राजेश प्रजापती की टीम द्वारा की गई छापामारी में उपभोक्ता खान मुदस्सर अख्तर और उजमा आरिफ शेख द्वारा बिजली मीटर को बायपास कर डायरेक्ट कनेक्शन के जरिए अनधिकृत रूप से बिजली का इस्तेमाल किए जाने का खुलासा हुआ। जांच में सामने आया कि 2 मार्च 2020 से 11 मार्च 2022 के बीच कुल 8,022 यूनिट बिजली चोरी की गई, जिससे कंपनी को 2,02,232 रुपये 48 पैसे का नुकसान हुआ। इस संबंध में शांतिनगर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज की गई है।

दूसरा मामला इस्लामपुरा, पुराने एसटी बस डिपो के पास का है। यहां असीम अंसारी ने बिजली के पोल से अवैध कनेक्शन लेकर 4,331 यूनिट बिजली का उपयोग किया। इस बिजली चोरी से कंपनी को 1,01,318 रुपये 82 पैसे का नुकसान हुआ। इस मामले में टोरेंट पावर की एक्जीक्यूटिव कु. अवंती सुदेश नाचणकर ने शांतिनगर पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है।

तीसरा मामला तेलीपाड़ा कनेरी इलाके के दत्तात्रेय बिल्डिंग से सामने आया है। यहां वंदना दिनेश पाटिल, दिनेश पाटिल और गणेश पाटिल पर आरोप है कि उन्होंने टोरेंट के मिनी सेक्शन पीलर से अवैध कनेक्शन लेकर और मीटर को बायपास कर 8,479 यूनिट बिजली का इस्तेमाल किया। इससे टोरेंट पावर को 2,11,699 रुपये 26 पैसे का नुकसान हुआ। इस मामले की भी शिकायत शांतिनगर पुलिस स्टेशन में दर्ज की गई है। तीनों मामलों की आगे की जांच सहायक पुलिस निरीक्षक अरुण घोलप कर रहे हैं। लगातार सामने आ रही बिजली चोरी की घटनाओं से प्रशासन और बिजली वितरण कंपनी की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठने लगे हैं।

रक्तदान के क्षेत्र मैं उत्कृष्ट कार्य हेतु हुए हिमांशु द्विवेदी हुए सम्मानित

मंत्र भारत संवाददाता

सिद्धार्थनगर। जिले के भनवापुर ब्लॉक के शिक्षक हिमांशु द्विवेदी रक्तदान के क्षेत्र मैं उत्कृष्ट कार्य हेतु हुए सम्मानित गाजीपुर में सम्पन्न हुआ राष्ट्रीय सम्मेलन एवं जीवन रक्षक सम्मान समारोह में 300 रक्तदाताओं को किया गया सम्मानित, जीवन रक्षक फाउंडेशन, गाजीपुर के तत्वावधान में राष्ट्रीय सम्मेलन एवं जीवन रक्षक सम्मान समारोह का भव्य आयोजन 01 फरवरी 2026 को शहनाई पैलेस, बन्धवा (गाजीपुर) में सफलतापूर्वक सम्पन्न हुआ। कार्यक्रम में रक्तदान के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने वाले गाजीपुर सहित देश के विभिन्न राज्यों एवं जनपदों के लगभग 300 रक्तदाताओं को सम्मानित किया गया। समारोह के मुख्य अतिथि अभिनव सिन्हा ने चयनित रक्तदाताओं को सम्मान प्रदान किया। इस अवसर पर शतकवीर एवं अर्ध शतकवीर रक्तदाताओं सहित उत्तर प्रदेश के 15 जनपदों और गाजीपुर के 300 से अधिक रक्तदाताओं को सम्मानित किया गया।

दूध की गाड़ी का ड्राइवर बना ठग

डेयरी व्यापारी से 4.50 लाख रुपये की ठगी

भिवंडी (संवाददाता)

मंत्र न्यूज

भिवंडी में दूध व्यवसाय से जुड़े एक गंभीर धोखाधड़ी के मामले में ड्राइवर और बिचौलिये की मिलीभगत सामने आई है। दूध सप्लाई के नाम पर डेयरी व्यापारी से 4.50 लाख रुपये की रकम हड़प ली गई। कोनगांव पुलिस ने इस मामले में आरोपी ड्राइवर के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है, वहीं पूरे प्रकरण में एक अन्य व्यक्ति राजू यादव की भूमिका भी अहम बताई जा रही है।

पुलिस के अनुसार, शिकायतकर्ता नरेन्द्र मधुकर देवरे (30), निवासी भिवंडी, पेशे से दूध डेयरी का व्यवसाय करते हैं। वे अपनी डेयरी से दूध की सप्लाई राजू यादव (निवासी नवी मुंबई) को करते थे, जो आगे अन्य स्थानों पर दूध पहुंचाने का काम करता था। इसी सप्लाई व्यवस्था में आरोपी संतोष राजाराम सिंह (40), जो दूध की गाड़ी चलाने का ड्राइवर है, को दूध और रकम लाने-ले जाने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी।

आरोप है कि राजू यादव को दूध सप्लाई के बदले मिलने वाली रकम ड्राइवर संतोष सिंह के माध्यम से शिकायतकर्ता तक पहुंचनी थी। लेकिन आरोपी ड्राइवर ने राजू यादव से दूध की रकम लेकर शिकायतकर्ता तक नहीं पहुंचाई और विश्वास का दुरुपयोग करते हुए अलग-अलग समय पर कुल 4 लाख 50 हजार रुपये की रकम अपने पास ही रख ली। बार-बार पूछताछ के बावजूद जब रकम वापस नहीं की गई, तब नरेन्द्र देवरे को ठगी का एहसास हुआ। घटना 1 फरवरी 2026 की रात करीब 10.30 बजे सुमननगर, सरवली पाड़ा, ब्रिज के पास बाबोसा कंपाउंड क्षेत्र में घटित हुई बताई जा रही है। इसके बाद 2 फरवरी 2026 को कोनगांव पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई गई। पुलिस ने आरोपी संतोष राजाराम सिंह के खिलाफ धोखाधड़ी और विश्वासघात की धाराओं में मामला दर्ज किया है। पुलिस अब यह भी जांच कर रही है कि इस पूरे प्रकरण में राजू यादव की भूमिका कितनी है और क्या वह सिर्फ सप्लाई लेने वाला था या ठगी की जानकारी उसे पहले से थी। साथ ही आरोपी ड्राइवर द्वारा अन्य डेयरी व्यापारियों के साथ की गई संभावित ठगी की भी जांच की जा रही है। घटना के बाद दूध व्यवसाय से जुड़े व्यापारियों में चिंता और सतर्कता का माहौल है।

ऑस्ट्रेलियन ओपन जीतते ही अल्काराज का बड़ा फैसला, रॉटरडैम ओपन से हटे

रॉटरडैम **(एजेंसी)**। नए ऑस्ट्रेलियन ओपन चैंपियन कार्लोस अल्काराज ने फरवरी में होने वाले एबीएन एमरो रॉटरडैम ओपन से अपना नाम वापस ले लिया है। टूर्नामेंट आयोजकों ने इसकी आधिकारिक पुष्टि कर दी है। स्पेन के स्टार टेनिस खिलाड़ी अल्काराज पिछले सीजन में इस एटीपी 500 इनडोर हार्ड कोर्ट टूर्नामेंट के चैंपियन रहे थे। हालांकि, एटीपी वेबसाइट के मुताबिक 9 से 16 फरवरी तक होने वाले इस टूर्नामेंट में वह अपने खिताब की रक्षा नहीं करेंगे।

22 वर्षीय अल्काराज ने यह फैसला उस ऐतिहासिक उपलब्धि के ठीक एक दिन बाद लिया, जब उन्होंने करियर ग्रैंड स्लैम पूरा करने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बनने का रिकॉर्ड बनाया। रविवार को खेले गए ऑस्ट्रेलियन ओपन फाइनल में उन्होंने नोवाक जोकोविच को चार सेट में हराकर मेलबर्न में अपना पहला ऑस्ट्रेलियन ओपन खिताब जीता था।

सोमवार को अल्काराज ने मेलबर्न के रॉयल एग्ज़िबिशन बिल्डिंग में आयोजित एक सेलिब्रेशन फोटोशूट में भी हिस्सा लिया, जहां ऑस्ट्रेलियन ओपन जीत का जश्न मनाया गया।

हालांकि अल्काराज की गैरमौजूदगी के बावजूद रॉटरडैम ओपन का मैदान सितारों से सजा रहेगा। इस टूर्नामेंट में दुनिया के नंबर-2 अलेक्जेंडर ज्वेरेव, फेलिक्स ऑगर-अलियासिमे और एलेक्स डी मिनौर जैसे शीर्ष खिलाड़ी हिस्सा लेंगे।

वर्तमान में एटीपी रैंकिंग में दुनिया के नंबर-1 खिलाड़ी अल्काराज अपने करियर में अब तक 15 बड़े खिताब जीत चुके हैं। इनमें ग्रैंड स्लैम ट्रॉफियां, निट्टो एटीपी फाइनल्स, एटीपी मास्टर्स 1000 इवेंट्स और एक ओलंपिक सिंगल्स गोल्ड मेडल भी शामिल है।

भारतीय मूल के क्रिकेटरों का दबदबा, टी20 विश्व कप में विदेशी टीमों की ओर से खेलेंगे

नई दिल्ली **(एजेंसी)**। 7 फरवरी से शुरू हो रहे टी20 विश्व कप में इस बार सिर्फ भारत ही नहीं, बल्कि कई विदेशी टीमों में भी भारतीय मूल के क्रिकेटरों का दबदबा देखने को मिलेगा। करीब तीन दर्जन से अधिक भारतीय मूल के खिलाड़ी अलग-अलग देशों की ओर से मैदान में उतरेंगे और अपनी जन्मभूमि या कर्मभूमि पर खास छाप छोड़ने को बेकरार हैं।

कनाडा और अमेरिका इस मामले में सबसे आगे हैं, जहां भारतीय मूल के खिलाड़ियों की संख्या सबसे अधिक है। दिलचस्प बात यह है कि इनमें से कई खिलाड़ी भारत में जन्मे, यहीं क्रिकेट सीखा और अब विदेशी जर्सी में उसी धरती पर खेलते नजर आएंगे।

मुंबई में जन्मे अमेरिकी तेज गेंदबाज सौरभ नेत्रवलकर के लिए भारत के खिलाफ वानखेड़े स्टेडियम में खेलना किसी सपने से कम नहीं होगा। भारत की अंडर-19 टीम का हिस्सा रह चुके नेत्रवलकर अमेरिका की ओर से शानदार प्रदर्शन कर चुके हैं।

34 वर्षीय सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने पिछले विश्व कप में बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए अमेरिका को सुपर-8 तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई थी। 7 फरवरी को जब वह सूर्यकुमार यादव के खिलाफ गेंदबाजी करेंगे, तो भावनाओं पर काबू रखना उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती होगी।

आनंद में जन्मे मोनांक पटेल भारत के खिलाफ अमेरिका की कप्तानी करेंगे। 32 वर्षीय सलामी बल्लेबाज ने पिछले विश्व कप में पाकिस्तान के खिलाफ मैच जिताऊ अर्धशतक जमाया था। मोनांक और जसप्रीत बुमराह गुजरात अंडर-19 टीम में साथ खेल चुके हैं। मोनांक मानते हैं कि किशोरावस्था में ही उन्हें समझ आ गया था कि बुमराह एक दिन दुनिया के सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजों में शामिल होंगे। फगवाड़ा में जन्मे इटली के तेज गेंदबाज जसप्रीत सिंह 2006 में अपने परिवार के साथ मिलान चले गए थे। टेप-बॉल क्रिकेट से शुरुआत करने वाले इस खिलाड़ी ने 2019 में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में पदार्पण किया। कभी उबर ड्राइवर के रूप में काम करने वाले जसप्रीत के लिए आईसीसी टूर्नामेंट में खेलना सपने के सच होने जैसा है।

22 वर्षीय आर्यन दत्त, नीदरलैंड की टीम में भारतीय मूल के इकलौते खिलाड़ी हैं। 2023 वनडे विश्व कप में भारत में खेल चुके आर्यन इस बार भी बड़े उलटफेर की उम्मीद लगाए बैठे हैं। उनका परिवार 1980 के दशक में पंजाब से नीदरलैंड गया था और आज भी भारत से उनका भावनात्मक रिश्ता बना हुआ है।

गुरदासपुर में जन्मे दिलप्रीत बाजवा छह साल पहले कनाडा गए थे और अब उसी देश की कप्तानी करते हुए भारत लौटे हैं। पंजाब में उम्र-वर्ग क्रिकेट में रन बनाने के बावजूद मौके नहीं मिले, लेकिन कनाडा ग्लोबल टी20 लीग में चमकने के बाद उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। 23 वर्षीय बाजवा 2024 टी20 वर्ल्ड कप में भी कनाडा का हिस्सा थे।

लुधियाना में जन्मे जतिंदर सिंह ओमान की टीम की कप्तानी करेंगे। 36 वर्षीय जतिंदर एक दशक से ज्यादा समय से अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खेल रहे हैं, लेकिन भारत में खेलने का सपना अभी अधूरा है। ओमान के सभी लीग मुकाबले श्रीलंका में होने के कारण यह सपना इस बार भी पूरा होता नहीं दिख रहा।

टेनिस रैंकिंग : हार के बावजूद सबालेंका टॉप पर कायम, जोकोविच तीसरे नंबर पर पहुंचे

मेलबर्न **(एजेंसी)**। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 के बाद जारी हुई नई टेनिस रैंकिंग में कई बड़े बदलाव देखने को मिले हैं। पुरुष और महिला–दोनों वर्गों में फाइनल हार के बावजूद कुछ दिग्गज खिलाड़ियों ने अपनी मजबूत स्थिति बरकरार रखी है, जबकि कुछ सितारों ने लंबी छलांग लगाई है।

ऑस्ट्रेलियन ओपन के फाइनल में कार्लोस अल्काराज़ से हारने के बावजूद 24 बार के ग्रैंड स्लैम चैंपियन नोवाक जोकोविच को रैंकिंग में फायदा मिला है। जोकोविच एक पायदान ऊपर चढ़कर तीसरे स्थान पर पहुंच गए हैं। 38 वर्षीय सर्बियाई दिग्गज अगस्त 2024 के बाद पहली बार टॉप-3 में लौटे हैं।

वहीं, ऑस्ट्रेलियन ओपन के विजेता कार्लोस अल्काराज़ ने शानदार प्रदर्शन के दम पर एटीपी

नंबर-1 रैंकिंग बरकरार रखी है। दूसरे नंबर पर मौजूद यानिक सिनर को पीछे छोड़ते हुए अल्काराज़ शीर्ष पर कायम हैं। गौर है कि जोकोविच ने टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में सिनर को हराया था।

महिला वर्ग में एरीना सबालेंका को ऑस्ट्रेलियन ओपन फाइनल में एलेना रयबाकिना से हार का सामना करना पड़ा, लेकिन इसके बावजूद वह डब्ल्यूटीए नंबर-1 रैंकिंग पर बनी हुई हैं। रयबाकिना दो स्थान की छलांग लगाते हुए तीसरे नंबर पर पहुंच गई हैं, जबकि इगा स्वियातेक दूसरे स्थान पर बरकरार हैं। डब्ल्यूटीए रैंकिंग में चौथे से छठे स्थान तक अमेरिकी खिलाड़ियों का दबदबा देखने को मिला है। इनमें शामिल हैं: अमांडा अनिसिमोवा, कोको गॉफ, जेसिका पेगुला।

पद्म श्री मिलने पर भावुक हुए रोहित शर्मा, बोले- देश को मैच जिताने की कोशिश हमेशा जारी रहेगी

नई दिल्ली **(एजेंसी)**। पूर्व भारतीय कप्तान रोहित शर्मा को देश के प्रतिष्ठित नागरिक सम्मानों में शामिल पद्म श्री से नवाज़ा गया है। इस सम्मान को लेकर रोहित ने खुशी जताते हुए इसे अपने और अपने परिवार के लिए बेहद खास पल बताया और कहा कि भारत के लिए मैच और ट्रॉफी जीतने की उनकी कोशिश कभी नहीं रुकेगी।

पद्म श्री मिलने के बाद रोहित शर्मा ने भारत सरकार और अपने पूरे क्रिकेट सफर में साथ देने वाले लोगों का धन्यवाद किया। दूरदर्शन स्पोर्ट्स द्वारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर साझा किए गए वीडियो संदेश में रोहित ने कहा–

'पद्म श्री प्राप्त करना मेरे और मेरे परिवार के लिए बहुत ही खास पल है। मैं भारत सरकार का इस सम्मान के लिए आभार व्यक्त करता हूं। अपने करियर में मेरा साथ देने वाले सभी लोगों का भी धन्यवाद। देश के लिए मैच और ट्रॉफी जीतने की मेरी कोशिश हमेशा जारी रहेगी। धन्यवाद। जय हिंद।'

रोहित शर्मा ने वर्ष 2007 में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में पदार्पण किया था। बीते करीब 19 वर्षों में उन्होंने बल्लेबाज और कप्तान दोनों रूपों में भारतीय क्रिकेट पर गहरी छाप छोड़ी है। सभी प्रारूपों में उनकी निरंतरता और नेतृत्व क्षमता की दुनियाभर में सराहना हुई है।

पाकिस्तान विकेटकीपर ने की 'चीटिंग' वायरल स्टंपिंग ने टी20 वर्ल्ड कप से पहले आईसीसी नियमों पर छेड़ी बहस

नई दिल्ली **(एजेंसी)**। टी20 वर्ल्ड कप 2026 से ठीक पहले पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले गए तीसरे टी20 मैच की एक वायरल स्टंपिंग ने क्रिकेट जगत में हलचल मचा दी है। सोशल मीडिया पर सामने आए स्लो-मोशन वीडियो में दावा किया जा रहा है कि पाकिस्तानी विकेटकीपर ख्वाजा नफे ने आईसीसी के नियमों का उल्लंघन किया, फिर भी बल्लेबाज़ को आउट दे दिया गया।

लाहौर में खेले गए तीसरे टी20 आई में ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाज़ कूपर कॉनॉली को मोहम्मद नवाज़ की गेंद पर स्टंप आउट दिया गया। मैदान पर अंपायरों ने तुरंत उंगली उठा दी, लेकिन बाद में आए रिप्ले ने कहानी बदल दी।

स्लो-मोशन फुटेज में साफ दिखता है कि: विकेटकीपर ने दाएं हाथ में गेंद पकड़ी हुई थी, लेकिन बाएं हाथ से बेल्स गिराईं, यहीं से विवाद शुरू हुआ, क्योंकि आईसीसी के नियम इसके उलट कुछ और कहते हैं।

आईसीसी मेन्स टी20 आई प्लेइंग कंडीशंस के क्लॉज 29.2.1 के अनुसारः विकेट तभी सही तरीके से टूटता है, जब जिस हाथ से बेल्स गिराई जाएं, उसी हाथ में गेंद हो। इस मामले में गेंद उस हाथ में नहीं थी जिससे विकेट तोड़ा गया। नियम के मुताबिक, यह फेयर स्टंपिंग नहीं मानी जाती और बल्लेबाज़ को नॉट आउट दिया जाना चाहिए था। ऑस्ट्रेलिया पहले से ही संघर्ष कर रहा था (82/6) इस फैसले के बाद स्कोर हुआ 82/7, पूरी टीम 96 रन पर ऑलआउट, यह ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी टी20 आई हारों में से एक रही, हालांकि पाकिस्तान की जीत पर यह विवाद भारी पड़ गया।

खत्म हो चुका था करियर, कोई नहीं दे रहा था काम 5 डूबते सितारों को मिला 'द 50' का सहारा! फिर लौटेगी पुरानी चमक

मुंबई। टेलीविजन के नए रियलिटी शो 'द 50' का 1 फरवरी 2026, रविवार से प्रीमियर हो चुका है। इस शो में 10-20 नहीं बल्कि पूरे 50 सेलिब्रिटीज अपना कमाल दिखाने के लिए शामिल हुए हैं, लेकिन हम कुछ ऐसे सितारों के बारे में जानेंगे जिनके लिए ये शो 'लाइफ जैकेट' साबित हो सकते हैं।

कल तक जो सितारे करोड़ों दिलों पर राज करते थे, आज वही गुमनामी के अंधेरे में कहीं खो गए हैं। न हाथ में कोई बड़ा प्रोजेक्ट है और न ही काम देने वाला कोई बड़ा नाम, लेकिन कहते हैं कि बाजी तब पलटती है, जब खेल में कोई नया मोहरा आता है। कलर्स टीवी और जियो हॉटस्टार का नया रियलिटी शो 'द 50' उन्हीं सितारों के लिए एक संजीवनी बनकर आया है, जिनका करियर ट्रेड एनालिस्ट्स की नजर में लगभग खत्म हो चुका था। तो चलिए जानते हैं इस लिस्ट में किस-किस का नाम शामिल है। लिस्ट में पहला नाम 'ये है मोहब्बतें' में रमन भल्ला का किरदार निभाने वाले एक्टर करण पटेल का नाम है, जो कभी टीवी के सबसे महंगे और बड़े स्टार्स में शुमार थे, लेकिन पिछले कुछ सालों में उनके हाथ कोई प्रोजेक्ट नहीं लगा था,

पर अब उन्हें 'द 50' में देखा जा रहा है। 'बिग बॉस 6' की विनर और टीवी की सबसे खतरनाक विलेन की लिस्ट में शुमार उर्वशी ढोलकिया भी काफी लंबे समय से पर्दे से गायब हैं। लेकिन अब एक्ट्रेस ने 'द 50' से एक बार फिर वापसी की है और शो में उन्हें कैप्टन बनाया गया है। ऐसे में फैंस उम्मीद कर रहे हैं कि वो अपना पुराना जलवा एक बार फिर कायम कर सकती हैं।

'द 50' शो के पहले ही दिन करण पटेल से भिड़ने वाले सिद्धार्थ भारद्वाज एमटीवी 'स्प्लिट्सविला' के विनर और 'बिग बॉस 5' के रनर-अप रहे हैं। रियलिटी टीवी में अपनी खास पहचान बनाने के बाद अचानक वे पर्दे से गायब हो गए। वहीं अब करीब 1 दशक के बाद 'द 50' से उन्होंने वापसी की है। फेमस और अनूठे कॉमेडी-साइंस फिक्शन सीरियल 'बहु हमारी रजनीकांत' से घर-घर में अपनी पहचान बनाने वाली एक्ट्रेस रिद्धिमा पंडित पिछले काफी समय से पर्दे से दूर थीं। रिद्धिमा को बिग बॉस ओटीटी में देखा गया था, लेकिन उनका सफर कुछ खास नहीं था। ऐसे में अब वो खुद को साबित करने के लिए 'द 50' के मैदान में उतरी हैं।

मध्य रेल

वार्षिक रखरखाव

खुली निविदा सूचना सं. BB.M.LTT.TC. 52.EOT.10T.AMC dated 01.02.2026. कार्य का नाम: एलटीटी कोचिंग डिपो में EOT क्रेन, मेक-KRANE INDIA, क्षमता-10 टन, के DSL फिटमेंट और समग्र वार्षिक रखरखाव अनुबंध (CAMC) का 02 वर्षों की अवधि के लिए कार्य। **अंदाजित मूल्य:** ₹ 39,76,921.05/- (केवल उनतालीस लाख छिहत्तर हजार नौ सौ इक्कीस रुपये और पॉच पैसे मात्र), **कार्य समापन की तिथि:** 24 महीन, **बयाना राशि जमा:** ₹ 79,500.00/- (केवल उनासी हजार पांच सौ रुपये मात्र), **निविदा प्रस्तुत करने की समाप्ति का दिनांक और समय:** 23.02.2026 को 11.00 बजे तक। निविदाएं केवल वेबसाइट **www.ireps.gov.in** के माध्यम से ई-टेंडरिंग प्रारूप में स्वीकार की जाएंगी। **निविदा दस्तावेज वेबसाइट में उपलब्ध हैं। यह निविदा सार्वजनिक खरीद नीति आदेश 2017/दिनांक 15.06.2017 का अनुपालन करती है।**

सुरक्षित यात्रा करें, फुटबोर्ड पर यात्रा न करें 871

बृहन्मुंबई महानगरपालिका

(हाइड्रोलिक अभियंता विभाग)
पत्र क्रमांक : एचई/एईओसी/6039/टीएम दिनांक : 01.02.2026

ई-निविदा सूचना

बृहन्मुंबई महानगरपालिका के आयुक्त द्वारा पात्र निविदादारों से निम्नलिखित कार्यों के लिए ऑनलाइन निविदाएँ आमंत्रित की जाती हैं। निविदा प्रारंभ होने की तिथि एवं समय तथा निविदा समाप्त होने की तिथि एवं समय का विवरण महाटेंडर पोर्टल पर उपलब्ध विस्तृत निविदा सूचना में दिया गया है।

बोली क्रमांक : 2026_एमसीजीएम_1273233_1

कार्य का नाम : एईओसी (टीएम) विभाग के अंतर्गत मुलुंड से सायन तक ईस्टर्न एक्सप्रेस राजमार्ग की सर्विस रोड के पश्चिमी भाग में स्थित 3000 मि.मी. व्यास की मुंबई तृतीय ट्रंक मुख्य पाइपलाइन पर तथा उसके किनारे एयर वाल्व, मैनहोल, स्लूस वाल्व, बटरफ्लाई वाल्व आदि विभिन्न कक्षों में एम.एस. (माइल्ड स्टील) सीढ़ियों की स्थापना का कार्य।

इच्छुक निविदादार निविदा से संबंधित अधिक जानकारी के लिए महाटेंडर पोर्टल की वेबसाइट http://mahatenders.gov.in पर अवश्य जाएँ।

कार्यकारी अभियंता
(मुख्य कार्य) जल कार्य विभाग

पीआरओ/2845/विज्ञा./2025-26

भोजन से पूर्व एवं शौच के बाद साबुन से हाथ स्वच्छ धोएं।

18 फीसदी अमेरिकी शुल्क से वैश्विक विनिर्माण केंद्र के रूप में भारत का आकर्षण बना रहेगा: आइसीईए

नई दिल्ली **(एजेंसी)**। मोबाइल उद्योग के निकाय आइसीईए ने मंगलवार को कहा कि भारत से अमेरिका को होने वाले निर्यात पर तय की गई 18 प्रतिशत की शुल्क दर एक वैश्विक विनिर्माण और निर्यात केंद्र के रूप में भारत के आकर्षण को बनाए रखेगी। भारत और अमेरिका एक व्यापार समझौते पर सहमत हुए हैं, जिसके तहत वाशिंगटन भारतीय सामानों पर जवाबी शुल्क को मौजूदा 25 प्रतिशत से घटाकर 18 प्रतिशत कर देगा।

आइसीईए के चेयरमैन पंकज महेंद्रू ने एक बयान में कहा, ''यह भारत के लिए एक सकारात्मक परिणाम है। इस शुल्क दर के साथ भारत प्रमुख विनिर्माण प्रतिस्पर्धियों के मुकाबले बेहतर स्थिति में है और एक वैश्विक विनिर्माण एवं निर्यात केंद्र के रूप में अपना आकर्षण बरकरार रखे हुए है।'' उन्होंने आगे कहा कि हालांकि हम सौदे के विस्तृत विवरण का इंतजार कर रहे हैं लेकिन यह दिशा स्पष्ट रूप से विनिर्माण को बढ़ाने और अमेरिका के नेतृत्व वाली वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं, विशेष रूप से इलेक्ट्रॉनिक्स में गहराई से जुड़ने की भारत की रणनीति का समर्थन करती है।

सूत्रों के अनुसार मोबाइल फोन और सेमीकंडक्टर सहित इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पाद शुल्क से मुक्त बने हुए हैं। वित्त वर्ष 2024-25 में भारत का इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन लगभग 19 प्रतिशत बढ़कर 11.3 लाख करोड़ रुपये हो गया और निर्यात 37.5 प्रतिशत बढ़कर 3.3 लाख करोड़ रुपये रहा।

महाराष्ट्र शासन

सार्वजनिक बांधकाम विभाग

निविदा सूचना क्र. ७४ सन २०२५-२६

कार्यकारी अभियंता, एकात्मिकृत घटक (सा.बां.) विभाग, २ रामजला, बांधकाम भवन, २५ मर्झबान रोड, मुंबई-४०० ००१ दुरध्वनी क्र.०२२-२२०१६९७४/७६ हे खालील कामे सा.बां. विभाग सुशिक्षित बेरोजगार अभियंता, यांचेसाठी मागवित आहेत. कोऱ्या निविदेचा नमुना कार्यकारी अभियंता, एकात्मिकृत घटक (सा.बां.) विभाग, २ रा मजला, बांधकाम भवन, २५ मर्झबान रोड, मुंबई यांचे कार्यालयातून दि. ०३/०२/२०२६ ते दि. १०/०२/२०२६ दुपारी १५.०० पर्यंत देण्यात यईल. भरुन पाठविलेल्या निविदा दि. १२/०२/२०२६ रोजी त्यादिवशी दुपारी १५.०५ वाजेपर्यंत स्विकारतील आणि शक्यतो त्याच दिवशी उघडतील.

अ. क्र.	कामांचे नांव	अंदाजित किंमत (रूपये)	इसारा रक्कम (रूपये)	वर्ग	काम पूर्ण करण्याची कालमर्यादा	निविदेचा नमूना प्रकार	को-या निविदा नमुन्याचा किंमत (रूपये)
१	Repairs and fabrication of Security gates at Sir J.J. Hospital Compound, Mumbai.	७६३८३९/-	८०००/-	वर्ग- ७ व वरील	१०० दिवस	ब-१	रु. ५९० /-
२	Repairs and renovation of Pump room and water tank of admin building at Sir J.J. Group of Hospital, Mumbai.	६९३७७३/-	७०००/-	वर्ग-७ व वरील	१०० दिवस	ब-१	रु. ५९० /-
३	Construction and Providing water tank platform No.1 of Terrace at OPD Building, G.T. Hospital, Mumbai.	८३००५३/-	९०००/-	वर्ग-७ व वरील	१०० दिवस	ब-१	रु. ५९० /-
४	Providing and Construction of M.S. Grill and Collapsible gate near Servant Quarters and in Prince of Walse Building and Chamber Cover in the Premises of G.T. Hospital, Mumbai.	८४०५३३/-	९०००/-	वर्ग-७ व वरील	१०० दिवस	ब-१	रु. ५९० /-
५	Construction and providing water tank Platform No.2 Terrace at OPD Building, G.T. Hospital, Mumbai.	८२३५०३/-	९०००/-	वर्ग-७ व वरील	१०० दिवस	ब-१	रु. ५९० /-
६	Construction and Providing water tank Platform at Terrace North and South Side at Main Building at G.T. Hospital, Mumbai. (Part-1)	८३४२५६/-	९०००/-	वर्ग-७ व वरील	१०० दिवस	ब-१	रु. ५९० /-
७	Construction and Providing water tank Platform at Terrace West Side at Main Building at G.T. Hospital, Mumbai.	८२८०७०/-	९०००/-	वर्ग-७ व वरील	१०० दिवस	ब-१	रु. ५९० /-
८	MOW Repairs to renovation Plaster, painting, flooring, toilet to room No.303 & 304, 3rd floor at Low rise Building at G.T. Hospital, Mumbai.	८३२३५३/-	९०००/-	वर्ग-७ व वरील	१०० दिवस	ब-१	रु. ५९० /-
९	MOW Repairs to renovation plaster, painting, flooring, toilet to room No.203 & 602, 2nd & 6th floor at Low rise Building at G.T. Hospital, Mumbai.	८३३४५३/-	९०००/-	वर्ग-७ व वरील	१०० दिवस	ब-१	रु. ५९० /-
१०	Providing and fixing furniture work of RMO room on Ground floor at St. Georges Hospital, Mumbai.	६९५३१६/-	७०००/-	वर्ग-७ व वरील	१०० दिवस	ब-१	रु. ५९० /-
११	Upgradation and renovation of OPD Mumbai No.6 on Ground floor at St. Georges Hospital, Mumbai.	८३७८३७/-	९०००/-	वर्ग-७ व वरील	१०० दिवस	ब-१	रु. ५९० /-
१२	Upgradation and renovation of RMO room on Ground floor at St. Georges Hospital, Mumbai.	८३४४८४/-	९०००/-	वर्ग-७ व वरील	१०० दिवस	ब-१	रु. ५९० /-
१३	Upgradation and renovation of OPD No.9 on Ground floor at St. Georges Hospital, Mumbai.	८७७१०४/-	९०००/-	वर्ग-७ व वरील	१०० दिवस	ब-१	रु. ५९० /-
१४	Providing and fixing furniture work of OPD No.9 on Ground floor at St. Georges Hospital. Mumbai.	८८०५००/-	९०००/-	वर्ग-७ व वरील	१०० दिवस	ब-१	रु. ५९० /-
१५	Carrying out detailed Traverse, Level with Internal Ley out plan for High Rise and Low Rise Building, Servant Quarters, Class-IV Quarters at G.T. Hospital, Badruddin Tayyabaji Marg, at Fort, Mumbai.	८१०९६०/-	९०००/-	वर्ग-७ व वरील	१०० दिवस	ब-१	रु. ५९० /-

कार्यकारी अभियंता, एकात्मिकृत घटक (सा.बां) विभाग, मुंबई यांचे कार्यालयामध्ये सूचना फलकावर सविस्तर निविदा सूचना पहावयास मिळेल एक किंवा सर्व निविदा कोणतेही कारण न देता रद्द ठरविण्याचा अधिकार राखून ठेवला आहे.

जा.क्र.एघ (सा.बा) वि/निविदा/ ६५२१
कार्यकारी अभियंता यांचे कार्यालय,
एकात्मिकृत घटक (सा.बां) विभाग,
बांधकाम भवन, २ रा मजला,
२५ मर्झबान रोड, फोर्ट, मुंबई-४०० ००१
दूरध्वनी क्र. २२०१६९७४/७६
दिनांक : ८/१२/२०२४

कार्यकारी अभियंता
एकात्मिकृत घटक (सा.बां) विभाग,
फोर्ट, मुंबई

DGIPR/2025-26/5526

आईसीएमएआई कानपुर चैप्टर में 'बजट-2026' पर कार्यशाला आयोजित

मुख्य वक्ताओं ने बजट को आत्मनिर्भर एवं विकसित भारत की दिशा में सशक्त कदम बताया

कानपुर।द इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (आईसीएमएआई), कानपुर चैप्टर (कानपुर विद्या मंदिर), स्वरूप नगर, कानपुर में मंगलवार को 'बजट-2026' विषय पर एक कार्यशाला का आयोजन किया गया।

कार्यशाला के मुख्य वक्ता सीएमए आर. के. शुक्ला ने केंद्रीय बजट 2026 पर विस्तार से प्रकाश डालते हुए कहा कि यह बजट देश को आत्मनिर्भर बनाने तथा वर्ष 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने बताया कि बजट का मुख्य फोकस गरीब, महिला, युवा और किसानों के समग्र विकास पर केंद्रित है। उन्होंने कहा कि विनिर्माण (मैन्युफैक्चरिंग) और एमएसएमई क्षेत्र के विकास के लिए सरकार द्वारा ठोस कदम उठाए गए हैं। शहरी विकास, आवास, ऊर्जा, सड़क और रेलवे क्षेत्र में बड़े पैमाने पर निवेश किया जा रहा है। अनुसंधान एवं विकास (आर एंड डी) के लिए भी भारी मात्रा में धनराशि का आवंटन किया गया है।

बजट में 500 शीर्ष कंपनियों में 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप का अवसर देने का प्रावधान किया गया है। मुद्रा ऋण की सीमा बढ़ाकर 20 लाख रुपये कर दी गई है। महिलाओं से संबंधित योजनाओं के लिए 3 लाख करोड़ रुपये से अधिक का आवंटन किया गया है। सोने और चांदी पर सीमा शुल्क घटाकर 6 प्रतिशत कर दिया गया है, जबकि कैंसर की दवाओं को सीमा शुल्क से पूर्णतः मुक्त किया गया है।

संस्थान के सचिव सीएमए अजय शर्मा ने बताया कि इस बार रक्षा बजट में ऐतिहासिक वृद्धि की गई है। कुल 7.85 लाख करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है, जो सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का लगभग 2 प्रतिशत है। उन्होंने कहा कि पूंजीगत व्यय के लिए पिछले वर्ष की तुलना में 22 प्रतिशत अधिक राशि का प्रावधान किया गया है।

कानपुर चैप्टर के चेयरमैन सीएमए ए. के. श्रीवास्तव ने कहा कि बजट में आधुनिकीकरण और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के लिए ठोस एवं दूरदर्शी कदम उठाए गए हैं। वहीं वाइस चेयरमैन सीएमए एस. के. वर्मा ने कहा कि यह बजट महिला सशक्तीकरण, युवाओं, किसानों और गरीब वर्ग को केंद्र में रखकर तैयार किया गया है।

संयुक्त सचिव सीएमए (डॉ.) आशुतोष मिश्रा ने बजट को दूरगामी सकारात्मक परिणाम देने वाला बताते हुए कहा कि यह देश को विकास की नई दिशा प्रदान करेगा।

कार्यक्रम में सीएमए अनिल कुमार राजपूत, सीएमए सीनक मल्ल, सीएमए सुधीर सक्सेना, राजकिशोर सहित बड़ी संख्या में सीएमए सदस्य एवं छात्र-छात्राएं उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन सीएमए हरिओम मिश्रा ने किया।

अमेरिका के साथ व्यापार समझौते से भारत की वृद्धि को मिलेगी गति : उद्योग जगत

नई दिल्ली **(एजेंसी)**। भारतीय उद्योग जगत के दिग्गजों ने मंगलवार को कहा कि भारत-अमेरिका व्यापार समझौता भारत की वृद्धि महत्वाकांक्षाओं को गति प्रदान देगा। उन्होंने साथ ही कहा कि इससे देश को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी विनिर्माण एवं नवाचार केंद्र बनाने में मदद मिलेगी।

भारती एंटरप्राइजेज के संस्थापक एवं चेयरमैन सुनील मित्तल से लेकर आदित्य बिड़ला समूह के कुमार मंगलम बिड़ला और महिंद्रा समूह के अनीश शाह तक भारतीय उद्योग जगत के दिग्गजों ने द्विपक्षीय व्यापार और निवेश परिदृश्य को बदलने की इसकी क्षमता को रेखांकित करते हुए इस ऐतिहासिक समझौते पर प्रतिक्रिया व्यक्त की।

दोनों देशों के बीच हुए इस व्यापार समझौते पर प्रतिक्रिया देते हुए महिंद्रा ग्रुप के सीईओ और प्रबंध निदेशक अनीश शाह ने इसे द्विपक्षीय व्यापार और निवेश संबंधों को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया।

उन्होंने कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था के मजबूत वृद्धि पथ पर होने के साथ, यह सौदा भारत की वृद्धि महत्वाकांक्षाओं को सार्थक गति प्रदान करता है। भारती एंटरप्राइजेज के संस्थापक और चेयरमैन सुनील भारती मित्तल ने कहा कि भारत-अमेरिका व्यापार समझौता दोनों देशों के लिए बहुप्रतीक्षित और महत्वपूर्ण उपलब्धि है, जो निवेश और वृद्धि के लिए अपार अवसर खोलता है। मित्तल ने कहा, मुक्त व्यापार समझौतों की श्रृंखला यह प्रमाण है कि भारत वैश्विक ढांचों के केंद्र में अपनी भूमिका निभा रहा है, जिसका उद्देश्य मजबूत अंतरराष्ट्रीय व्यापार रूपरेखा तैयार करना है।

आदित्य बिड़ला ग्रुप के चेयरमैन कुमार मंगलम बिड़ला ने कहा कि कम शुल्क से इन दो महान देशों के बीच रणनीतिक और आर्थिक संबंधों को मजबूत करने में मदद मिलेगी और निवेश तथा सहयोग के अतिरिक्त अवसर मिलेंगे। यह बताते हुए कि आदित्य बिड़ला ग्रुप अमेरिका में सबसे बड़ा भारतीय निवेशक है, उन्होंने कहा कि यह समझौता अधिक लचीली आपूर्ति श्रृंखला बनाने, विनिर्माण के अवसरों को खोलने और अमेरिका तथा भारत में दीर्घकालिक आर्थिक प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने में मदद करेगा। टीवीएस मोटर कंपनी के चेयरमैन सुदर्शन वेणु ने भी कहा कि भारतीय सामानों पर अमेरिकी जवाबी शुल्क को घटाकर 18 प्रतिशत करना एक सकारात्मक कदम है, जो निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार करता है और दीर्घकालिक द्विपक्षीय आर्थिक संबंधों में विश्वास पैदा करता है।

पाकिस्तान में फिर पोलियो रोधक टीम बनी निशाना, हमले में पुलिसकर्मी की मौत

पेशावर **(एजेंसी)**। उत्तर-पश्चिमी पाकिस्तान के अशांत खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में अज्ञात बंदूकधारियों ने पोलियो टीकाकरण टीम को निशाना बनाते हुए गोलीबारी की जिसमें टीम की सुरक्षा में तैनात एक पुलिसकर्मी की मौत हो गई। पुलिस ने मंगलवार को यह जानकारी दी। यह घटना सोमवार को अफगानिस्तान की सीमा से लगे उत्तरी वजीरिस्तान जिले की मीर अली तहसील में हुई।

हमले के बाद हमलावर मौके से फरार हो गए। पुलिस ने बताया कि घटना की सूचना मिलते ही पुलिस दल घटनास्थल पर पहुंचा और पूरे इलाके की घेराबंदी की। क्षेत्र में हमलावरों की तलाश के लिए अभियान शुरू किया गया है। पाकिस्तान में पिछले एक दशक में पोलियो कर्मियों और उनकी सुरक्षा में तैनात सुरक्षाकर्मियों पर बार-बार हमले हुए हैं, विशेष रूप से खैबर पख्तूनख्वा के कुछ हिस्सों में। इन खतरों के बावजूद, सरकार कड़े सुरक्षा इंतजामों के बीच देशव्यापी पोलियो अभियान जारी रखे हुए है।

केन्द्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने 1,237 लाभार्थियों को सहायक उपकरण किए वितरित

अशोकनगर/भोपाल। केन्द्रीय संचार एवं पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री तथा गुना सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कल सोमवार को अपने संसदीय क्षेत्र के अशोकनगर जिले के मरूप गाँव में आयोजित भव्य 'दिव्यांगजन एवं वृद्धजन सहायक उपकरण वितरण शिविर' में संवेदना और सम्मान के संकल्प को साकार किया। इस अवसर पर उन्होंने 1237 दिव्यांगजनों और वरिष्ठ नागरिकों को आधुनिक सहायक उपकरण वितरित करते हुए कहा कि यह आयोजन केवल उपकरण वितरण नहीं, बल्कि आत्मसम्मान, आत्मनिर्भरता और सामाजिक समावेशन की दिशा में एक सशक्त कदम है।

सेवा की सिंधिया परंपराः शासन नहीं, कर्तव्य

सभा को संबोधित करते हुए केन्द्रीय मंत्री ने कहा कि ग्वालियर-चंबल अंचल में सेवा सिंधिया परिवार के लिए शासन का विषय नहीं, बल्कि पीढ़ियों से निभाया जा रहा एक पवित्र कर्तव्य रहा है। उन्होंने स्पष्ट किया कि अशोकनगर मे 1456, गुना में 1745 और शिवपुरी में 5250 सहित कुल पूरे संसदीय क्षेत्र में 8,240 दिव्यांगजनों तक सेवा पहुँचाने का लक्ष्य किसी आँकड़े तक सीमित नहीं है, बल्कि यह 8,240 परिवारों की आशा, गरिमा और भविष्य से जुड़ा संकल्प है।

आत्मसम्मान की नई भाषा प्रधानमंत्री मोदी का 'दिव्यांग' विजनः सिंधिया

केन्द्रीय मंत्री सिंधिया ने रेखांकित किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 'विकलांग' के स्थान पर 'दिव्यांग' शब्द देकर देश की सोच, संवेदना और दृष्टिकोण को नई दिशा दी है। उन्होंने ऋषि अष्टावक्र, वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग और पैरालंपिक स्वर्ण पदक विजेता देवेंद्र झाझरिया जैसे उदाहरणों के माध्यम से कहा कि सामर्थ्य

शरीर की सीमाओं से नहीं, बल्कि संकल्प और आत्मविश्वास से जन्म लेता है। यह उदाहरण दिखाते हैं कि दिव्यांगजन हमारे राष्ट्र निर्माण की सामूहिक जिम्मेदारी के सहभागी हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने दिव्यांगजनों की विशेषता को पहचानते हुए देश के इतिहास में पहली बार दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 में संसद में पारित किया और दिव्यांगजनों के लिए आवंटन राशि को 330 करोड़ से 5 गुना बढ़ाकर 2000 करोड़ तक पहुंचाया। पूरे देश में पिछले 12 वर्षों में भाजपा सरकार द्वारा 18000 से अधिक शिविर लगाए गए हैं जहां 21 लाख से अधिक दिव्यांगजनों को सशक्तिकरण की ओर अग्रसर किया गया है। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में रेल विभाग ने दिव्यांग ई टिकटिंग फोटो पहचान पत्र जारी किया है जिससे दिव्यांगजनों को विशिष्ट रूप से टिकट मिलने की सुविधा मिलेगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 32 दिव्यांगजनों को राष्ट्रपति सम्मान से सम्मानित किया है। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉ वीरेंद्र सिंह को भी इस पहल के लिए धन्यवाद किया।

सम्मान, सेवा और सहभागिता का संकल्प

अपने संबोधन के अंत में केन्द्रीय मंत्री ने कहा, 'आपका यह सैनिक आपके सम्मान, सशक्तिकरण और आत्मनिर्भरता के लिए सदैव आपके साथ खड़ा रहेगा और आपके लिए लड़ेगा।' उन्होंने सभी नागरिकों से 'विकसित भारत 2047' के संकल्प में सहभागी बनने और दिव्यांगजनों को समाज के मुख्यधारा में और सशक्त रूप से जोड़ने का आह्वान किया।

कोस्टा रिका की राजनीति में बड़ा मोड़

रूढ़िवादी लौरा फर्नांडीज ने जीता राष्ट्रपति पद का चुनाव

सैन होज़े **(एजेंसी)**। कोस्टा रिका में रूढ़िवादी जनवादी नेता लौरा फर्नांडीज ने राष्ट्रपति पद का चुनाव जीत लिया है। उन्होंने निवर्तमान राष्ट्रपति रोड्रिगो चावेस द्वारा शुरू किए गए देश की राजनीति के आक्रामक पुनर्गठन को आगे बढ़ाने का वादा किया है। प्रारंभिक और आंशिक नतीजों के अनुसार, फर्नांडीज ने पहले ही दौर में निर्णायक जीत हासिल की, जिससे दूसरे चरण की जरूरत नहीं पड़ी। सर्वोच्च चुनावी न्यायाधिकरण के मुताबिक, 96.8 प्रतिशत मतदान केंद्रों की गिनती पूरी होने तक 'सॉवरेन पीपुल्स पार्टी' की फर्नांडीज को 48.3 प्रतिशत वोट मिले। उनके निकटतम प्रतिद्वंद्वी 'नेशनल लिबरेशन पार्टी' के अर्थशास्त्री आल्वारो रामोस को 33.4 प्रतिशत वोट प्राप्त हुए। राष्ट्रपति चुनाव के पहले दौर में जीत के लिए कम से कम 40 प्रतिशत वोट आवश्यक थे। सोमवार को फर्नांडीज ने कहा कि अगले राष्ट्रपति के रूप में उनकी सबसे बड़ी इच्छा देश के विकास को सुदृढ़ करना, वैश्विक चुनौतियों का बेहतर सामना करना और मजबूत आर्थिक वृद्धि सुनिश्चित करना है। रामोस ने हार स्वीकार करते हुए ''रचनात्मक विपक्ष'' की भूमिका निभाने का वादा किया।

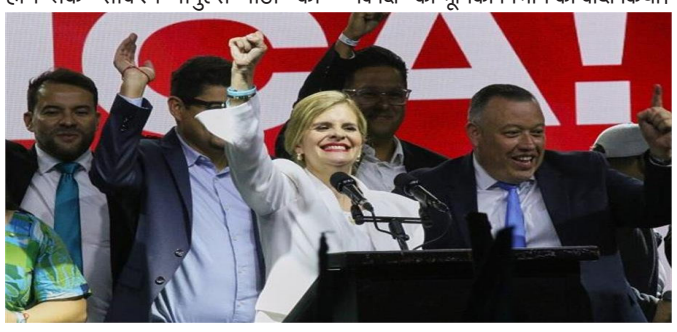

ईरान प्रदर्शनों का काला व भयावह सच

सुरक्षा बलों ने महिलाओं से रेप किए व गर्भाशय निकाला, सिर की खाल तक नोच दी

तेहरान **(एजेंसी)**। ईरान प्रदर्शनों का काला व भयावह सच सामने आया है जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। ईरान में सरकार-विरोधी प्रदर्शनों के दौरान सुरक्षा बलों की कार्रवाई को लेकर बेहद गंभीर मानवाधिकार आरोप सामने आए हैं। ईरानी-जर्मन पत्रकार माइकल अब्दुल्लाही ने दावा किया है कि प्रदर्शनों को दबाने के लिए ईरानी शासन ने महिलाओं के खिलाफ यौन हिंसा और अमानवीय व्यवहार को हथियार की तरह इस्तेमाल किया।एक ईरानी-जर्मन पत्रकार के अनुसार, ईरान में प्रदर्शनकारियों पर की गई कार्रवाई में सिर्फ हजारों लोगों की हत्या ही नहीं हुई, बल्कि महिलाओं के खिलाफ बलात्कार और अंग-भंग को भी हथियार की तरह इस्तेमाल किया गया।

यूरोपीय मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, हिरासत में ली गई कई महिला प्रदर्शनकारियों को धमकियां दी गईं, उनके साथ दुर्व्यवहार हुआ और उन्हें शारीरिक व मानसिक यातनाएं दी गईं। जर्मन अखबार डाइ वेल्ट में प्रकाशित प्रत्यक्षदर्शियों के बयानों में भी हिरासत के दौरान महिलाओं के साथ गंभीर अत्याचार के आरोप लगाए गए हैं।अब्दुल्लाही ने प्रत्यक्षदर्शियों के हवाले से कहा कि प्रदर्शन में शामिल महिलाओं के साथ बलात्कार किया गया, उनके गर्भाशय निकाल दिए गए, सिर की खाल उधेड़ दी गई और शरीर पर सिगरेट से जलाने के निशान बनाए गए। अब्दुल्लाही ने सोशल मीडिया पर साझा किए गए अपने बयानों में कहा कि उन्हें ऐसे कई प्रत्यक्ष विवरण मिले हैं, जिनमें इस्लामी शासन का विरोध करने वाली महिलाओं को निशाना बनाए जाने की बात कही गई है। ये आरोप ऐसे समय सामने आए हैं, जब दिसंबर 2025 से शुरू हुए आर्थिक संकट विरोधी प्रदर्शन

धीरे-धीरे ईरान में व्यापक सरकार-विरोधी आंदोलन में बदल गए। ब्रिटिश अखबार द गार्डियन और मानवाधिकार संगठनों की रिपोर्टों में भी हिरासत में महिला प्रदर्शनकारियों के साथ यौन हिंसा और क्रूरता के आरोप सामने आए हैं। रिपोर्टों के अनुसार, प्रदर्शनों को दबाने के लिए सरकार ने इंटरनेट सेवाएं बंद कर दीं और आईआरजीसी की बसीज मिलिशिया सहित अतिरिक्त बलों को तैनात किया गया।

ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई ने इन प्रदर्शनों को इस्लामी शासन को गिराने की 'विदेशी साजिश' करार दिया है। मृतकों की संख्या को लेकर अलग-अलग आंकड़े सामने आए हैं सरकारी आंकड़ों और अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों के अनुमानों में बड़ा अंतर बताया जा रहा है। मानवाधिकार संगठनों का कहना है कि कई मामलों की जांच अभी जारी है। अब्दुल्लाही के अनुसार, भारी दमन और जनहानि के बावजूद ईरान में सरकार-विरोधी आवाजें पूरी तरह शांत नहीं हुई हैं और देश गहरे सामाजिक आघात के दौर से गुजर रहा है।

शशिकला का डीएमके पर बड़ा हमला- खत्म होगा वंशवादी शासन, आएगी जनता की सरकार

चेन्नई **(एजेंसी)**। ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुन्नेत्र कज़गम (एआईएडीएमके) की निष्कासित अम्मा पेरावई शाखा की महासचिव वी.के. शशिकला ने मंगलवार को केंद्रीय बजट 2026 पर निराशा व्यक्त करते हुए कहा कि व्यक्तिगत आयकर स्लैब में कोई बदलाव न होना जनता के लिए निराशाजनक है। चेन्नई के मरीना बीच स्थित पूर्व मुख्यमंत्री पेरागनर अन्ना के स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित करने के बाद शशिकला ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि तमिलनाडु की जनता अच्छी तरह जानती है कि गद्दार कौन हैं और असली विरोधी कौन हैं।

शशिकला ने जोर देकर कहा कि उनका मुख्य उद्देश्य पुरची थलाइवर एमजीआर और पुरची थलाइवी जयललिता के शासन को वापस लाना है, जो पार्टी के पूर्व नेताओं की विरासत को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि मेरी योजना तमिलनाडु में पुरची थलाइवर और अम्मा द्वारा दिखाए गए मार्ग का अनुसरण करने की है। उन्होंने आगे कहा कि अपने 39 वर्षों के राजनीतिक अनुभव के साथ, वह डीएमके सरकार को हराने और सत्ता से बेदखल करने के लिए हर संभव प्रयास करेंगी।

उन्होंने दृढ़ता से कहा कि पुरची थलाइवर, पुरची थलाइवी और मेरे समर्पित पार्टी कार्यकर्ता मैदान में डटे रहेंगे। इससे पहले, शशिकला ने सत्ताधारी डीएमके पर तीखा हमला करते हुए दावा किया कि राज्य में वंशवादी शासन जल्द ही समाप्त हो जाएगा और उसकी जगह एक 'जनता की सरकार' आएगी। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। इस वर्ष तमिलनाडु में चल रहा वंशवादी शासन समाप्त होगा और जनता की सरकार का उदय होगा। डीएमके सरकार के सत्ता में आने के बाद से तिरुत्तानी हमले जैसी कई आपराधिक घटनाएं घटित हुई हैं। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पुलिस विभाग के प्रभारी हैं, लेकिन उन्होंने अभी तक इस घटना पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है।

आर्मेनिया के डिफेंस मिनिस्टर से मिले सीडीएस जनरल अनिल चौहान, रक्षा सहयोग पर उच्चस्तरीय वार्ता की

येरेवान **(एजेंसी)**। भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (सीडीएस) जनरल अनिल चौहान की नेतृत्व वाली भारतीय रक्षा टीम ने आर्मेनिया में उच्च स्तरीय वार्ता की और दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग को मजबूत करने पर चर्चा की। वार्ता में विभिन्न सुरक्षा और रणनीतिक मुद्दों पर सहयोग बढ़ाने के तरीके शामिल रहे। बैठक के बाद इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ (आईडीएस) मुख्यालय ने एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर कहा कि जनरल चौहान ने आर्मेनिया के रक्षा मंत्री सुरेन पापक्यान से मुलाकात की। बातचीत में दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग को बढ़ाने पर जोर दिया गया। जनरल चौहान ने आर्मेनिया की नेशनल डिफेंस रिसर्च यूनिवर्सिटी में छात्रों और फैकल्टी को संबोधित करते हुए वैश्विक सुरक्षा माहौल, संरचनात्मक परिवर्तन और तकनीक के महत्व पर चर्चा की। उन्होंने युद्ध की बदलती प्रकृति, सैन्य मामलों में क्रांति और मल्टी-डोमेन ऑपरेशन (मल्टी-डोमेन युद्ध) पर जोर दिया। उन्होंने साइबर, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, स्पेस और कॉग्निटिव डोमेन जैसे नए युद्धक्षेत्रों के बारे में भी बात की। इसके बाद सीडीएस ने आर्मेनियाई सशस्त्र बलों के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल एडवर्ड अस्रियन से भी मुलाकात की और दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग को और मजबूत करने पर चर्चा की। आईडीएस मुख्यालय ने कहा कि इस बातचीत ने रणनीतिक साझेदारी को गहरा करने और क्षमता विकास को बढ़ावा देने की साझा प्रतिबद्धता को दर्शाया।

जनरल चौहान ने यरेवन में वज़्गेन सारग्स्यान मिलिट्री अकादमी में आईटी लैब और डिस्टेंस लर्निंग सेंटर का उद्घाटन भी किया। भारतीय रक्षा दल रविवार को चार दिवसीय आधिकारिक दौरे पर आर्मेनिया पहुंचा था। इस दौरे को दोनों देशों के बीच दीर्घकालिक रक्षा और सुरक्षा सहयोग को आगे बढ़ाने वाला महत्वपूर्ण कदम बताया जा रहा है।

दक्षिण अफ्रीका का युद्धपोत 'एसएएस अमाटोला' भारत के लिए रवाना, नौसैनिक अभ्यास आईएफआर में लेगा भाग

केप टाउन **(एजेंसी)**। दक्षिण अफ्रीकी नौसेना का जंगी जहाज 'एसएएस अमाटोला' भारत के लिए एक रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण तैनाती पर रवाना हो गया है, जहां यह भारतीय नौसेना द्वारा आयोजित 2026 'अंतरराष्ट्रीय बेड़ा समीक्षा और अभ्यास मिलन' में दक्षिण अफ्रीका का प्रतिनिधित्व करेगा। रविवार को जहाज के रवाना होने के बाद दक्षिण अफ्रीकी नौसेना ने एक बयान में कहा, ''एसएएस अमाटोला की भारत यात्रा कई स्तरों पर महत्वपूर्ण है।'' बयान में कहा गया है, ''यह तैनाती दक्षिण अफ्रीका की समुद्री रणनीति के लिए एक अहम पड़ाव है, जो हिंद महासागर क्षेत्र में बहुपक्षीय नौसैनिक सहयोग में सक्रिय योगदानकर्ता के रूप में दक्षिण अफ्रीकी नौसेना की भूमिका की पुष्टि करती है।

यह लंबे समय के बाद दूरस्थ तैनातियों की एक संतुलित वापसी को भी दर्शाती है, जिसे सावधानीपूर्वक योजना, अनुशासित प्राथमिकताओं और पेशेवर संकल्प के साथ अंजाम दिया गया है।'' दक्षिण अफ्रीकी नौसेना के अनुसार, इस तैनाती में भारतीय नौसेना की अंतरराष्ट्रीय बेड़ा समीक्षा (आईएफआर) और अभ्यास मिलन में भागीदारी शामिल है। यह एक बड़ा बहुराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास है, जिसका उद्देश्य आपसी समन्वय, समुद्री सुरक्षा अभियानों और भागीदार देशों के बीच रणनीतिक संवाद को मजबूत करना है। बयान में कहा गया है कि इन आयोजनों में कई देशों की नौसेनाएं भाग लेती हैं और हिंद महासागर क्षेत्र में सुरक्षा, स्थिरता और सहयोग की साझा जिम्मेदारियों पर ध्यान केंद्रित किया जाता है।

Facebook: https://www.facebook.com/profile.phpid=100063787346044 Twitter: https://twitter.com/mantrabharatt=8tJONQ7H-h6EKqqap2tVMw&s=08 Mobile No: 7007837917

मंत्र भारत : R.N.I. MAHHIN/ 2016/65841 स्वात्वाधिकारी राकेश शर्मा के लिए राकेश शर्मा द्वारा AIS Printing solution प्लॉट नं0-A- 544 TTC इंडस्ट्रियल एरिया एमआईडीसी माहपे-नवी मुंबई, थाने 400709 से मुद्रित एवं शाप.नं. 36, द्वितीय तल, प्लाट -490.1. जाम मील बिल्डिंग, डॉ बाबा साहेब अम्बेकर रोड, लाल बाग परेल, मुम्बई-400012प्रकाशित एवं सम्पादित । कार्यालय : शाप.नं. 36, द्वितीय तल, प्लाट -490.1. जाम मील बिल्डिंग, डॉ बाबा साहेब अम्बेकर रोड, लाल बाग परेल, मुम्बई-400012 । फोन : 022-24706563 । कार्यकारी सम्पादक- योगेन्द्र चौधरी
E-Mail : editormantrabharat@gmail.com mantrabharatmumbai@gmail.com । सम्पादक : विनोद आर शर्मा, मोबाइल : 7007837917 । समूह सम्पादक : डॉ दयानन्द तिवारी। दैथानिक सूचना : मंत्र भारत से संबंधित समस्त विवाद निपटारे के लिए मंत्र प्रधान कार्यालय क्षेत्र प्रयागराज/ इलाहाबाद न्यायालय ही होगा। प्रधान कार्यालयः 80ए मेंहदौरी, तेलियरगंज, प्रयागराज-211004 (नोटः कानूनी पत्र व्यवहार का पता प्रधान कार्यालय ही होगा।)